केंद्र और राज्य शासन से विज्ञापन के लिए अनुमोदित

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

16 वर्षों से निरंतर....

Website:- www.malwaherald.com

RNI No. MPHIN/2010/33238
dainikmalwaherald@yahoo.com
malwaherald@gmail.com

महाकालेश्वर जी का संध्या काल आरती श्रृंगार दर्शन

मालवा हेराल्ड

सुविचार

जिंदगी उत्तम है यदि आप स्वयं प्रसन्न है तो और यदि आपकी वजह से लोग प्रसन्न है तो जिंदगी सर्वोत्तम है..!!

वर्ष : 16 अंक : 359 | उज्जैन, बुधवार 10 जून 2026 | पृष्ठ-8 | मूल्य-1 रुपए

विकास, तकनीकी नवाचार और किसान कल्याण के लिए 13 हजार 800 करोड़ रूपये की स्वीकृति

अब जिलों में कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, प्रसंस्करण इकाईयों एवं लॉजिस्टिक सुविधाओं को मिलेगा प्रोत्साहन

भोपाल/ दैनिक मालवा हेराल्ड। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में हुई। मंत्रि-परिषद की बैठक में मध्यप्रदेश के बुनियादी ढांचे, तकनीकी विकास और किसान कल्याण से जुड़े कार्यों के लिए लगभग 13 हजार 800 करोड़ रूपये की स्वीकृति के साथ कई बड़े एवं महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुहर लगाई गई है। बैठक में भोपाल मेट्रो रेल परियोजना की संशोधित कुल लागत और अतिरिक्त वित्त पोषण को मिलाकर 13,565.84 करोड़ रूपये की पुनरीक्षित राशि की स्वीकृति दी गई। अब भोपाल शहर के यातायात नेटवर्क को बड़ा विस्तार मिलेगा। इसके साथ ही राज्य में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को सुदृढ़ करने के लिए आगामी 5 वर्षों 2026-2031 के लिए आई.टी. संवर्ग परामर्श सेवाओं और कार्य योजना के लिए 235 करोड़ 63 लाख रूपये स्वीकृत किए गए है।

कृषि और व्यापार जगत को गति देने के लिए मंत्रि-परिषद ने कपास पर मंडी फीस की दर को 1% से घटाकर 0.5% करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जिससे स्थानीय जिनिंग मिलों को मजबूती मिलेगी और रोजगार बढ़ेगा। किसान हित में सामान्य मंडी शुल्क को एक रूपये से बढ़ाकर एक रूपये 50 पैसे किया गया है। शुल्क के रूप में प्राप्त होने वाली 500 करोड़ रूपये की अनुमानित अतिरिक्त आय का उपयोग सीधे किसान सड़क निधि और कृषि अनुसंधान के विकास में किया जाएगा। आगामी रबी और खरीफ विपणन सत्रों में फसलों के सुचारू उपार्जन को सुनिश्चित करने के लिए MPSCSC और मार्कफेड को 8,600 करोड़ रूपये की निःशुल्क शासकीय प्रत्याभूति देने की भी बड़ी मंजूरी दी गई है। यह फैसले प्रदेश की आर्थिक और सामाजिक उन्नति की दिशा में सशक्त कदम साबित होंगे।

भोपाल मेट्रो की पुनरीक्षित लागत और अतिरिक्त वित्त पोषण के लिए 13,565.84 करोड़ रूपये की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने भोपाल मेट्रो रेल परियोजना की मूल लागत 6,941.40 करोड़ में 3,092.22 करोड़ रूपये की अतिरिक्त लागत जोड़कर संशोधित कुल लागत 10,033.62 करोड़ रूपये के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की है। मंत्रि-परिषद ने इसके अतिरिक्त उद्योग के स्वीकृत मानदंडों के अनुसार परियोजना के लिए अतिरिक्त वित्त पोषण के लिए 3,532 करोड़ 22 लाख रूपये की भी स्वीकृति प्रदान की है। इसमें भारत शासन और राज्य शासन द्वारा 995 करोड़ 9 लाख रूपये की अतिरिक्त इक्विटी और केन्द्रीय करों के लिए 84 करोड़ 54 लाख रूपये का अतिरिक्त अधीनस्थ ऋण, वित्तपोषण एजेंसी बैंकों से ऋण निधि के विरुद्ध 1,620 करोड़ 64 लाख रूपये का अतिरिक्त PTA/आंतरिक ऋण, मध्यप्रदेश शासन से भूमि की लागत और पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन के लिए 138 करोड़ 38 लाख रूपये का अतिरिक्त अधीनस्थ ऋण तथा मध्यप्रदेश शासन से राज्य करों के लिए 446 करोड़ 35 लाख रूपये एवं ढ्ढष्ट की लागत के लिए 246 करोड़ 41 लाख रूपये का अतिरिक्त अनुदान शामिल है।

मंत्रि-परिषद ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग अंतर्गत राज्य आई.टी. संवर्ग परामर्श सेवाओं के लिए अनुदान और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य योजना 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक की अवधि तक निरंतर संचालन के लिए 235 करोड़ 63 लाख रूपये की स्वीकृति दी है।

स्वीकृति अनुसार राज्य आई.टी. संवर्ग परामर्श सेवाओं के लिए अनुदान योजना के लिए 180 करोड़ 20 लाख रूपये स्वीकृत किए गए हैं। योजना के अंतर्गत शासन के विभिन्न विभागों, निगमों, प्राधिकरणों एवं परियोजनाओं को तकनीकी परामर्श सेवाएँ प्रदान करने के लिए राज्य स्तरीय आई.टी. संवर्ग का गठन किया गया है। योजना से प्राप्त अनुदान का उपयोग विशेषज्ञों की नियुक्ति, प्रशिक्षण, क्षमता-विकास एवं विभागीय आवश्यकताओं के अनुरूप परामर्श सेवाओं के लिए किया जाता है। यह योजना वर्तमान में शासन की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया की आधारभूत आवश्यकता है तथा भविष्य में कृत्रिम बुद्धिमता (एआई), बिग डाटा एनालिटिक्स, ब्लॉक चेन तकनीक एवं सायबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में राज्य की तैयारियों को सुदृढ़ करने के लिए भी अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी।

न्यूज ब्रीफ

सिंधु जल संधि पर भारत का सख्त रुखः पाकिस्तान को नहीं मिलेगा एक बूंद पानी, केंद्र का बड़ा बयान

नई दिल्ली/ जीएनएस। केंद्र सरकार ने मंगलवार को सिंधु जल संधि को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि आने वाले वर्षों में उसे भारत की ओर से एक बूंद पानी भी नहीं मिलेगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि भारत सरकार सिंधु नदी प्रणाली का पानी पाकिस्तान तक पहुंचने से रोकने के लिए तेजी से काम कर रही है। सीआर पाटिल ने स्पष्ट किया कि 1960 की सिंधु जल संधि को समाप्त नहीं किया गया है, बल्कि फिलहाल स्थगित रखा गया है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले के बाद हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि पाकिस्तान तक पानी न पहुंचे। आने वाले वर्षों में एक बूंद पानी भी वहां नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे की निगरानी केंद्र सरकार के सर्वोच्च स्तर पर की जा रही है। पाटिल ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर गृह मंत्री अमित शाह भी व्यक्तिगत रूप से इस मामले पर नजर रख रहे हैं और तय समयसीमा के भीतर काम आगे बढ़ाया जा रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव पहलगाम आतंकी हमले के बाद और बढ़ गया है। इसके बाद भारत ने इंडस जल संधि को स्थगित रखने का फैसला लिया था। इसी बीच भारत ने संधि के तहत गठित कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की वैधता को भी खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने हाल ही में कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन द्वारा दिए गए %मैक्सिमम पॉन्डेज% फैसले को पूरी तरह अस्वीकार करते हुए कहा कि भारत इस अदालत को अवैध मानता है। उन्होंने कहा, भारत तथाकथित फैसले को पूरी तरह खारिज करता है। इस अवैध रूप से गठित अदालत की किसी भी कार्यवाही, निर्णय या आदेश को भारत मान्यता नहीं देता। भारत लंबे समय से जम्मू-कश्मीर की किशनगंगा और रतले जलविद्युत परियोजनाओं को लेकर पाकिस्तान की आपत्तियों का विरोध करता रहा है। भारत का कहना है कि मध्यस्थता तंत्र संधि के प्रावधानों के अनुरूप नहीं बनाया गया।

बगावत, बिखराव और टकराव... सियासी संकट के बीच सोनिया गांधी ममता के लिए कैसे बनी दीदी

नई दिल्ली/ जीएनएस। नई दिल्ली बंगाल की हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में बगावत-बिखराव के गंभीर संकट के बीच ममता बनर्जी को कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के संबल की खास जरूरत महसूस हो रही है। आईएनडीआइए गठबंधन की एक दिन पहले हुई बैठक में विपक्षी दलों की राजनीति को सजाने-संवारने की पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस को सौंपने की पैरोकारी करने के बाद दूसरे दिन ममता बनर्जी का पांच साल बाद सोनिया गांधी से मिलने के लिए दस जनपथ पर दस्तक देना टीएमसी में आए भूचाल से बढ़ी उनकी बेचैनी का प्रमाण है। इससे यह भी स्पष्ट है कि लोकसभा में टीएमसी के करीब 20 सांसदों के टूट कर भाजपा के साथ जाने की तैयारियों के बीच अपनी राजनीति को बचाने के लिए दीदी कांग्रेस के सियासी ऑक्सीजन का सहारा ले रही हैं। कांग्रेस और टीएमसी दोनों ने बेशक 10 जनपथ पर मंगलवार को सोनिया गांधी के साथ ममता बनर्जी की हुई मुलाकात में हुई चर्चा का ब्यौरा साझा नहीं किया। मगर सूत्रों के मुताबिक दौरान वर्तमान राजनीतिक हालातों में विपक्षी आईएनडीआइए गठबंधन की एकजुटता और मजबूती को लेकर बातचीत तो हुई ही। साथ ही तृणमूल सांसदों के पार्टी छोड़ने के घटनाक्रम से लेकर बंगाल चुनाव में केंद्रीय मशीनरियों के इस्तेमाल तथा चुनाव आयोग की कथित पक्षपाती भूमिका का ममता बनर्जी ने विस्तार से उल्लेख किया। वहीं सत्ता की ताकत से विपक्ष को ध्वस्त करने की भाजपा की तेज होती रफ्तार की बात उठाते हुए यह भी कहा कि आईएनडीआइए को तमाम विषयों पर मिलकर काम करते हुए जनता से जुड़े मुद्दों को उठाना चाहिए।

5300 भारतीय सिम कार्ड से कंबोडिया का गिरोह कर रहा था साइबर ठगी

नई दिल्ली/ जीएनएस। ईडी ने देश में 5,300 सिम कार्ड की खरीद से जुड़े मामले की जांच शुरू कर दी है। इसका उपयोग कंबोडिया में एक मलेशियाई नागरिक के नेतृत्व वाले गिरोह द्वारा पूरे भारत में साइबर धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए किया गया था।

जांच एजेंसी ने पांच जून को लुधियाना के अलावा राजस्थान के किशनगढ़, नागौर और जोधपुर में सात परिसर की तलाशी ली थी। इसी के आधार पर 30 घरेलू बैंक खातों की पहचान हुई। जो इस धोखाधड़ी नेटवर्क का हिस्सा हैं। ईडी ने सोमवार को जारी एक बयान में कहा कि मनी लांड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज किया गया यह मामला जोधपुर पुलिस की उस प्राथमिकी से जुड़ा है, जिसमें कुछ पीओएस (प्वाइंट ऑफ सेल्स) विक्रेताओं के खिलाफ भारतीय सिम को धोखाधड़ी से सक्रिय करने और उन्हें एक मलेशियाई नागरिक को सौंपने का आरोप लगाया गया था।

ईडी के अनुसार कंबोडिया के ठगी गिरोहों से जुड़े कई साइबर अपराध के मामले सामने आए हैं। इनमें डिजिटल अरेस्ट भी शामिल है। इन मामलों में भारतीयों को साइबर अपराध के जरिये फंसाया गया है। ईडी ने बताया कि उसने 2.3 लाख नंबरों (सिम कार्ड) का विश्लेषण किया।

इसमें पता चला कि उनमें से लगभग 36 हजार कंबोडिया में सक्रिय थे, जिनमें से लगभग 5,300 का इस्तेमाल वॉट्सएप काल कर पूरे भारत में सैकड़ों करोड़ रुपये के साइबर धोखाधड़ी करने में किया गया।

एजेंसी के अनुसार, तलाशी के दौरान सामने आया कि राहुल कुमार झा, मोहम्मद शरीफ और संदीप भट्ट ने प्रकाश भील, रामअवतार राठी, हरीश मालाकार और हेमंत पनवार नामक अन्य सिम विक्रेताओं के साथ मिलकर मलेशियाई नागरिक को सैकड़ों सिम कार्ड की आपूर्ति की।

सिम विक्रेताओं के पास एयरटेल, जियो और वोडाफोन इंडिया जैसे दूरसंचार ऑपरेटरों की पीओएस आईडी थी।

कोयला संकट का दौर खत्म, देश के पास 80 दिनों की बिजली का बैकअपः केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी

नई दिल्ली/ जीएनएस। केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी ने कहा है कि 80 दिनों की बिजली उत्पादन जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार के पास प्रचुर मात्रा में कोयले का भंडार है। राजग सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि अर्जेंटीना में अधिग्रहित महत्वपूर्ण खनिज ब्लाक में काम शुरू हो गया है।

उत्पादन जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। पहले कोयले की कमी रहती थी। अब भारत सरकार के पास 80 दिनों तक बिजली उत्पादन के लिए पर्याप्त कोयला भंडार है। मानसून शुरू होने के कारण भारी वर्षा से कोयला उत्पादन में बाधा आ सकती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर हमने 80 दिनों के लिए जरूरी कोयले का भंडारण कर रखा है। रेड्डी ने कहा कि केंद्र सरकार महत्वपूर्ण खनिज भंडारों की पहचान कर रही है।

एआई की दुनिया आईटी अधिनियम के दौर से बहुत अलग, नए कानून की जरूरतः अश्विनी वैष्णव

नई दिल्ली/ जीएनएस। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि एआइ के तेजी से बदलते परिदृश्य को देखते हुए भारत को एक नए कानून की आवश्यकता पड़ सकती है। उन्होंने कहा कि मौजूदा आईटी अधिनियम वर्ष 2000 में लागू किया गया था, जब एआई जैसी तकनीकों का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में नहीं था।

एक साक्षात्कार में वैष्णव ने कहा कि सरकार इस विषय पर उद्योग जगत के साथ लगातार चर्चा कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि एआई के नियमन को लेकर कोई भी निर्णय सोच-समझकर लिया जाएगा, ताकि नवाचार और नागरिकों की सुरक्षा के बीच संतुलन बना रहे। जब उनसे पूछा गया कि क्या भारत एआई के लिए अलग कानून बनाएगा या मौजूदा आईटी अधिनियम में संशोधन करेगा, तो उन्होंने कहा कि यह एक जटिल विषय है।

आईटी अधिनियम के ढांचे के भीतर कुछ कदम उठाए गए हैं, लेकिन एआई की दुनिया उस समय से बिल्कुल अलग है, जब वर्ष 2000 में यह कानून बनाया गया था। इसलिए नए कानून की आवश्यकता महसूस होती है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना है, लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित करना है कि एआइ के दुरुपयोग से लोगों को कोई नुकसान न पहुंचे।

उन्होंने कहा कि उद्योग जगत के साथ विचार-विमर्श के बाद ही आगे की दिशा तय की जाएगी। फरवरी में केंद्र सरकार ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के लिए एआई-जनित और कृत्रिम सामग्री से संबंधित नियमों को और सख्त किया था।

CM बनते ही DK शिवकुमार को फिर झटका

नई दिल्ली/ जीएनएस। कर्नाटक के नए नवेले मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने भले ही लंबी खींचतान के बाद राज्य की कमान अपने हाथ में लेने में कामयाब हो गए हों, लेकिन उनकी मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रहीं।

पहले रामलिंगा रेड्डी ने शपथ लेने के दो दिन बाद इस्तीफा दे दिया और काफी मान-मनौव्वल के बाद उसे वापस लिया। अब मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा भी अपनी शिकायतें लेकर कांग्रेस आलाकमान से मिलने दिल्ली पहुंचे हैं।

मंत्रालय को लेकर विवाद- दरअसल मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा को बेंगलुरु विकास विभाग की जिम्मेदारी मिली है। लेकिन उन्होंने अभी तक अपना पदभार नहीं संभाला है। सूत्र बता रहे हैं कि पेच इस बात पर अटका है कि गौड़ा को ग्रेटर बेंगलुरु डेवलपमेंट विभाग दिया गया है जबकि बेंगलुरु डेवलपमेंट अथॉरिटी और बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी शिवकुमार ने अपने पास रखा है।

दिलचस्प बात ये है कि ये वही विभाग है, जिसे लेकर रामलिंगा रेड्डी नाराज हो गए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें यह विभाग देने का वादा किया गया था, लेकिन बाद में इसे कृष्णा बायरे गौड़ा दे दिया गया और उन्हें सिंचाई मंत्रालय सौंप दिया गया।

अब लगता है कि कृष्णा बायरे गौड़ा भी यह विभाग पाकर खुश नहीं हैं। वह कांग्रेस आलाकमान से मिलने दिल्ली पहुंचे हैं। गौड़ा के अलावा विधायक रिजवान अरशद भी दिल्ली आए हैं। रिजवान शिवकुमार के पक्के समर्थक माने जाते हैं।

वैश्विक शिक्षा का नया दौरः भारत में खुलेंगे तीन विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस

नई दिल्ली/ जीएनएस। ब्रिटेन के दो विश्वविद्यालयों और आस्ट्रेलिया के एक विश्वविद्यालय को भारत में परिसर की स्थापना के लिए केंद्र सरकार ने अनुमति दे दी है। जो विश्वविद्यालय आने वाले दिनों में भारत में अपने शिक्षण परिसर स्थापित करेंगे उनमें ब्रिटेन के ब्रिस्टल विश्वविद्यालय और यार्क विश्वविद्यालय हैं, जबकि आस्ट्रेलिया का न्यू साउथवेल्स विश्वविद्यालय है।

यह जानकारी भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने दी है। शिक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इन विदेशी विद्यालयों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत भारत में परिसर स्थापित करने की अनुमति दी गई है। नीति में भारत को शिक्षा प्राप्ति का वैश्विक केंद्र बनाने की योजना है। ब्रिटेन के दोनों विश्वविद्यालय मुंबई में परिसर स्थापित करेंगे जबकि आस्ट्रेलिया का विश्वविद्यालय बेंगलुरु में अपना परिसर स्थापित करेगा। दोनों विश्वविद्यालयों के प्रबंधन से जुड़े पदाधिकारियों को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के समक्ष उच्च शिक्षा सचिव और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष विनीत जोशी ने स्वीकृति पत्र दिए।

इस अवसर पर ब्रिटेन और आस्ट्रेलिया के भारत स्थित उच्चायोगों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री प्रधान ने कहा, तीनों विश्वविद्यालयों के भारत में स्थापित होने वाले परिसर विश्व में शिक्षा के नए केंद्र बनेंगे, वे भारतीय शिक्षा के महत्व और गुणवत्ता से विश्व को अवगत कराएंगे।

ये विश्वविद्यालय देश के दो महत्वपूर्ण शहरों में स्थापित होंगे। इनमें से बेंगलुरु विश्व के पूर्वी भाग की सिलिकान वैली है। जबकि ब्रिटिश विश्वविद्यालय भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में स्थापित होंगे।

यार्क विश्वविद्यालय का यह ब्रिटेन के बाहर पहला परिसर होगा और उसमें फाइनेंस, कंप्यूटर साइंस, आर्टिफीशियल इंटेलीजेंस, साइबर सिक्युरिटी, बिजनेस, इकनोमिक्स, क्रिएटिव इंडस्ट्रीज और मैनेजमेंट जैसे विषयों की पढ़ाई होगी।

देश की सुरक्षा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

नई दिल्ली/ जीएनएस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जून को संवैधानिक चुनाव पद्धति से चयनित सबसे अधिक कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री हो जायेंगे। मोदी देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का 4398 दिनों का रिकॉर्ड ध्वस्त कर 4399 दिन अपनी देश सेवा के पूर्ण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपने मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री दोनों के कार्यकाल को जोड़कर 25 वर्षों के साथ ही 9007 दिनों की अनवरत राष्ट्र सेवा को भी पूर्ण करेंगे। यह उत्साही ,अविश्रांत, अनथक कर्मयोगी की यात्रा है।

देश के विकास के लिए अनेक कीर्तिमान गढ़ने वाले कठोर निर्णयों के लिए तो 12 वर्षों का उनका कार्यकाल अविस्मरणीय रहेगा ही साथ-साथ देश की सुरक्षा के लिए भी उनके योगदान और भुलाया नहीं जा सकता । राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत का अनुपालन करते हुए उन्होंने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया ।

13 जून 2014 को भारतीय सेना के साउथ ब्लॉक में स्थित रक्षा वॉर रूम में सेना उच्च अधिकारियों के साथ संवाद एवं रक्षा तैयारियों की समीक्षा करने के साथ ही अपनी सुरक्षा के प्रति प्राथमिकता को स्पष्ट कर दिया था । जब समस्त देश दीपावली पर दीपों से अपने-अपने घरों को प्रकाशमान करता है तब प्रधानमंत्री सीमा पर सुरक्षा में तैनात जवानों के बीच में उपस्थित रहकर देश उनके साथ है ऐसा संदेश देते हैं । सियाचिन से प्रारंभ कर 12 वर्षों में 12 स्थानों पर जाकर उन्होंने अपनी सीमा सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता प्रकट की है ।

आचार्य चाणक्य ने राष्ट्र की सुरक्षा के संदर्भ में कहा था कि मजबूत सेना के बिना राष्ट्र सुरक्षित नहीं रह सकता। 1962 में चाइना युद्ध में हमारी पराजय तथा 1964 में चाइना के परमाणु परीक्षण के बाद निर्मित निराशाजनक स्थिति से उबारने के लिए भारत को भी परमाणु शक्ति युक्त होना चाहिए , यह मांग जनसंघ ने 4 दिसम्बर 1964 को पटना अधिवेशन में की थी । तब कांग्रेस सहित समस्त दलों ने इस मांग का उपहास किया था।

वर्ष 1974 के पहले परमाणु परीक्षण के पश्चात जनसंघ के इसी संकल्प की पूर्ति को 11 मई 1998 को प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पोखरण विस्फोट कर पूर्ण किया था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद 2014 रक्षा विभाग का बजट 2.27 लाख की तुलना में 3 गुना 7.85 लाख करोड़ हो गया । आज हम 100 से अधिक देशों को अपने रक्षा उत्पाद बेच रहे हैं ।

मोदी के नाम नया कीर्तिमान, भाजपा करेगी विशेष पूजा-अर्चना और धार्मिक आयोजन

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। भारतीय जनता पार्टी इंदौर नगर की कामकाजी बैठक मंगलवार को नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री Narendra Modi ने भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सेवा देने का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। भाजपा नेताओं के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने 4399 दिनों तक प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए यह उपलब्धि हासिल की है।

बैठक में नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बनाई है। उन्होंने देश की आर्थिक प्रगति, आधारभूत संरचना के विकास, जनकल्याणकारी योजनाओं और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण को सरकार की प्रमुख उपलब्धियां बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक सहित कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं साकार हुई हैं।

प्रधानमंत्री मोदी के दीर्घायु एवं उत्तम स्वास्थ्य की कामना को लेकर भाजपा इंदौर नगर द्वारा बुधवार सुबह खजराना गणेश मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना, आरती और हवन का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद प्रसादी वितरण तथा खजराना अन्नक्षेत्र में जरूरतमंदों को भोजन कराया जाएगा।

बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री के सार्वजनिक जीवन के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों के साथ इंदौर नगर के 35 मंडलों में भी धार्मिक अनुष्ठान, पूजा-पाठ और विशेष प्रार्थना कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन आयोजनों का उद्देश्य प्रधानमंत्री के स्वास्थ्य, दीर्घायु और विकसित भारत के संकल्प की सफलता के लिए प्रार्थना करना है।

बैठक में भाजपा के अनेक पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष एवं अभियान से जुड़े कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नेताओं ने आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा करते हुए अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं और नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित करने का आह्वान किया।

शौर्या दल 22 लाख महिलाओं की देश की सबसे बड़ी साइलेंट आर्मी

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। मध्यप्रदेश के गांवों और शहरों की गलियों से गुज़रते हुए अगर आपको साड़ी का पल्लू संभाले या कॉलेज का बैग टांगे महिलाओं की कोई टोली दिखाई दे, तो उन्हें सिर्फ राहगीर समझने की भूल मत कीजिएगा। यह मध्यप्रदेश की शौर्या दल सेना है–बिना वर्दी के समाज की वो गार्डियन जो आज देश में महिला सशक्तिकरण की सबसे बुलंद हुंकार बन चुकी है ,जिसने महिला सशक्तिकरण की परिभाषा को कागजों से निकालकर धरातल पर साकार कर दिखाया है। वर्ष 2013 में महज़ 6 जिलों से शुरू हुआ यह कारवां आज प्रदेश के कोने-कोने में फैल चुका है, जिसे देखते हुए सरकार ने इसे अगले 5 साल (2026-27 से 2030-31) तक लगातार जारी रखने का महत्वपूर्ण फैसला किया है।

अपराध पर प्री-एंट्री बैन- पुलिस से पहले पहुंचती है यह जाबांज टोली - शौर्या दल की सबसे बड़ी यूएसपी यह है कि ये अपराध होने के बाद मोमबत्तियां नहीं जलातीं, बल्कि अपराध होने से पहले ही उसकी कमर तोड़ देती हैं। किसी घर में घरेलू हिंसा की सुगबुगाहट हो, किसी गांव में गुपचुप बाल विवाह मंडप सज रहा हो, या कोई संदिग्ध मानव तस्करी (ट्रैफिकिंग) का जाल बुन रहा हो–शौर्या दल का खुफिया नेटवर्क तुरंत एक्टिव हो जाता है। 15 से 45 वर्ष की ये जांबाज महिलाएं पुलिस और कानून के हस्तक्षेप से पहले अपनी सामुदायिक समझाइश के ब्रह्मास्त्र से बड़े-बड़े मामलों को शांति से सुलझा देती हैं।

22 लाख से अधिक की साइलेंट आर्मी, जहां किशोरी और गृहणी हैं एक साथ- यह देश का शायद सबसे अनोखा और विशाल सामाजिक नेटवर्क है, जिसमें वर्तमान में 22.52 लाख से अधिक महिलाएं और बेटियाँ सीधे तौर पर जुड़ी हैं। इस दल की खूबसूरती देखिए–एक तरफ जहां 7.64 लाख कॉलेज और स्कूल जाने वाली नई पीढ़ी की लड़कियां अपने तकनीकी और आधुनिक विचारों के साथ इसमें शामिल हैं, वहीं दूसरी तरफ 14.88 लाख अनुभवी गृहणियां और बुजुर्ग महिलाएं हैं, जो समाज की विविधताओं से भलीभाँति परिचित हैं। युवा जोश और अनुभव जब एक मंच पर आता है, तो दकियानूसी सोच और नकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोण को घुटने टेकने ही पड़ते हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग की इस पहल ने सुदूर आदिवासी क्षेत्रों से लेकर शहरी वार्डों तक की महिलाओं को अपनी बंदिशें तोड़कर खुलकर सांस लेने का मौका दिया है।

चार ट्रेनें निरस्त, आठ शार्ट टर्मिनेट और 10 गाड़ियों का बदला मार्ग

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल के इंदौर-देवास-उज्जैन खंड में लक्ष्मीबाई नगर यार्ड के फेज-टू रीमॉडलिंग कार्य के कारण कुछ ट्रेनें निरस्त, शार्ट टर्मिनेट/ओरिजिनेट एवं परिवर्तित मार्ग से चलेगीं। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार के अनुसार इसके कारण कई ट्रेनें प्रभावित रहेंगी।

उज्जैन से चलने वाली ट्रेन उज्जैन-इंदौर पैसेंजर निरस्त रहेगी

इंदौर से चलने वाली ट्रेन इंदौर-उज्जैन पैसेंजर निरस्त रहेगी

उज्जैन से चलने वाली ट्रेन उज्जैन-इंदौर पैसेंजर निरस्त रहेगी

इंदौर से चलने वाली ट्रेन इंदौर-उज्जैन पैसेंजर निरस्त रहेगी

शार्ट टर्मिनेट/शार्ट ओरिजिनेट होने वाली ट्रेनें 11 जून को- रतलाम से चलने वाली ट्रेन रतलाम-डा. अंबेडकर नगर (महू) डेमू लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन पर शार्ट टर्मिनेट होंगी। लक्ष्मीबाई नगर-डा.अंबेडकर नगर के मध्य आंशिक रूप से निरस्त रहेगी।

डा. अंबेडकर नगर से चलने वाली ट्रेन डा. अंबेडकर नगर-रतलाम डेमू, लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन से शार्ट ओरिजिनेट होंगी। डा. अंबेडकर नगर-लक्ष्मीबाई नगर के मध्य आंशिक रूप से निरस्त रहेगी।

रतलाम से चलने वाली ट्रेन रतलाम-डा. अंबेडकर नगर डेमू, लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन पर शार्ट टर्मिनेट होंगी। लक्ष्मीबाई नगर-डा. अंबेडकर नगर के मध्य आंशिक रूप से निरस्त रहेगी। डा. अंबेडकर नगर से चलने वाली ट्रेन डा. अंबेडकर नगर-रतलाम डेमू आदी।

अंतर्राष्ट्रीय समपार जागरूकता दिवस पर रेलवे ने चलाया सुरक्षा अभियान

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल में 7 से 9 जून 2026 तक अंतर्राष्ट्रीय समपार जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। अभियान के तहत समपार फाटकों पर सड़क उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित आवागमन एवं रेल संरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। 9 जून को अंतर्राष्ट्रीय समपार जागरूकता दिवस के अवसर पर विशेष जनजागरूकता गतिविधियां संचालित की गईं।

पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के अनुसार समपार फाटकों पर होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम तथा सड़क उपयोगकर्ताओं में सुरक्षित व्यवहार विकसित करने के उद्देश्य से यह अभियान चलाया गया। रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार मंडल के विभिन्न समपार फाटकों, विद्यालयों, ग्राम पंचायतों और सार्वजनिक स्थलों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

अभियान के दौरान पोस्टर, बैनर, पंपलेट और जनसंपर्क गतिविधियों के माध्यम से लोगों को समपार फाटक पार करते समय बरती जाने वाली सावधानियों की जानकारी दी गई। रेलवे कर्मचारियों एवं नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों ने गांवों में पहुंचकर दोपहिया और चारपहिया वाहन चालकों को रेल सुरक्षा नियमों से अवगत कराया। नुक्कड़ नाटकों और जनजागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से भी लोगों तक संरक्षा संदेश पहुंचाया गया।

अंतर्राष्ट्रीय समपार सुरक्षा जागरूकता दिवस पर रतलाम-गोधरा रेलखंड के समपार क्रमांक 80 तथा बंजली-सेजावता बाइपास स्थित समपार संख्या 190 पर नुक्कड़ नाटकों का मंचन किया गया। इस दौरान सड़क उपयोगकर्ताओं को समपार फाटक पार करते समय बरती जाने वाली सावधानियों, रेलवे सुरक्षा नियमों तथा संभावित दुर्घटनाओं से बचाव के उपायों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में अपर मंडल रेल प्रबंधक (ऑपरेशन) के.एल. मीणा, वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी डी.एम. सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

मंडल रेल प्रबंधक Ashwani Kumar ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि समपार फाटकों पर अधिकांश दुर्घटनाएं मानवीय भूल और असावधानी के कारण होती हैं। उन्होंने लोगों से रेलवे सुरक्षा नियमों का पालन करने, बंद फाटक पार करने का जोखिम नहीं लेने तथा दुर्घटना से देर भली के संदेश को अपनाने का आग्रह किया।

संपत हिल कॉलोनी बनी जल संरक्षण की मिसाल, सात दिन में लगाए 50 से अधिक रिचार्ज संयंत्र

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। जल संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप देने की दिशा में इंदौर की संपत हिल कॉलोनी एक प्रेरणादायक उदाहरण बनकर उभरी है। नगर निगम के जल गंगा संवर्धन अभियान और कैच द रेन अभियान के अंतर्गत कॉलोनी के रहवासियों ने मात्र सात दिनों में 50 से अधिक रिचार्ज संयंत्र स्थापित कर वर्षा जल संचयन और भूजल संवर्धन की दिशा में उल्लेखनीय पहल की है।

महापौर Pushyamitra Bhargav ने मंगलवार को झोन क्रमांक 19 के वार्ड 76 स्थित संपत हिल कॉलोनी का दौरा कर वहां किए गए रेन वाटर हार्वेस्टिंग और भूजल पुनर्भरण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने कॉलोनीवासियों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह मॉडल पूरे शहर के लिए अनुकरणीय है और अन्य रहवासी क्षेत्रों को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए।

निरीक्षण के दौरान महापौर ने बताया कि कॉलोनी के जागरूक नागरिकों ने गिरते भूजल स्तर को सुधारने के उद्देश्य से तेजी से कार्य करते हुए 50 से अधिक रिचार्ज संयंत्र स्थापित किए हैं। इसके साथ ही विभिन्न स्थानों पर रिचार्ज पिटों का निर्माण किया गया है, जिनके माध्यम से वर्षा जल और छतों से एकत्रित पानी को सीधे जमीन में पहुंचाया जाएगा, जिससे भूजल स्तर में सुधार होगा।

महापौर ने कहा कि जल संरक्षण केवल सरकारी योजनाओं तक सीमित विषय नहीं है, बल्कि यह समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। संपत हिल के रहवासियों ने जनभागीदारी के माध्यम से यह साबित किया है कि नागरिकों की सक्रिय भूमिका से बड़े बदलाव संभव हैं। उन्होंने कहा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग और रिचार्ज सॉफ्ट जैसी व्यवस्थाएं भविष्य में जल संकट को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

उन्होंने शहर के नागरिकों, रहवासी संघों, संस्थानों और कॉलोनाइजरों से अपने परिसरों में वर्षा जल संचयन और रिचार्ज पिट निर्माण कराने की अपील करते हुए कहा कि यदि प्रत्येक व्यक्ति वर्षा की हर बूंद को सहेजने का संकल्प ले, तो इंदौर जल संरक्षण के क्षेत्र में भी देश के अग्रणी शहरों में शामिल हो सकता है। कार्यक्रम के दौरान नगर निगम के अधिकारी, रहवासी संघों के प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

सीक्रेट मिडनाइट ऑपरेशन में मनचला गिरफ्तार, महिला सुरक्षा को लेकर इंदौर पुलिस की सख्त कार्रवाई

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और छेड़छाड़ जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से इंदौर पुलिस द्वारा चलाया जा रहा विशेष अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में पुलिस थाना सराफा एवं महिला थाना की संयुक्त टीम ने राजवाड़ा क्षेत्र में स्टिंग ऑपरेशन सीक्रेट मिडनाइट चलाकर एक मनचले को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की।

पुलिस आयुक्त Santosh Kumar Singh के निर्देश पर महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए शहर में विशेष निगरानी अभियान संचालित किया जा रहा है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त Mayank Awasthi तथा पुलिस उपायुक्त Sunil Mehta के मार्गदर्शन में सराफा क्षेत्र में यह कार्रवाई की गई।

जानकारी के अनुसार 7 जून की रात राजवाड़ा क्षेत्र के आसपास महिला पुलिसकर्मियों को सादे वस्त्रों में तैनात किया गया था। ऑपरेशन के दौरान महिला पुलिसकर्मी सामान्य नागरिक बनकर क्षेत्र में घूमती रहीं और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी गई। इसी दौरान कुछ युवकों द्वारा अभद्र टिप्पणियां और फब्तियां कसी गईं, जिस पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एक मनचले को मौके पर ही पकड़ लिया।

पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करते हुए स्पष्ट किया कि महिलाओं की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ भविष्य में भी इसी तरह सख्त कदम उठाए जाएंगे। अधिकारियों ने बताया कि सीक्रेट मिडनाइट अभियान का उद्देश्य महिलाओं के लिए सुरक्षित और भयमुक्त वातावरण सुनिश्चित करना है।

इंदौर पुलिस का कहना है कि शहर में महिला सुरक्षा को लेकर ऐसे विशेष अभियान आगे भी जारी रहेंगे। कार्रवाई में थाना सराफा और महिला थाना की टीम की भूमिका सराहनीय रही।

देवास के शराब ठेकेदार की आत्महत्या के मामले में सीबीआई जांच पर रोक की मांग वाली अपील पर हाई कोर्ट में सुनवाई टली, अब 15 जून को होगी

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। देवास के शराब ठेकेदार आत्महत्या प्रकरण में सीबीआई जांच के आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर सोमवार को होना थी, लेकिन टल गई। अब कोर्ट मामले में 15 जून को सुनवाई करेगी।

शराब ठेकेदार दिनेश मकवाना ने 8 नवंबर 2025 को आत्महत्या की थी। मौत के बाद उनका इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो बहुप्रसारित हुआ था। इसमें उन्होंने तत्कालीन देवास आबकारी उपायुक्त मंदाकिनी दीक्षित पर रिश्वत मांगने और प्रताड़ित करने के आरोप लगाए थे।

मामला सामने आने के बाद शासन ने 24 नवंबर 2025 को मंदाकिनी दीक्षित को निलंबित कर दिया। बाद में मृतक की मां संतोष मकवाना ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दीक्षित के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और निष्पक्ष जांच की मांग की थी।

इस याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 18 अप्रैल को मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने का आदेश दे दिया। एकलपीठ के इस आदेश को चुनौती देते हुए निलंबित आबकारी उपायुक्त मंदाकिनी दीक्षित ने युगलपीठ में अपील दायर की है। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने शासन से कहा था कि वह बताए कि मामला अब तक सीबीआई को सौंपा जा चुका है या नहीं।

जनसुनवाई में 92 शिकायतें पहुंचीं, पुलिस कमिश्नर ने दिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान और प्रभावी निराकरण के उद्देश्य से आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में मंगलवार को बड़ी संख्या में नागरिक अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे। पुलिस कमिश्नर Santosh Kumar Singh ने सभी आवेदकों की समस्याएं गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ सुनीं तथा संबंधित अधिकारियों को त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई के निर्देश दिए।

पुलिस कमिश्नर कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में कुल 92 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें पारिवारिक विवाद, आपसी मतभेद, पैसों के लेन-देन से जुड़े मामले, वित्तीय धोखाधड़ी, प्लॉट और मकान संबंधी विवाद, महिला अपराध तथा पुलिस कार्रवाई से संबंधित शिकायतें प्रमुख रहीं।

जनसुनवाई के दौरान पुलिस कमिश्नर ने कई मामलों में मौके पर ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए, जबकि कुछ प्रकरणों में दूरभाष के माध्यम से संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रत्येक शिकायत का निष्पक्ष और प्रभावी निराकरण पुलिस की प्राथमिकता है, जिससे नागरिकों को समय पर न्याय और राहत मिल सके।

कार्यक्रम में सभी जोनों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने आवेदकों की समस्याओं को विस्तार से सुना और कई मामलों में तत्काल कार्रवाई प्रारंभ कराई। जनसुनवाई में पहुंचे लोगों ने अपनी समस्याओं को सीधे वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष रखने का अवसर मिलने पर संतोष व्यक्त किया।

पुलिस कमिश्नर ने कहा कि इंदौर पुलिस नागरिकों की सुरक्षा, अधिकारों के संरक्षण और न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि पारिवारिक और आपसी विवादों के समाधान के लिए पुलिस द्वारा संचालित मध्यस्थता केंद्रों में लगातार काउंसलिंग की जा रही है, जिससे विवादों का शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण समाधान संभव हो सके। जनसुनवाई में बढ़ती नागरिक भागीदारी को पुलिस प्रशासन के प्रति आमजन के बढ़ते विश्वास का संकेत माना जा रहा है।

गेल इंडिया लिमिटेड ने इंदौर जिले में जिला प्रशासन के सहयोग से ऑफसाइट मॉक ड्रिल का आयोजन किया

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। आपातकालीन प्रतिक्रिया एवं आपदा प्रबंधन योजना के अंतर्गत प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क पर संभावित आपात स्थितियों से निपटने की तैयारियों का परीक्षण करने के उद्देश्य से गेल (इंडिया) लिमिटेड जगोटी इंदौर पीथमपुर पाइपलाइन विभाग ने जिला प्रशासन-इंदौर ,राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और पारस्परिक सहायता भागीदारों के सहयोग से आज सीजीएस इंदौर मे मॉक ड्रिल का आयोजन किया। आपातकालीन प्रतिक्रिया दल ने गैस रिसाव और उसकी रोकथाम, सड़क यातायात नियंत्रण, बचाव और हताहतों को स्वास्थ्य देखभाल केंद्र/अस्पताल में स्थानांतरित करने, आस-पास के क्षेत्र के निवासियों को सुरक्षित निकालने और राहत शिविरों में स्थानांतरित करने आदि को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया, ड्रिल के दौरान सभी टीम के सदस्यो का प्रभावी ढंग से समन्वय किया गया।

गेल (इंडिया) लिमिटेड भारत सरकार का एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जिसके पास प्राकृतिक गैस के गैस प्रसंस्करण संयंत्रों के साथ-साथ तक़रीबन 20,000 किलोमीटर क्रॉस कंट्री प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क है।

पश्चिम इंदौर को मिलेगी सुदृढ़ जलापूर्ति

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। नागरिकों को बेहतर एवं दीर्घकालीन जलापूर्ति की दिशा में कदम बढ़ाते हुए महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने पश्चिम इंदौर क्षेत्र के लिए प्रस्तावित 30 एमएलडी क्षमता के जीएसआर (ग्राउंड सर्विस रिजर्वायर) निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया। इस अवसर पर जल कार्य प्रभारी अभिषेक शर्मा बबलू, स्थानीय नागरिक उपस्थित थे। जल कार्य प्रभारी अभिषेक शर्मा बबलू ने बताया कि पश्चिम इंदौर की बढ़ती जल आवश्यकताओं एवं भविष्य की मांग को देखते हुए यह महत्वपूर्ण परियोजना शुरू की जा रही है। इसके पूरा होने पर रेती मंडी, रंगवासा, प्रगति नगर, ग्रेटर वैशाली, स्कीम-71, केट रोड, बीएसएफ क्षेत्र, चंदन नगर सहित आसपास के क्षेत्रों के नागरिकों को बेहतर, नियमित एवं पर्याप्त जलापूर्ति हो सकेगी।

जल कार्य प्रभारी अभिषेक शर्मा बबलू ने बताया कि निगम की प्राथमिकता है कि प्रत्येक नए विकसित क्षेत्र तक मजबूत एवं आधुनिक जल वितरण व्यवस्था पहुंचाई जाए। इसे देखते हुए आगामी 20-25 वर्षों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जल अधोसंरचना को निरंतर सुदृढ़ किया जा रहा है, जिससे भविष्य में भी नागरिकों को निर्बाध जलापूर्ति सुनिश्चित की जा सके। कार्यक्रम में पार्षद ओपी आर्य, योगेश गेदर, जीतू राठौर सहित बड़ी संख्या में क्षेत्र के रहवासी उपस्थित थे।

इंदौर जिले में मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने की कार्यवाही तेजी से जारी

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। इंदौर जिले में नगरीय निकायों और पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन की प्रक्रिया लगातार जारी है। इसी सिलसिले में जिले में अब तक नगरीय निकायों एवं पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए 2627 आवेदन प्राप्त हुए है। मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए अंतिम तिथि 15 जून है।

यह जानकारी आज यहां सम्पन्न हुई स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में दी गई। बैठक में सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अजीत श्रीवास्तव सहित अन्य संबंधित अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद थे। बैठक में उपस्थित सदस्यों को मतदाता सूची के पुनरीक्षण के संबंध में चल रही प्रक्रिया की जानकारी दी। बताया गया कि पुनरीक्षण का कार्य 15 जून तक चलेगा। इस दौरान कोई भी नागरिक अपना नाम नगरीय निकायों और पंचायतों की फोटो युक्त मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। साथ ही नाम हटाने और संशोधन के लिए आवेदन दिया जा सकता है। बताया गया कि नगरीय निकायों के लिए अभी तक नाम जोड़ने के लिए 558 तथा पंचायतों के लिए 755 नाम हटाने के लिए नगरीय निकायों में 215 और पंचायतों में 986 तथा संशोधन के लिए नगरीय निकायों में 63 और पंचायतों में कुल 50 आवेदन प्राप्त हुए है। बताया गया कि मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों एवं पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण-2026 के लिए संशोधित कार्यक्रम जारी किया गया है।

इंदौर पुलिस ने लौटाई दिल्ली के व्यापारी की मुस्कान, दो घंटे में ढूंढ निकाला तीन लाख रुपये से भरा बैग

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। इंदौर पुलिस की त्वरित कार्रवाई और सतर्कता ने दिल्ली से आए एक व्यापारी की बड़ी चिंता दूर कर दी। थाना रावजी बाजार पुलिस ने आधुनिक तकनीक और सीसीटीवी फुटेज की मदद से महज दो घंटे के भीतर करीब तीन लाख रुपये और महत्वपूर्ण दस्तावेजों से भरा गुम बैग तलाश कर उसके मालिक को सुरक्षित वापस सौंप दिया।

जानकारी के अनुसार दिल्ली निवासी सेनेटरी व्यापारी राहुल मित्तल व्यापारिक भुगतान संग्रह करने के लिए इंदौर आए थे। सियागंज क्षेत्र से विभिन्न व्यापारियों से भुगतान लेने के बाद वे ई-रिक्शा से सिंधी कॉलोनी की ओर जा रहे थे। इस दौरान उनका बैग रास्ते में कहीं गिर गया, जिसकी जानकारी उन्हें गंतव्य पर पहुंचने के बाद हुई। बैग में लगभग तीन लाख रुपये नकद और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे हुए थे।

बैग गुम होने की सूचना मिलते ही थाना रावजी बाजार पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू की। थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने व्यापारी द्वारा बताए गए मार्ग के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और तकनीकी सहायता से बैग की तलाश शुरू की। लगातार प्रयासों के बाद पुलिस ने कुछ ही घंटों में बैग को खोज निकाला और उसमें रखी पूरी नकद राशि तथा दस्तावेज सुरक्षित हालत में व्यापारी को वापस सौंप दिए।

पौधे पचास नहीं पांच लगाओ, लेकिन उनको पल्लवित करने की जिम्मेदारी उठाओ

नेशनल मीडिया फाउंडेशन का 55 वा राज्य स्तरीय सेमिनार एवं सम्मान समारोह का आयोजन ग्वालियर में संपन्न

मंदसौर/ भारतसिंह तोमर/ दैनिक मालवा हेराल्ड। नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष में 55वां राज्य स्तरीय सेमिनार एवं सम्मान समारोह का आयोजन मध्यप्रदेश के ग्वालियर में चैंबर आफ कॉमर्स सभागार में आयोजित किया गया। जिसमें प्रदेशभर के 250 से अधिक पर्यावरणविद, समाजसेवी,एवं पत्रकारों को शील्ड एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।

समारोह ग्वालियर की पूर्व महापौर एवं मध्यप्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष समीक्षा गुप्ता के मुख्य आतिथ्य में सम्पन्न हुआ। अध्यक्षता नेशनल मीडिया फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र जैन ने की। विशेष अतिथि के रूप में देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले श्री तात्या टोपे के वंशज सुभाष टोपे, नेशनल मीडिया फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र अग्रवाल, राष्ट्रीय संगठन महासचिव आरबी सिंह, राष्ट्रीय सचिव राजेन्द्र सिंह जयपुर मंचासीन थे। समारोह की मुख्य अतिथि समीक्षा गुप्ता ने कहा कि पर्यावरण की रक्षा करना हम सबका दायित्व है। आजकल देखने में आता है कि एक पौधा रोपा जाता है और उस पौधे को रोपने में 20 हाथ नजर आते हैं लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए ,उसे पल्लवित करने के लिए कोई हाथ सामने नहीं आता है। आपने कहा कि पौधे 50 नहीं पांच लगाओ लेकिन उसकी सुरक्षा जरूर करो। पौधे लगाने वाले अपना दायित्व समझते हुए 5 वर्ष तक पौधे की देखरेख करेगे तो निश्चित रूप से वह पौधा बड़ा होकर वटवृक्ष बन जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष में नेशनल मीडिया फाउंडेशन द्वारा पूरे देश में पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले पर्यावरणविद, समाजसेवी एवं पत्रकारों का सम्मान करने का जो बीड़ा उठा रखा है वास्तव में वह प्रशंसनीय है। जब एक व्यक्ति का मंच के माध्यम से सम्मान होता है तो हजारों लोगों को प्रेरणा मिलती है नेशनल मीडिया फाउंडेशन आमजन को पर्यावरण के लिए प्रेरणा देने का कार्य मध्य प्रदेश में कर रहा है। ऐसे संगठनों से अन्य संगठन को भी प्रणा लेना चाहिए। समारोह की अध्यक्षता करते हुए नेशनल मीडिया फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र जैन ने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस पर लगातार 55 वर्षों से मध्यप्रदेश में सेमिनार एवं सम्मान करने वाला एकमात्र संगठन नेशनल मीडिया फाउंडेशन है। संगठन के माध्यम से पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए ही मध्य प्रदेश स्तर का सम्मान समारोह का आयोजन किया जाता है जिससे प्रदेश में अच्छे कार्य करने वालों को प्रेरणा मिलती है। श्री जैन ने कहा कि देश का एकमात्र ऐसा संगठन नेशनल मीडिया फाउंडेशन है जो पत्रकारों के हितों के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है पत्रकार सुरक्षा कानून बनाए जाने के लिए भी संपूर्ण भारत में प्रयासरत हैं। समय-समय पर नेशनल मीडिया फाउंडेशन के माध्यम से अनेक आयोजन किए जाते हैं लेकिन वर्ष भर में दो बड़े आयोजन प्रतिवर्ष किए जाते है 29 जनवरी को पत्रकारिता दिवस देश के किसी भी स्थान पर राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और 5 जून पर्यावरण दिवस के उपलक्ष में मध्य प्रदेश में बड़े स्तर का आयोजन किया जाता है जिसमें पर्यावरण, समाजसेवा एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों का सम्मान किया जाता है।

समारोह के विशेष अतिथि श्री सुभाष टोपे ने कहा कि आजादी की लड़ाई में जिन परिवारों ने बड़ा योगदान दिया है उन परिवारों के वंशजों को हमेशा याद रखना चाहिए। उन्हीं की वजह से आज भारत देश में लोकतंत्र स्थापित हुआ है। नेशनल मीडिया फाउंडेशन ने पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों का सम्मान करने का जो बीड़ा उठाया है वह अच्छे कार्य करने वालों का हौसला बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहा है। नेशनल मीडिया फाउंडेशन मध्यप्रदेश के अध्यक्ष नरेंद्र अग्रवाल ने कहा कि पर्यावरण के क्षेत्र में हम सबको बहुत कार्य करने की आवश्यकता है। पेड़ है तो हम हैं यह बात कोरोना काल में साबित हो चुकी है कि ऑक्सीजन की मनुष्य के जीवन में कितनी आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में यदि सभी व्यक्ति मात्र एक-एक पेड़ लगाते हुए उनकी रक्षा करने हेतु जुट जाएगा तो देश में देश में कभी भी ऑक्सीजन की कमी नहीं रहेगी।

श्री अग्रवाल ने कहा कि नेशनल मीडिया फाउंडेशन के माध्यम से 55 वा राष्ट्रीय सेमिनार एवं सम्मान समारोह का आयोजन ग्वालियर की माटी पर संपन्न हुआ है। प्रदेश भर के 250 से अधिक पर्यावरणविद एवं समाज सेवी एवं पत्रकारों का एक साथ सम्मान होना गौरव का क्षण है द्य अतिशीघ्र मंदसौर जिले में भी पर्यावरण एवं समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले वालों का संगठन के माध्यम से सम्मान किया जाएगा। आरंभ में अतिथियों ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया। अतिथियों का स्वागत ग्वालियर इकाई की टीम ने किया। अतिथियों एवं बाहर से कार्यक्रम में उपस्थित हुए सम्मानित बंधुओं को मंदसौर की पहचान भगवान पशुपतिनाथ की तस्वीर प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र अग्रवाल ने भेंट करते हुए मंदसौर आने का आमन्त्रण दिया। कार्यक्रम का संचालन सूरज पाठक ने किया।

हर मंगलवार, लोगों की आवाज़ सुनने खुद बैठती हैं एसडीएम प्रीति संघवी

नीमच/ सतीश सैन/ दैनिक मालवा हेराल्ड। आमजन की छोटी-बड़ी समस्याओं का समाधान अब उनके द्वार पर हो रहा है। नीमच कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के निर्देश पर जावद में हर मंगलवार को लगने वाली जनसुनवाई ने लोगों को बड़ी राहत दी है। इस जनसुनवाई की कमान संभाल रहीं एसडीएम प्रीति संघवी खुद फरियादियों से मिलकर उनकी बात सुन रही हैं और मौके पर ही अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दे रही हैं।

प्रशासन का बदला अंदाज़ - पहले जहां शिकायत लेकर लोग दफ्तरों के चक्कर काटते थे, अब जावद में हर मंगलवार को एसडीएम का दरबार लगता है। जमीन विवाद, पेंशन, राशन, बिजली-पानी और अन्य जनसुविधाओं से जुड़ी शिकायतें सीधे एसडीएम के सामने रखी जाती हैं। सबसे बड़ी बात ये कि समस्याओं को सुनकर टालने की बजाय उसी समय निपटारे की कोशिश होती है।

एसडीएम प्रीति संघवी की संवेदनशील और तत्पर कार्यशैली आमजन के बीच चर्चा का विषय बन गई है। उनकी पहल से न सिर्फ शिकायतों का त्वरित निपटारा हो रहा है, बल्कि प्रशासन और जनता के बीच भरोसे का पुल भी मजबूत हो रहा है। फील्ड में उतरकर लोगों की बात सुनना और समस्या को जड़ से समझकर समाधान करना - यही वजह है कि जनसुनवाई में लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसी व्यवस्था से प्रशासन के प्रति भरोसा बढ़ा है और छोटे कामों के लिए अब भटकना नहीं पड़ता।

पूर्व विधायक सिसौदिया ने सीवरेज परियोजना की प्रगति, तकनीकी व्यवस्थाओं एवं भविष्य की कार्ययोजना पर चर्चा कर किया मंथन

मंदसौर/ भारतसिंह तोमर/ दैनिक मालवा हेराल्ड। पूर्व विधायक एवं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता यशपाल सिंह सिसौदिया ने मंदसौर शहर में भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन की संयुक्त सहभागिता से लगभग 171 करोड़ रुपये की लागत से संचालित सीवरेज परियोजना के निर्माण कार्यों पर चर्चा की। इस दौरान नगर पालिका के अधिकारियों तथा निर्माण एजेंसी पीसी स्नेहल इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी, अहमदाबाद के तकनीकी विशेषज्ञों के साथ परियोजना की प्रगति, तकनीकी व्यवस्थाओं एवं भविष्य की कार्ययोजना पर विस्तार से मंथन किया गया। श्री सिसौदिया ने बताया कि शहर में सीवरेज व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए 6 इंटरमीडिएट पंपिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, जो आधुनिक तकनीक एवं पक्के स्ट्रक्चर के साथ निर्मित होंगे। इन स्टेशनों के माध्यम से सीवरेज जल को पाइपलाइन द्वारा अलावदाखेड़ी-शिवना क्षेत्र तक पहुंचाया जाएगा, जहां एक मुख्य पंप हाउस का निर्माण किया जाएगा। श्री सिसौदिया ने बताया कि गांधीनगर, यशनगर एवं मेघदूत नगर क्षेत्र का आई.पी.एस. लगभग 1.1 एमएलडी क्षमता का होगा, जिसका निर्माण केशव कुंज के पीछे सर्वे नंबर 315 स्थित ऑडिटोरियम के समीप किया जाएगा। यहां से 150 मिमी से 300 मिमी व्यास की पाइपलाइन के माध्यम से सीवरेज जल का प्रवाह किया जाएगा। इसके बाद विभिन्न जोनल प्वाइंट्स से यह जल ग्रेविटी सिस्टम के माध्यम से अलावदाखेड़ी तक पहुंचेगा। श्री सिसौदिया ने बताया कि शहर में कुल छह स्थानों पर आई.पी.एस. स्थापित किए जाएंगे। बैठक में अधिकारियों एवं निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधियों ने आश्वस्त किया कि परियोजना के पूर्ण होने के बाद आगामी 10 वर्षों तक इसके रखरखाव एवं संचालन की जिम्मेदारी निर्माण एजेंसी द्वारा ही निभाई जाएगी। श्री सिसौदिया ने कहा कि यह परियोजना मंदसौर शहर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिससे भविष्य में स्वच्छता व्यवस्था और पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिलेगी तथा नागरिकों को आधुनिक सीवरेज सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखने और कार्य को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने की बात भी कही।

5 करोड़ मूल्य की शासकीय भूमि अतिक्रमण मुक्त, जिला प्रशासन की बड़ी कार्यवाही

मंदसौर/ भारतसिंह तोमर/ दैनिक मालवा हेराल्ड। कलेक्टर अदिती गर्ग के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन द्वारा शासकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए तहसील गरोठ के ग्राम कुरलासी में लगभग 5 करोड़ रुपये बाजार मूल्य की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गरोठ राहुल चौहान ने बताया कि ग्राम कुरलासी में उद्योग विभाग को आवंटित शासकीय भूमि, सर्वे क्रमांक 888 एवं 889, कुल रकबा 6.16 हेक्टेयर पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई। उक्त भूमि का अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 5 करोड़ रुपये है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई राजस्व एवं पुलिस विभाग के संयुक्त दल द्वारा शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित रूप से की गई। प्रशासन की इस कार्रवाई से शासकीय भूमि को सुरक्षित कर उसके नियोजित उपयोग का मार्ग प्रशस्त हुआ है। कार्यवाही के दौरान तहसीलदार अर्जुन भदौरिया, नायब तहसीलदार श्री निगम, रघुनाथ मचार तथा पुलिस विभाग से थाना प्रभारी बलवीर यादव सहित संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

मंदसौर सहित दुनिया के लाखों हज तीर्थयात्री 45 दिन हज यात्रा कर लौटे अपने वतन हिंदुस्तान

तवाफ ए विदा कर नम आंखों से लौटे हाजी, बार बार हो अल्लाह के घर के दीदार रही दिली ख्वाहिश

मंदसौर/ भारतसिंह तोमर/ दैनिक मालवा हेराल्ड। मक्का मदीना शरीफ के मुकद्दस सफर हज की पवित्र यात्रा कर समाजसेवी नाहरु खां मेव एवं उनकी पत्नी आमना बी मेव सहित सात समंदर पार मक्का मदीना शरीफ की जियारत कर वतन हिंदुस्तान और घर, परिवार के लिए अमन, चैन, खुशहाली, सुख, समृद्धि के साथ दुनिया में शक्तिशाली देश बनने की प्रार्थना की। हज यात्रा के दौरान मंदसौर के हज यात्रियों के साथ साथ मक्का मदीना शरीफ के मीना, अराफात, मुजदलफा, जमरात से हर अरकान पूरे कर मक्का लौटे है।

मंदसौर जिला हज कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट शाहिद निजामी ने बताया कि हज इस्लाम के पांच स्तंभों में से एक है, सक्षम मुस्लिम को एक बार हज करना फर्ज है, इस्लामी वर्ष के 12 वे महीने में होने वाला हज दुनिया के सबसे बड़े सामूहिक धार्मिक आयोजनों में से एक है। मीना में 5 दिन किए हज के आयोजन हाजी नाहरु खां मेव ने बताया कि मक्का मदीना शरीफ में हज के मुकद्दस 5 दिन जिसमें हाजी मीना में रुककर, अराफात के मैदान में प्रार्थना, मुजदलफा में रात रुककर कंकरी इकट्ठा करना, जमरात में तीनों शैतान को कंकरी मारना, हरम शरीफ काबा परिक्रमा करना सहित सफा मरवा पहाड़ियों के बीच दौड़ना सहित कई अनुष्ठान किए। हाजी नाहरु मेव ने बताया कि गुंबद ए खिजरा व अस्ताना ए महबूब से इश्क व मुहब्बत को लेकर हज पर आने वाले हाजियों द्वारा मक्का व मदीना शरीफ में बेजुबान पक्षी में बेजुबान पक्षी कबूतरों को दाना डालते है जो अपने वतन से साथ लेकर आते है। इस अवसर पर समाजसेवी एवं वरिष्ठ जन परिवारजन उपस्थित रहे यह जानकारी जिला हज कमेटी के सेक्रेटरी सरवर खान ने दी। (13 जिल हिज्जा) को 'तवाफ अल-वदा' (अलविदा तवाफ) की अदायगी के साथ हो रहा है। पवित्र अनुष्ठान पूरे कर मक्का स्थित अपने आवास पर लौट रहे हाजी। हाजियों की वापसी से जुड़ी मुख्य बातें

तवाफ-ए-जियारत और रमीः शैतान को कंकरी मारने (रमी) और काबा में अनिवार्य परिक्रमा (तवाफ-ए-जियारत) के बाद हाजी अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। अलविदा तवाफः मीना से मक्का लौटने के बाद, स्वदेश या अपने गंतव्य के लिए निकलने से पहले हाजी काबा का अंतिम चक्कर (तवाफ अल-वदा) लगाते हैं। सम्मानः मक्का में इस यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले तीर्थयात्रियों को समुदाय में 'हाजी' (पुरुष) और 'हज्जा' (महिला) के रूप में सम्मान दिया जाता है।

औद्योगिक क्षेत्र जग्गाखेड़ी में बैंक, होटल, वेयर हाउस और अन्य सुविधाओं के विकास का खुला रास्ता, कमर्शियल प्लॉट्स की ई-बिडिंग शुरू

5900 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों के बीच व्यापारिक सुविधाओं के विस्तार की तैयारी

मंदसौर/ भारतसिंह तोमर/ दैनिक मालवा हेराल्ड। एमपीआईडीसी के कार्यकारी संचालक राजेश राठौड़ द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने और रोजगार के नए अवसर तैयार करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। इसका असर अब अलग-अलग जिलों में भी दिखाई देने लगा है। मंदसौर जिले के जग्गाखेड़ी औद्योगिक क्षेत्र में भी इसी दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है। एमपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एमपीआईडीसी) ने यहां कमर्शियल भूखंडों की ई-बिडिंग प्रक्रिया शुरू की है। क्योंकि सरकार का उद्देश्य सिर्फ उद्योगों के लिए जमीन उपलब्ध कराना नहीं है, बल्कि ऐसा माहौल तैयार करना है जहां उद्योगों के साथ व्यापार और सेवाओं से जुड़ी गतिविधियां भी बढ़ें। इससे क्षेत्र में नए कारोबार शुरू होने के अवसर बनेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा और औद्योगिक विकास को और मजबूती मिलेगी।

प्रदेश सरकार की मंशा केवल औद्योगिक क्षेत्रों में फैक्ट्रियां स्थापित करवाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ऐसे औद्योगिक केंद्र विकसित करने की है, जहां उद्योगों के साथ-साथ उनसे जुड़ी सभी जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध हों। इसी सोच के तहत जग्गाखेड़ी औद्योगिक क्षेत्र में कमर्शियल भूखंडों की ई-बिडिंग शुरू की गई है। इन भूखंडों पर बैंक, होटल, रेस्टोरेंट, ऑफिस, ट्रांसपोर्ट कंपनियां, वेयरहाउस, ऑटोमोबाइल सर्विस सेंटर, शोरूम और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान विकसित हो सकेंगे। इससे यहां काम करने वाले उद्योगों, कर्मचारियों और निवेशकों को रोजमर्रा की कई सुविधाएं एक ही क्षेत्र में मिल सकेंगी। पिछले कुछ वर्षों में जग्गाखेड़ी औद्योगिक क्षेत्र में निवेशकों की रुचि लगातार बढ़ी है। फेज-1 में कई इकाइयां संचालित हो रही हैं, जबकि फेज-2 में बड़े निवेश प्रस्तावों पर काम आगे बढ़ रहा है। ऐसे में उद्योगों की संख्या बढ़ने के साथ बैंकिंग, परिवहन, भंडारण, खानपान और अन्य सेवाओं की मांग भी स्वाभाविक रूप से बढ़ रही है। इसी की पूर्ति के लिए कमर्शियल भूखंडों का विकास किया गया है। इनकी बिडिंग के बाद व्यवसायिक गतिविधियां शुरू हो सकेंगी और उद्योगों को आवश्यक सेवाएं स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सकेगी। इससे जग्गाखेड़ी फेज-2 में निवेश के अवसर भी बढ़ेंगे।

औद्योगिक मैप पर तेजी से उभर रहा मंदसौर- मंदसौर पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बदल रहा है। कृषि प्रधान जिले के रूप में पहचान रखने वाला यह क्षेत्र अब उद्योगों और नए निवेश के लिए भी ध्यान खींच रहा है। जिले में विकसित, विकासाधीन और प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रों में अब तक 5900 करोड़ रुपये से अधिक निवेश अनुमानित है। जिनसे 15 हजार से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। बड़ी संख्या में अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी तैयार होंगे। यही वजह है कि नए उद्योगों के साथ-साथ उनसे जुड़ी सुविधाओं के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस बदलाव के केंद्र में जग्गाखेड़ी औद्योगिक क्षेत्र है। फूड पार्क जग्गाखेड़ी फेज-1 में 136 औद्योगिक प्लॉट हैं। यहां 78 फैक्टरियां शुरू हो चुकी हैं। इससे करीब सात सौ लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार हासिल हो रहा है।

जग्गाखेड़ी फेज-2 निवेशकों के लिए 219 प्लॉट- जग्गाखेड़ी फेज-2 निवेशकों के लिए आकर्षण का नया केंद्र बनकर उभरा है। यहां 219 प्लॉट हैं और करीब 1200 करोड़ रुपये के निवेश से 4500 से अधिक रोजगार सृजित होने की संभावना है। बेहतर आधारभूत सुविधाओं के चलते यहां नए उद्योगों की स्थापना के लिए अनुकूल माहौल बन रहा है, जिससे मंदसौर की पहचान एक उभरते औद्योगिक केंद्र के रूप में और मजबूत हो रही है। एमपीआईडीसी के कार्यकारी संचालक श्री राजेश राठौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में उद्योगों और निवेश को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जग्गाखेड़ी औद्योगिक क्षेत्र में कमर्शियल भूखंडों की ई-बिडिंग इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे स्थानीय उद्यमियों को नए अवसर मिलेंगे, व्यापारिक सुविधाओं का विस्तार होगा और क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। जग्गाखेड़ी मंदसौर में बढ़ रही औद्योगिक गतिविधियों के साथ यह पहल क्षेत्र के संतुलित और समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

जीर्ण-शीर्ण भवनों के खिलाफ न.पा. की कार्यवाही- नगरपालिका ने तीन जीर्ण शीर्ण भवनों को किया जमींदोज

नीमच/ सतीश सैन/ दैनिक मालवा हेराल्ड। शासन के निर्देशानुसार एवं जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में नगरपालिका परिषद नीमच द्वारा मंगलवार को जीर्णशीर्ण भवनों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही करते हुए तीन जीर्णशीर्ण भवनों को जमीदोज किया गया।

सीएमओ श्रीमती दुर्गा बामनिया ने बताया, कि मंगलवार 9 जून को नगरपालिका की टीम द्वारा जनसुरक्षा के मद्देनजर नीमच सिटी के कालिदास मार्ग (जूना बाजार), पर जीर्णशीर्ण भवन, पूरनगंज में आर्य समाज का जीर्णशीर्ण भवन तथा ठक्कर बप्पा गंज में जीर्णशीर्ण भवन के खतरनाक हिस्से को जेसीबी व अन?य उपकरणों के माध?यम से जमीदोज किया गया। मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्रीमती दुर्गा बामनिया ने बताया, कि नगरपालिका नीमच द्वारा जीर्णशीर्ण भवनों से संभावित दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नीमच शहर में सर्वे करवा कर 12 खतरनाक एवं जीर्णशीर्ण भवनों को चिन्हित कर, भवन स्वामियों को नोटिस जारी कर संभावित दुर्घटना वाले जीर्णशीर्ण भवन को गिरवाने हेतु सूचित किया गया था। किन्तु निर्धारित अवधि में भवन स्वामी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने पर, नगरपालिका नीमच द्वारा उक्त कार्रवाई की गई है।

इस कार्यवाही के दौरान नगरपालिका के प्रभारी राजस्व अधिकारी श्री टेकचंद बुनकर, श्री महावीर जैन, श्री हेमंत सिसोदिया,श्री महेंद्र साहू, श्री अब्दुल हमीद, रवि भंडारी पूरे अमले के साथ मौजूद थे।

नवीन सीएमओ ने संभाला सिंगोली न प का कार्यभार

सिंगोली/ सतीश सैन/ दैनिक मालवा हेराल्ड। नव पदस्थ मुख्य नगर परिषद अधिकारी रामचंद्र शिंदल ने मंगलवार दोपहर में पदभार ग्रहण कर अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। उन्हें पूर्व प्रभारी सीएमओ कपिल सिंह राजावत ने पदभार सौंपा ओर पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने नगर के समग्र विकास, स्वच्छता व्यवस्था में सुधार तथा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम नागरिकों तक पहुंचाने को अपनी पहली प्राथमिकता बताया।

नवागत सीएमओ ने कहा कि नगर परिषद की सभी योजनाओं और विकास कार्यों को पारदर्शिता एवं समयबद्ध तरीके से संचालित किया जाएगा। आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जाएगा तथा नगर में स्वच्छता, पेयजल, सड़क और प्रकाश व्यवस्था जैसी मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। साथ ही बकाया कर को समय पर जमा करवाने का प्रयास ओर जनहित के मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा,,उन्होंने नगरवासियों से भी सहयोग की अपील करते हुए कहा कि स्वच्छ, सुंदर और विकसित सिंगोली के निर्माण में जनभागीदारी महत्वपूर्ण है। नगर परिषद की टीम के साथ मिलकर नगर के विकास के लिए सकारात्मक कार्य किए जाएंगे।नगर परिषद के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने नवागत सीएमओ का स्वागत किया तथा उन्हें सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दीं। नगरवासियों को भी नए सीएमओ से नगर के विकास और जनसमस्याओं के समाधान को लेकर काफी उम्मीदें हैं।

उर्वरक की सोसायटी में उपलब्धता एवं वितरण सुनिश्चित करें- श्री चंद्रा

नीमच/ सतीश सैन/ दैनिक मालवा हेराल्ड। जिले की सभी सोसायटी के गोदामों में डबल लाक केंद्रों से पर्याप्त उर्वरक का भण्डारण हो। सोसायटी में नियमित रूप से उर्वरक का अग्रिम भण्डारण एवं किसानों को उर्वरक का वितरण सुनिश्चित किया जाए। यह निर्देश कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने मंगलवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष नीमच में समय सीमा पत्रों के निराकरण की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में कृषि, सहकारिता एवं विपणन संघ अधिकारियों को दिए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री अमन वैष्णव, एडीएम श्री बी.एस.कलेश, सभी एसडीएम एवं जिला अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में कलेक्टर ने तीनों एसडीएम को उर्वरक की उपलब्धता, वितरण व्यवस्था पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होने कहा, कि किसी भी सोसायटी में उर्वरक की कमी ना रहे। अग्रीम भण्डारण किया जाए। बैठक में बताया, कि यूरिया की आधी रैंक और एनपीके की आधी रैंक एक दो दिन में लग रही है। नीमच पर्याप्त मात्रा में डलब लाक केंद्रों में उर्वरक उपलब्ध है।

बैठक में कलेक्टर ने सभी निर्माण विभागों के जिला अधिकारियों को निर्देश दिए, कि वे सड़क निर्माण के प्रगतिरत कार्य स्थल पर सड़क सुरक्षा के मानकों के अनुरूप साईनेज, रिफ्लेक्टर एवं बेरियर संकेतक आदि अनिवार्य रूप से लगवाना सुनिश्चित करें। यदि किसी प्रगतिरत कार्य पर सड़क सुरक्षा संबंधित साईनेज, संकेतक, बोर्ड नही पाए जाएंगे, तो संबंधित जिला अधिकारी, निर्माण एजेंसी की जवाबदेही तय की जावेगी।

कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने फायरसेफ्टी के मद्देनजर जिला अस्पताल, सीएचसी व बडे प्रायवेट अस्पतालों में भी फायर सेफ्टी उपकरणों को परखने के लिए फायर सेफ्टी मॉकड्रील करवाने के निर्देश मुख्य चिकित्सा अधिकारी नीमच को दिए है। कलेक्टर ने जिला अस्पताल नीमच में प्रसूति एवं बच्चों के वार्ड में सुरक्षा के लिए दो अतिरिक्त होमगार्ड जवान तैनात करने तथा जिला अस्पताल में ड्यूटी चिकित्सकों व पैरामेडीकल स्टाफ की नामजद ड्यूटी का चार्ज भी बडी एलईडी पर प्रदर्शित करवाने के निर्देश दिए।

दिवस के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए ऑनलाइन योग सत्र में जुड़ें

नीमच/ सतीश सैन/ दैनिक मालवा हेराल्ड। भारत सरकार, आयुष मंत्रालय, नई दिल्ली के निर्देशानुसार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के तहत समग्र स्वास्थ्य, कल्याण और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रव्यापी गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है।

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रयास- आयुष मंत्रालय द्वारा के सहयोग से 14 जून 2026 को प्रातः 6-15 बजे से 7-35 बजे तक एक ऐतिहासिक ऑनलाइन योग सत्र का आयोजन किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य आयुष मंत्रालय के YouTube Platform के माध्यम से एक साथ अधिकतम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। पंजीकरण प्रक्रिया- इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रतिभागियों को टोल-फ्री नंबर 1800-315-7008 पर मिस्ड कॉल देकर पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण के बाद प्रतिभागियों को सत्र का लिंक वाला WhatsApp message प्राप्त होगा। महत्वपूर्ण निर्देश- गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के प्रयास वाले दिन प्रत्येक प्रतिभागी को अपने-अपने डिवाइस से व्यक्तिगत रूप से लॉग-इन करना होगा, क्योंकि सत्र में शामिल होने वाले प्रत्येक registered डिवाइस को आधिकारिक रिकॉर्ड में गिना जाएगा। एक डिवाइस पर समूह में योग करने से केवल एक ही गिनती होगी।

अपील- कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने सभी जनप्रतिनिधिगण, अधिकारी-कर्मचारियों, संबद्ध संस्थानों, संगठनों, योग अभ्यासकर्ताओं और आम जनता से अपील की है कि वे अपने-अपने व्यक्तिगत उपकरणों- मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट के माध्यम से अलग-अलग जुड़कर इस ऐतिहासिक पहल में सक्रिय भागीदारी करें और जिले से अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित कराएं।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वैश्विक आंदोलन के रूप में उभरा है। इस सामूहिक प्रयास को सफल बनाने के लिए सभी की भागीदारी आवश्यक है।

सम्पादकीय

चीन उत्तर कोरिया और रसिया के बीच नए समीकरण

चीन लंबे समय से एशिया में अमेरिकी प्रभाव को संतुलित करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी ओर रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी प्रतिबंधों और नाटो के विस्तार से स्वयं को घिरा हुआ महसूस कर रहा है। उत्तर कोरिया पहले से ही अमेरिका और उसके सहयोगियों दक्षिण कोरिया तथा जापान के साथ तनावपूर्ण संबंध रखता है। ऐसे में इन तीनों देशों के हित कई बिंदुओं पर एक-दूसरे से मेल खाते दिखाई देते हैं। यही कारण है कि इनके बीच राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य सहयोग की संभावनाएँ लगातार मजबूत होती जा रही हैं।

रूस और उत्तर कोरिया के बीच हाल के वर्षों में संबंधों में उल्लेखनीय गर्मजोशी देखने को मिली है। दोनों देशों के शीर्ष नेताओं की मुलाकातों ने यह संदेश दिया है कि वे सुरक्षा और रक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के इच्छुक हैं। यूक्रेन युद्ध के कारण रूस को पश्चिमी देशों के भारी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं उत्तर कोरिया भी दशकों से आर्थिक प्रतिबंधों के दबाव में है। ऐसे में दोनों देशों के बीच सहयोग उन्हें कुछ हद तक रणनीतिक राहत प्रदान कर सकता है।अमेरिका और नाटो के विरुद्ध चीन-रूस-उत्तर कोरिया की नई तिकड़ी बदलती विश्व राजनीति का संकेत

विश्व राजनीति एक बार फिर ऐसे मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है जहाँ महाशक्तियों के बीच नए समीकरण बन रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में रूस और पश्चिमी देशों के बीच बढ़ा तनाव, यूक्रेन युद्ध, ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा तथा कोरियाई प्रायद्वीप में लगातार बढ़ती सैन्य गतिविधियों ने वैश्विक शक्ति संतुलन को नई दिशा दी है। इसी परिप्रेक्ष्य में चीन, रूस और उत्तर कोरिया के बीच बढ़ती निकटता को अंतरराष्ट्रीय राजनीति के जानकार अत्यंत महत्वपूर्ण मान रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन से मुलाकात तथा रूस और उत्तर कोरिया के बीच बढ़ते सामरिक संबंध इस बात के संकेत हैं कि अमेरिका और नाटो देशों के सामने एक नया रणनीतिक समूह आकार ले रहा है।

चीन इस पूरे समीकरण का सबसे प्रभावशाली पक्ष है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के कारण चीन के पास आर्थिक और तकनीकी संसाधनों की विशाल शक्ति है। चीन खुले तौर पर किसी सैन्य गठबंधन की घोषणा नहीं करता, लेकिन उसके कूटनीतिक कदम यह संकेत देते हैं कि वह अमेरिका के नेतृत्व वाली व्यवस्था के विकल्प के रूप में बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को बढ़ावा देना चाहता है। उत्तर कोरिया के साथ उसके संबंध ऐतिहासिक हैं, जबकि रूस के साथ उसकी साझेदारी पिछले दशक में और अधिक गहरी हुई है। अमेरिका और नाटो देशों की चिंता का मुख्य कारण यह है कि यदि चीन, रूस और उत्तर कोरिया के बीच सहयोग और मजबूत होता है तो एशिया-प्रशांत क्षेत्र तथा यूरोप दोनों में पश्चिमी रणनीतियों को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। नाटो पहले ही रूस को अपनी सुरक्षा के लिए प्रमुख चुनौती मान चुका है। दूसरी ओर अमेरिका चीन को अपने सबसे बड़े रणनीतिक प्रतिस्पर्धी के रूप में देखता है। उत्तर कोरिया की मिसाइल और परमाणु क्षमताएँ भी लगातार चर्चा का विषय बनी हुई हैं। ऐसे में इन तीनों देशों का बढ़ता सामंजस्य पश्चिमी देशों की सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा रहा है। यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि चीन, रूस और उत्तर कोरिया किसी औपचारिक सैन्य गठबंधन का निर्माण कर रहे हैं। इनके अपने-अपने राष्ट्रीय हित हैं और कई मामलों में इनके दृष्टिकोण अलग भी हो सकते हैं। फिर भी अंतरराष्ट्रीय राजनीति में संकेतों का महत्व होता है, और वर्तमान संकेत बताते हैं कि ये तीनों देश अमेरिका के नेतृत्व वाली वैश्विक व्यवस्था के प्रति समान प्रकार की असहमति रखते हैं। यही साझा दृष्टिकोण इन्हें एक-दूसरे के करीब ला रहा है।

विश्व व्यवस्था में यह परिवर्तन केवल सैन्य या राजनीतिक नहीं है, बल्कि आर्थिक और कूटनीतिक स्तर पर भी दिखाई दे रहा है। डॉलर आधारित वैश्विक आर्थिक व्यवस्था के विकल्पों की चर्चा, क्षेत्रीय सहयोग मंचों की सक्रियता तथा पश्चिमी प्रभाव से स्वतंत्र नीति अपनाने की कोशिशें इस बदलाव का हिस्सा हैं। चीन और रूस पहले ही कई क्षेत्रों में स्थानीय मुद्राओं में व्यापार बढ़ाने की दिशा में कदम उठा चुके हैं। उत्तर कोरिया भी इस उभरते समीकरण में अपने लिए सुरक्षा और आर्थिक अवसर तलाश रहा है। वर्तमान परिस्थितियाँ शीत युद्ध जैसी प्रतिद्वंद्विता की याद अवश्य दिलाती हैं, किंतु आज की दुनिया पहले की तुलना में कहीं अधिक परस्पर जुड़ी हुई है। इसलिए किसी भी नए शक्ति समूह का प्रभाव केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक होगा। चीन, रूस और उत्तर कोरिया की बढ़ती निकटता इस बात का संकेत है कि आने वाले वर्षों में विश्व राजनीति और अधिक जटिल तथा बहुध्रुवीय हो सकती है। अमेरिका और नाटो जहाँ अपनी रणनीतियों को मजबूत करने में लगे हैं, वहीं यह नई तिकड़ी अपने हितों की रक्षा और प्रभाव विस्तार के लिए नए रास्ते तलाश रही है। यह माना जा सकता है कि चीन, रूस और उत्तर कोरिया के बीच बढ़ता सहयोग अंतरराष्ट्रीय राजनीति में उभरते नए शक्ति संतुलन का प्रतीक है। यह गठजोड़ चाहे औपचारिक रूप न ले, लेकिन इसके संकेत स्पष्ट हैं कि विश्व व्यवस्था एक नए दौर में प्रवेश कर रही है जहाँ महाशक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा और रणनीतिक समीकरण वैश्विक राजनीति की दिशा निर्धारित करेंगे।

ध्यान ईश्वर की ओर प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत यात्रा है

वर्तमान समय में ध्यान तथाकथित योग गुरुओं तथा मनोचिकित्सकों द्वारा लोगों को लुभाने का एक उपकरण मात्र बनकर रह गया है। सहजयोग संस्थापिका श्री माताजी निर्मला देवी जी द्वारा हमें मार्गदर्शित किया गया है कि ध्यान कोई क्रिया नहीं है बल्कि ध्यान में स्थित होना होता है। ध्यान हमें वैराग्य सिखाता है। अधिकांशतः मनुष्य में चाहना अथवा इच्छाएं ही बलवती होती हैं, कभी अपने लिए, कभी अपनों के लिए। लौकिक जीवन में कुछ ना कुछ उसे चाहिए ही होता है और जब वह परम शक्तिमान के सामने उपस्थित हो प्रार्थना को तत्पर होता है तो वही सब जो उसके दिमाग में चल रहा है जिसे वह आवश्यक समझता है वही एक के बाद एक उसकी प्रार्थनाओं का हिस्सा होता चला जाता है। जबकि वास्तव में परमात्मा को जानने के बाद, ध्यान में ईश्वर तत्व का एवं अपनी आत्मा में परम तत्व का अनुभव कर लेने के बाद मनुष्य परिपक्व मति हो जाता है। अब वह जान जाता है कि लौकिक जीवन की अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यह प्रार्थना का अनमोल समय उसे खोना नहीं है। वास्तव में परमात्मा से परम मांगना चाहिए अलौकिक मांगना चाहिए, परंतु ध्यान के पूर्व दृष्टि के संकोच के कारण वह बड़ा नहीं सोच पाता। सहजयोग में अत्यंत सरलता से ध्यान के द्वारा आत्मा से साक्षात्कार का अनुभव होता है और हम अपने भीतर गहनता का अनुभव करते हैं यही गहनता हमारी मन बुद्धि को परिपक्व करती है गहरा करती है तब हम प्रार्थना में निर्विचार हो जाते हैं और हमारी ऐसी प्रार्थनाएं फलीभूत भी होती हैं। ध्यान में आपका कोई सगा संबंधी नहीं है, आप इसमें अकेले हैं यह आपकी व्यक्तिगत यात्रा है। यह भगवान की ओर एक निजी यात्रा है, आपको अपने भीतर अकेले आगे बढ़ना होता है। लेकिन ध्यान मन में आप अकेले हैं। कोई भी वहां मौजूद नहीं है। एक बार जब आप उस सागर में प्रवेश करते हैं तो आपका परिवार पूरी दुनिया हो जाती है क्योंकि तब हमारा संयोग परम से हो जाता है और तब हमें अहसास होता है कि हम जमीन के किसी एक छोटे से टुकड़े के मालिक नहीं है बल्कि संपूर्ण धरा के स्वामी हैं। इस स्थिति में हमारी प्रार्थनाओं का विस्तार हो जाता है। पर पीड़ा को समझने की गहन शक्ति का विकास हमारे भीतर होने लगता है और तब हमारी प्रार्थनाओं को पूर्ण होने की सिद्धि प्राप्त हो जाती है।

सिस्टम की आग में जलते मजदूर, प्रगति का स्वांग कब तक?

जब रोज़ी-रोटी कमाने निकले हाथ आग की लपटों में खो जाएं, तब हादसे सिर्फ दुर्घटनाएं नहीं, व्यवस्था की नाकामी का आईना बन जाते हैं। विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में 8 जून 2026 की वह शाम भी ऐसा ही दर्दनाक सच बनकर उभरी। स्टील मेल्टिंग शॉप-1 में लेडल फटने के बाद 1600 डिग्री तापमान की पिघली धातु मजदूरों पर बरसी तो केवल आठ श्रमिकों की जान नहीं गई, बल्कि सुरक्षित और मानवीय औद्योगिक विकास का दावा भी सवालों के घेरे में आ गया। आग ने उनके शरीर झुलसाए, लेकिन उससे कहीं गहरा घाव हमारी व्यवस्था की संवेदनहीनता पर लगा। विकास की चकाचौंध के पीछे छिपा यह अंधेरा पूछ रहा है—क्या इस देश में एक मजदूर की कीमत अब लोहे से भी कम रह गई है?

हर बड़ी त्रासदी से पहले लापरवाही की कई अनदेखी परतें होती हैं। यह हादसा भी अचानक नहीं हुआ। जर्जर मशीनें, सुरक्षा में चूक, अधूरा रखरखाव, कमजोर प्रशिक्षण और ठेका श्रमिकों के प्रति उपेक्षा ने मिलकर वह हालात बनाए, जिनमें आठ जिंदगियां बुझ गईं। विडंबना यह है कि खतरे के संकेत पहले ही मिल चुके थे। कुछ सप्ताह पूर्व इसी संयंत्र में कार्बन मोनोऑक्साइड रिसाव से चार श्रमिक अस्पताल पहुंचे थे। चेतावनी साफ थी, लेकिन व्यवस्था ने उसे नजरअंदाज कर दिया। सच यह है कि हादसे विस्फोट के दिन नहीं होते; वे उसी दिन शुरू हो जाते हैं, जब चेतावनियों को फाइलों में दफना दिया जाता है।

यह सिर्फ विजाग (विशाखापत्तनम) स्टील प्लांट का हादसा नहीं, बल्कि देश की औद्योगिक व्यवस्था का कड़वा सच है। मैन्युफैक्चरिंग, खनन और इस्पात क्षेत्रों में हर वर्ष सैकड़ों श्रमिक मौत के मुंह में समा जाते हैं। जो आंकड़े दिखते हैं, वे अधूरी तस्वीर हैं; असंगठित क्षेत्र में तो कई मौतें रिकॉर्ड तक नहीं बन पातीं। ठेकेदारी व्यवस्था ने श्रमिक को अधिकारों वाले इंसान से ज्यादा एक इस्तेमाल की वस्तु बना दिया है। न पर्याप्त सुरक्षा, न समुचित प्रशिक्षण, न संकट से बचाव की ठोस व्यवस्था। जब एक प्रतिष्ठित सार्वजनिक संयंत्र में सुरक्षा का यह हाल है, तो उन निजी इकाइयों की स्थिति का अनुमान सहज लगाया जा सकता है, जहां मुनाफा अक्सर इंसानी जिंदगी पर भारी पड़ जाता है।

इस त्रासदी का सबसे असहज सवाल जवाबदेही का है। हमारे यहां हर बड़े हादसे के बाद वही घिसा-पिटा क्रम दोहराया जाता है—शोक, मुआवजा, जांच समिति और कुछ दिनों तक मीडिया की हलचल। फिर धीरे-धीरे सब कुछ सामान्य मान लिया जाता है। पर क्या कभी सचमुच जिम्मेदारों की पहचान होती है? क्या दोष केवल मशीन का था या महज तकनीकी विफलता का? बिल्कुल नहीं। इस हादसे की जिम्मेदारी प्रबंधन, सुरक्षा तंत्र, निरीक्षण एजेंसियों, श्रम विभाग, सरकारों और उस राजनीतिक संस्कृति पर भी है, जो जवाबदेही से अधिक संरक्षण को महत्व देती है। यदि निरीक्षण निष्पक्ष होते, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होती और भ्रष्टाचार की परतें इतनी मोटी न होतीं, तो शायद यह त्रासदी टाली जा सकती थी। दुर्भाग्य से हमारे यहां हादसों की जांच होती है, व्यवस्था की नहीं।

एक ओर भारत तेज़ आर्थिक विकास, निवेश, विनिर्माण और बुनियादी ढांचे के नए कीर्तिमान गढ़ने का दावा कर रहा है, वहीं दूसरी ओर श्रमिकों की सुरक्षा लगातार सवालों के घेरे में है। किसी भी विकास की असली कसौटी आंकड़े नहीं, बल्कि सबसे कमजोर व्यक्ति की सुरक्षा होती है। यदि उत्पादन बढ़ाने की कीमत श्रमिकों के प्राण बन जाए, तो उसे प्रगति नहीं, संस्थागत अमानवीयता कहना अधिक उचित होगा। किसी राष्ट्र की महानता उसकी गगनचुंबी इमारतों से नहीं, उन हाथों की सुरक्षा से तय होती है जो उन्हें खड़ा करते हैं। दुर्भाग्य यह है कि हमारे यहां अक्सर उत्पादन के लक्ष्य इंसानी जीवन से अधिक मूल्यवान मान लिए जाते हैं।

इस संकट की जड़ें मशीनों में नहीं, मानसिकता में छिपी हैं। यह केवल तकनीकी नहीं, बल्कि नैतिक विफलता है। भ्रष्टाचार, लागत घटाने की होड़, प्रशासनिक उदासीनता और राजनीतिक संरक्षण ने ऐसी व्यवस्था गढ़ दी है, जहां मजदूर को इंसान नहीं, बदले जा सकने वाले संसाधन की तरह देखा जाता है। एक श्रमिक की जगह दूसरा मिल सकता है, लेकिन किसी परिवार का सहारा, बच्चों के सपने और माता-पिता की उम्मीदें नहीं लौट सकतीं। सबसे खतरनाक बात यह है कि व्यवस्था अक्सर ऐसी त्रासदियों को सामान्य मानकर आगे बढ़ जाती है। जब किसी वर्ग की पीड़ा साधारण लगने लगे, तब हादसे सिर्फ कारखानों में नहीं, समाज की संवेदनाओं में भी होने लगते हैं।

हर नई त्रासदी यह साबित कर रही है कि चेतावनियों को अब और अनसुना नहीं किया जा सकता। औद्योगिक सुरक्षा को औपचारिकता नहीं, अनिवार्य जिम्मेदारी बनाना होगा। प्रत्येक इकाई में स्वतंत्र सुरक्षा ऑडिट हों और लापरवाही से हुई मौतों पर जिम्मेदार प्रबंधकों, अधिकारियों व ठेकेदारों के खिलाफ केवल विभागीय कार्रवाई नहीं, बल्कि आपराधिक मुकदमे चलें। ठेका श्रम व्यवस्था पर सख्त नियंत्रण, श्रमिकों को प्रभावी प्रशिक्षण, आधुनिक सुरक्षा उपकरण और आपात स्थितियों से निपटने की पूरी तैयारी सुनिश्चित की जाए। श्रम कानून कागजों से निकलकर कारखानों तक पहुंचें। सबसे महत्वपूर्ण, सुरक्षा को खर्च नहीं, मानव जीवन की रक्षा में किया गया सबसे आवश्यक निवेश माना जाए।

किसी राष्ट्र की महानता उसकी फैक्ट्रियों की ऊंचाई से नहीं, बल्कि अपने श्रमिकों के जीवन के प्रति उसकी संवेदनशीलता से मापी जाती है। भारत को महाशक्ति बनने का स्वप्न अवश्य देखना चाहिए, लेकिन उसकी नींव श्रमिकों की चिताओं पर नहीं रखी जा सकती। विजाग की यह त्रासदी केवल आठ परिवारों का शोक नहीं, पूरे देश के लिए एक गंभीर चेतावनी है। यदि विकास की दौड़ में मानवीय गरिमा और सुरक्षा को यूं ही नजरअंदाज किया गया, तो कल केवल स्थान, संयंत्र और आंकड़े बदलेंगे, लेकिन श्मशानों की आग और परिवारों का विलाप वही रहेगा। तब इतिहास दर्ज करेगा कि भारत स्टील की भट्टियों में नहीं, अपनी ही संवेदनहीनता और लापरवाही में पिघल रहा था।

-प्रो. आरके जैन

औपनिवेशिक छाप से मुक्त हो शिक्षा

देश में रह-रहकर बौद्धिक वर्ग में डीकोलोनाइजेशन यानी वि-उपनिवेशीकरण की चर्चा छिड़ती रहती है, लेकिन वह किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाती। यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जब भी वि-उपनिवेशीकरण की मुहिम छिड़े तो उसका आधार भी भारतीय होना चाहिए। हमें इस तथ्य को पहचान कर भारत में समकालीन उच्च शिक्षण संस्थानों और उनके उत्पादों, अनुसंधान प्रयासों एवं स्नातकों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करना ही प्राथमिकता होनी चाहिए। इस संदर्भ में देखा जाए तो उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम को नवाचारों के माध्यम से सजीव करने की आवश्यकता तो बहुत दिनों से महसूस की जाती रही है, परंतु कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा सका। यह प्रवृत्ति देशज विकास के प्रयासों में सदैव बाधक ही रहेगी। स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने वर्षों बाद भी देश की शैक्षणिक प्रणाली पर औपनिवेशिक पकड़ को समाप्त करना एक कठिन कार्य सिद्ध हो रहा है। वर्तमान में कई भारतीय संस्थानों के पाठ्यक्रम भारतीय परिप्रेक्ष्य की वास्तविकताओं या इसकी समस्याओं के ज्ञान को पूरी तरह से प्रतिबिंबित नहीं करते। उच्च संस्थानों की प्रणालियों में भारतीय ज्ञान के वि-उपनिवेशीकरण के प्रयासों को तभी स्पष्ट और सक्रिय रूप से समर्थन दिया जा सकेगा, जब छात्रों को यह सिखाया जाए कि मौलिकता की राह पर कैसे चलें? उन्हें भारतीय परिस्थितियों के लिए विशेष और विशिष्ट समाधान की दिशा में सोचने के लिए भी शिक्षित करना होगा। भारतीय ज्ञान की वर्तमान व्यवस्था के वि-उपनिवेशीकरण से ही पूर्ण स्वराज की प्राप्ति संभव हो सकेगी। अब नवोन्मेषी विचारों और कार्यक्रमों की शुरुआत करने से पहले सोचने के लिए ज्ञान मीमांसकीय रूप से स्वतंत्र होना होगा। ज्ञान मीमांसकीय मुक्ति मानसिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक स्वतंत्रता को जन्म देती है। शिक्षा के उच्च संस्थानों ने भारतीय विचार-दृष्टि की गतिशीलता पर अपनी पकड़ खो दी है। इसका एक विशेष कारण है ज्ञान को समायोजित करने के लिए भारतीय भाषाओं को विकसित करने में विफलता। आज भी अंग्रेजी प्रामाणिक भाषा है और ज्ञान की दुनिया में उसी का वर्चस्व है। मन में हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं में सोचते हुए उन विचारों को अंग्रेजी में उल्था कर प्रस्तुत करना समयसाध्य ही नहीं, बहुधा निष्प्रभावी एवं अप्रामाणिक भी सिद्ध होता है। मौलिक सोच का अवसर इसलिए भी जाता रहता है कि हम अपने विचार और उसकी कोटियां विदेश से आयातित किए हुए हैं और उसमें 'फिट' किए बगैर सोचने-विचारने की प्रक्रिया ही नहीं शुरू हो पाती है।

अपने शिक्षण संस्थानों में होने वाले बौद्धिक प्रयासों, शिक्षण प्रक्रिया और अनुसंधान में भारतीय भाषाओं को संस्थागत रूप से न अपना पाना मौलिकता के रास्ते में एक बहुत बड़ा रोड़ा है। यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि कई देश जो तकनीकी प्रगति में छलांग लगा रहे हैं, आविष्कारों में प्रगति कर रहे हैं और अकादमिक उत्कृष्टता की सीमाओं को तोड़ रहे हैं, वे ही देश हैं जिन्होंने अपने शैक्षिक पाठ्यक्रम को अपने अनुसार अनुकूलित एवं विकसित किया है।

-धनंजय राजौरा

भारत की बढ़ती परमाणु शक्ति

सिपरी यानी स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय षांति अनुसंधान संस्थान की ताजा रिपोर्ट में भारत की बढ़ती परमाणु षक्ति को रेखांकित किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत ने पहली बार 12 परमाणु हथियार मोर्चे पर तैनात किए हैं। जबकि भारत के पास कुल परमाणु हथियारों की संख्या बढ़कर लगभग 190 हो गई हैं। भारत ने 2025 में सैन्य खर्च 92.1 अरब डॉलर किया है। इस कारण भारत दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा सैनिक हथियारों पर खर्च करने वाला देष बन गया है। हथियार आयात करने में भी भारत दूसरे स्थान पर है। इस कड़ी में पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे पर रूस, तीसरे पर चीन, चैथे पर भारत और पांचवें पर पाकिस्तान हैं। दुनिया के पास कुल 12.187 परमाणु हथियार हैं। इनमें सबसे ज्यादा अमेरिका के पास 5042 हथियार हैं। सिपरी के अनुसार भारत लंबी दूरी के हथियारों की संख्या बढ़ा रहा हैं, ताकि पूरे चीन तक भारत की मारक क्षमता मजबूत हो जाए। भारत की प्रतिद्वंद्विता पाकिस्तान से भी है। भारत परमाणु डिलीवरी सिस्टम पर भी काम कर रहा है। ऑपरेषन सिंदूर के दौरान सैन्य संघर्श में भारत ने पहली बार साइबर मोर्चा भी खोल दिया था।

कुछ दिन पहले अमेरिकी राश्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा 'बयान-बम' फोड़ा था। विवादित बयानों को लेकर चर्चित ट्रंप ने दावा किया था कि चीन और पाकिस्तान गुप्त रूप से परमाणु परीक्षण में लगे हैं। रूस और उत्तर कोरिया भी परमाणु परीक्षण कर अपने हथियारों की ताकत टटोल रहे हैं। ये देश कभी भी यह बात स्वीकारने को तैयार नहीं हैं कि वे परमाणु परीक्षण कर रहे हैं। ये देश भूमि की बहुत गहराई में परीक्षण करते हैं। इसलिए इनके परीक्षण की आहट किसी के कानों में नहीं गूंजती है। इन देषों के लोग खुले समाज के हिस्सा नहीं हैं, अतएव यहां की जानकारियां गोपनीय बनी रहती हैं। यह बात ट्रंप को इसलिए कहनी पड़ी, क्योंकि अमेरिका 30 साल बाद अपने परमाणु हथियारों का परीक्षण फिर से करने का फैसला ले चुका है। इसलिए उन्होंने अपनी सरकार के फैसले को पाक और चीन के परीक्षणों के परिप्रेक्ष्य में तार्किक ठहराने के लिए कही है। यह बात ट्रंप ने न्यूज चैनल सीबीएस से बात करते हुए कही थी।

दरअसल रूस द्वारा ट्रंप से पूछा गया था कि 'क्या वे एडवांस न्यूक्लियर-कैपेबल सिस्टम, जिसके द्वारा पोसाइडन अंडरवाटर ड्रोन गतिविधि शामिल है, उसके परीक्षण के बाद परमाणु हथियारों का परीक्षण भी करेंगे ?' इसके उत्तर में ट्रंप ने कहा था, 'उनके पास किसी भी दूसरे देश से अधिक परमाणु हथियार हैं। इन हथियारों से दुनिया को 150 बार नष्ट किया जा सकता है। हम इन्हें नहीं परखते। किंतु जब दूसरे देष परीक्षण कर रहे हैं, तब हमें भी करने की जरूरत है।'याद रहे, ट्रंप ने दक्षिण कोरिया के बुसान नगर में चीन के राष्टपति शी जिनपिंग से मुलाकात करने से पहले अमेरिका द्वारा परमाणु परीक्षणों को फिर से शुरू करने का बयान दिया था। पानी के भीतर पोसाइडन ड्रोन प्रणाली एक ऐसी तकनीक है, जिसमें रोबोटिक वाहन पानी के नीचे सक्रिय रहते हैं। ये स्वायत्त रूप से संचालित रहने के साथ इन्हें रिमोट के जरिए दूर से भी संचालित किया जा सकता है। ये ड्रोन पनडुब्बी वाहनों के समान होते हैं, जो बिना किसी मानव के पानी के नीचे संचालन और अनुसंधान के लिए होते हैं।

किसी भी परमाणु हथियार संपन्न देश को परमाणु परीक्षण की जरूरत इसलिए होती है, क्योंकि परमाणु बम के लिए जरूरी यूरेनियम को संवर्धन (एनरिच) करना होता है। यह प्रक्रिया एक तकनीकी परीक्षण है। परमाणु परीक्षण की घोषणा किसी भी देश की ऐसी यौद्धिक रणनीति का हिस्सा है, जिससे वह षत्रु देष को अपनी ताकत का अहसास कराता है। भारत ने 1998 के बाद कोई परमाणु परीक्षण नहीं किया है। अब चीन और पाक द्वारा गोपनीय रूप में परमाणु परीक्षण की बात सामने आई है। अतएव इन देषों से भारत को परमाणु हमले का खतरा बढ़ गया है। इसलिए भारत को भी अपनी परमाणु हथियार दागने की तकनीक का परीक्षण करना जरूरी हो गया है। हालांकि भारत का सिद्धांत पहले परमाणु हमला नहीं करने का रहा है। लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह चुके हैं कि अब हम इस वचन के पालन के लिए प्रतिबद्ध नहीं हैं।

पहले भी हमला कर सकते हैं। वैसे भी भारत ने अब तक परमाणु परीक्षणों को प्रतिबंधित करने वाली संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। षायद इसीलिए टंउप्र को कहना पड़ा है कि 'ऑपरेषन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के विरुद्ध भारत परमाणु हमले के लिए तत्पर था। इस कारण पाकिस्तानी प्रधानमंत्री षहबाज षरीफ ने मुझसे निवेदन किया था कि आप बीच में आकर युद्ध रोकें, वरना पाक में लाखों लोग मारे जाएंगे।'

बहरहाल, ट्रंप के किसी भी दावे की पुश्टि भारत नहीं करता है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि दुनिया के कई देष न केवल परमाणु परीक्षण करने में लगे हैं, बल्कि घातक परमाणु हथियारों को इकट्ठा करने की होड़ में भी लगे हैं। स्टॉकहोम स्थित 'अंतरराश्ट्रीय षांति अनुसंधान संस्थान' (एसआईआरआई) के एक अध्ययन ने दावा किया है कि चीन के पास 350, पाकिस्तान 165 और भारत के पास जनवरी 2021 तक 156 परमाणु हथियार मौजूद थे। हालांकि ताजा रिपोर्ट के अनुसार सभी देषों ने अपने परमाणु हथियारों की संख्या में वृद्धि कर ली है। ऐसा लगता है कि ये तीनों पड़ोसी देष अपने परमाणु षस्त्रगारों का विस्तार कर रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक इस समय 12,187 परमाणु हथियार दुनिया के देषों के पास हैं। इनमें 90 प्रतिषत से ज्यादा रूस और अमेरिका के पास हैं। इनके अलावा ब्रिट्रेन, फ्रांस, इजराइल और उत्तर कोरिया के पास भी हथियारों का बड़ा जखीरा है। चीन परमाणु हथियारों की संख्या के बढ़ाने के साथ उनका तकनीकी रूप से आधुनिकीकरण भी कर रहा है। सऊदी अरब, मिश्र, भारत, आस्ट्रेलिया और चीन ने 2016 से 2020 के बीच सबसे ज्यादा हथियार आयात किए हैं। ट्रंप तो सरेआम कह रहे हैं कि उनके पास दुनिया को 150 बार तहस-नहस करने की परमाणु क्षमता है। यानी दुनिया परमाणु युद्ध के मुहाने पर खड़ी है।

अमेरिकी गुप्तचर संस्था सीआईए के पूर्व वरिश्ठ खुफिया अधिकारी केविन हलबर्ट की बात मानें तो पाकिस्तान दुनिया के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक देषों में से एक है। पाकिस्तान की यह खुंखार और डरावनी सूरत इसलिए बन गई है, क्योंकि तीन तरह के जोखिम इस देष में खतरनाक ढंग से बढ़ रहे हैं। एक आतंकवाद, दूसरे ढह रही अर्थव्यवस्था और तीसरे परमाणु हथियारों का जरूरत से ज्यादा भंडारण। आर्थिक संकट के ऐसी ही बद्तर हालात से उत्तर कोरिया जूझ रहा है। मानव स्वभाव में प्रतिषोध और ईर्श्या दो ऐसे तत्व हैं, जो व्यक्ति को विवेक और संयम का साथ छोड़ देने को मजबूर कर देते हैं। इस स्वभाव को क्रूरतम परिणति में बदलते हम अमेरिका द्वारा हिरोषिमा और नागासाकी पर किए परमाणु हमलों के रूप में देख चुके हैं। अमेरिका ने हमले का जघन्य अपराध उस नाजुक परिस्थिति में किया था, जब जापान इस हमले के पहले ही लगभग पराजय स्वीकार कर चुका था। पाक इस समय इसी क्रूरतम मानसिकता से गुजर रहा है। ऐसे में यदि वह चीन के साथ परमाणु परीक्षण कर रहा है, तो यह बेहद चिंताजनक स्थिति है। ट्रंप जो बात कह रहे हैं, वह हवा-हवाई होने की बजाय संभव है कि उनकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के आधार पर कही गई हो ट्रंप जैसे अविवेकी शासक पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है।

-प्रमोद भार्गव

नेत्रदानः अंधकार से प्रकाश की ओर सबसे बड़ा सेतु

मानव जीवन में आंखों का महत्व केवल देखने तक सीमित नहीं है, बल्कि वे हमारी चेतना, संवेदना, ज्ञान और जीवन के सौंदर्य का द्वार हैं। आंखों के माध्यम से ही हम प्रकृति की विविधता, परिवार का स्नेह, समाज की गतिविधियों और संसार की अनंत संभावनाओं का अनुभव करते हैं। इसलिए दृष्टि का अभाव केवल शारीरिक अक्षमता नहीं, बल्कि जीवन के अनेक आयामों से वंचित हो जाने की पीड़ा है। ऐसे में नेत्रदान केवल एक चिकित्सकीय प्रक्रिया नहीं, बल्कि किसी अंधेरे जीवन में प्रकाश भरने वाला महान मानवीय और आध्यात्मिक उपक्रम है। प्रतिवर्ष 10 जून को मनाया जाने वाला 'विश्व नेत्रदान दिवस' हमें यह स्मरण कराता है कि मृत्यु के बाद भी हमारा अस्तित्व किसी अन्य व्यक्ति के जीवन में रोशनी बनकर जीवित रह सकता है। यह दिवस केवल जागरूकता का अवसर नहीं, बल्कि मानवीय संवेदना, सामाजिक उत्तरदायित्व और परोपकार की संस्कृति को सशक्त करने का अभियान है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया में करोड़ों लोग दृष्टिबाधिता और अंधता से प्रभावित हैं। भारत में भी लाखों लोग कॉर्निया संबंधी रोगों के कारण दृष्टि खो चुके हैं। विशेष चिंता की बात यह है कि कॉर्निया की खराबी से होने वाली अंधता के अनेक मामलों का उपचार संभव है, किंतु पर्याप्त नेत्रदान न होने के कारण लाखों मरीज वर्षों तक प्रतीक्षा सूची में बने रहते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार कॉर्निया प्रत्यारोपण चिकित्सा विज्ञान की सबसे सफल प्रत्यारोपण प्रक्रियाओं में से एक है, जिसकी सफलता दर 95 से 98 प्रतिशत तक मानी जाती है। इसके बावजूद देश में आवश्यकता की तुलना में उपलब्ध कॉर्निया की संख्या बहुत कम है। हर वर्ष लाखों लोगों को कॉर्निया की जरूरत होती है, लेकिन दान की संख्या अपेक्षाकृत बहुत कम रहती है। यह स्थिति बताती है कि समस्या चिकित्सा संसाधनों की नहीं, बल्कि जागरूकता और सामाजिक संकल्प की है।

भारतीय संस्कृति में दान को धर्म का आधार माना गया है। अन्नदान भूख मिटाता है, वस्त्रदान शरीर को ढंकता है, धनदान आर्थिक सहायता देता है, किंतु नेत्रदान किसी व्यक्ति को जीवन का नया अनुभव प्रदान करता है। इसीलिए इसे महादान या जीवनदान की श्रेणी में रखा गया है। जब कोई व्यक्ति मृत्यु के बाद अपनी आंखें दान करता है, तब वह केवल एक अंग नहीं देता, बल्कि किसी अंधे व्यक्ति को संसार देखने का अवसर प्रदान करता है। वह किसी बच्चे को शिक्षा का मार्ग, किसी युवा को रोजगार की संभावना और किसी वृद्ध को आत्मनिर्भरता की शक्ति देता है। यह दान ऐसा है जिसमें दाता को कोई हानि नहीं होती, लेकिन प्राप्तकर्ता का संपूर्ण जीवन बदल जाता है। भारतीय परंपरा में महर्षि दधीचि का उदाहरण त्याग और देहदान की सर्वोच्च मिसाल माना जाता है। उन्होंने लोककल्याण के लिए अपना शरीर समर्पित किया था। नेत्रदान उसी परंपरा की आधुनिक अभिव्यक्ति है। यह मृत्यु के बाद भी मानवता की सेवा का अवसर प्रदान करता है। वास्तव में नेत्रदान वह पुण्य है जिसमें दाता का शरीर समाप्त हो जाता है, किंतु उसकी दृष्टि किसी और के जीवन में प्रकाश बनकर जीवित रहती है।

आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने नेत्रदान की उपयोगिता को और अधिक व्यापक बना दिया है। पहले एक दाता की दोनों आंखों से केवल दो व्यक्तियों को लाभ मिलता था, किंतु नई तकनीकों के माध्यम से एक कॉर्निया के विभिन्न भागों का उपयोग करके अधिक लोगों की सहायता संभव हो रही है। आज एक नेत्रदाता कई व्यक्तियों के जीवन में प्रकाश ला सकता है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि नेत्रदान के लिए किसी विशेष आयु की आवश्यकता नहीं होती। 80 या 90 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति की आंखें भी उपयोगी हो सकती हैं। चश्मा पहनने वाले, मधुमेह या उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति भी अधिकांश स्थितियों में नेत्रदान कर सकते हैं। यह भ्रांति कि केवल पूर्णतः स्वस्थ व्यक्ति ही नेत्रदान कर सकते हैं, पूरी तरह गलत है। मृत्यु के बाद 4 से 6 घंटे के भीतर कॉर्निया सुरक्षित निकाल लिया जाता है और पूरी प्रक्रिया अत्यंत सम्मानपूर्वक संपन्न होती है। इससे मृतक के चेहरे की बनावट में कोई विकृति नहीं आती और अंतिम संस्कार में भी कोई बाधा नहीं होती।

नेत्रदान को बढ़ावा देने में सबसे बड़ी बाधा सामाजिक मिथक और अंधविश्वास हैं। अनेक लोग मानते हैं कि नेत्रदान करने से मृत शरीर विकृत हो जाता है या अगले जन्म में आंखें नहीं मिलेंगी। कुछ लोग यह भी सोचते हैं कि वृद्ध व्यक्तियों अथवा चश्मा पहनने वालों की आंखें उपयोगी नहीं होतीं। चिकित्सा विज्ञान ने इन धारणाओं को पूरी तरह निराधार सिद्ध कर दिया है। आवश्यकता इस बात की है कि समाज वैज्ञानिक तथ्यों को स्वीकार करे और अंधविश्वासों से मुक्त होकर मानवता के इस महान अभियान से जुड़े। नेत्रहीनता केवल व्यक्तिगत समस्या नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक चुनौती भी है। दृष्टिबाधिता व्यक्ति की शिक्षा, रोजगार और आत्मनिर्भरता को प्रभावित करती है। इससे परिवार पर आर्थिक बोझ बढ़ता है और समाज की उत्पादक क्षमता भी घटती है। विभिन्न अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि दृष्टिबाधिता के कारण देश को प्रतिवर्ष अरबों रुपये की आर्थिक क्षति होती है। यदि कॉर्निया अंधता से पीड़ित लोगों को समय पर प्रत्यारोपण उपलब्ध हो जाए, तो वे पुनः शिक्षा, रोजगार और सामाजिक जीवन में सक्रिय भागीदारी कर सकते हैं। इस प्रकार नेत्रदान केवल मानवीय सेवा नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का भी माध्यम है।

सभी प्रमुख धर्म मानव सेवा को सर्वोच्च धर्म मानते हैं। किसी भी धर्मग्रंथ में नेत्रदान या अंगदान का निषेध नहीं है। इसके विपरीत, परोपकार, दया और करुणा को आध्यात्मिक उन्नति का आधार बताया गया है। जब कोई व्यक्ति मृत्यु के बाद अपने नेत्र दान करता है, तो वह यह संदेश देता है कि जीवन केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जिया जाना चाहिए। यह भावना व्यक्ति को संकीर्ण स्वार्थ से ऊपर उठाकर व्यापक मानवता से जोड़ती है। वास्तव में नेत्रदान ईश्वर की सृष्टि के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक श्रेष्ठ माध्यम है। आज आवश्यकता है कि नेत्रदान को केवल एक स्वास्थ्य कार्यक्रम न मानकर सामाजिक एवं नैतिक आंदोलन के रूप में देखा जाए। परिवारों में इस विषय पर खुलकर चर्चा हो, युवाओं को इसके प्रति प्रेरित किया जाए और प्रत्येक नागरिक मृत्यु के उपरांत नेत्रदान का संकल्प ले। यदि समाज का एक बड़ा वर्ग इस दिशा में आगे आता है तो देश में कॉर्निया अंधता की समस्या को काफी हद तक समाप्त किया जा सकता है।

नेत्रदान को जन-आंदोलन बनाने में विभिन्न सामाजिक संगठनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। विशेष रूप से 'लायन्स क्लब नई दिल्ली अलकनंदा' तथा 'लायन्स इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 321 ए-1' ने इस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। विगत कई दशकों से इन संस्थाओं द्वारा नेत्रदान जागरूकता अभियान, नेत्रदान संकल्प-पत्र भरवाने, नेत्र चिकित्सा शिविरों के आयोजन तथा आई बैंकों के साथ समन्वय स्थापित करने जैसे अनेक रचनात्मक कार्य किए जा रहे हैं। लायन्स इंटरनेशनल का वैश्विक सेवा अभियान 'साइट फर्स्ट' दृष्टि संरक्षण एवं अंधत्व निवारण की दिशा में विश्व का सबसे बड़ा स्वैच्छिक कार्यक्रम माना जाता है। इस अभियान के माध्यम से लाखों लोगों को नेत्र चिकित्सा सेवाएं, मोतियाबिंद ऑपरेशन, दृष्टि परीक्षण तथा नेत्रदान के प्रति जागरूकता प्रदान की गई है।

-ललित गर्ग-

शहर में स्वच्छता के कार्यो को लेकर आयुक्त ने की समीक्षा बैठक

देवास/ राजेन्द्र सिंह पंवार/ दैनिक मालवा हेराल्ड। मंगलवार 9 जून को निगम बैठक हॉल में स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के संबंध में विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ निगमायुक्त दलीप कुमार ने की समीक्षा बैठक। बैठक में स्वच्छ भारत मिशन से जुड़े अधिकारियों, कर्मचारियों एवं सहयोगी संस्थाओं को महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए।

बैठक में आयुक्त ने दिए दिशा निर्देश

शहर में शत प्रतिशत डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण एवं स्त्रोत पर ही कचरे का पृथक्कीकरण सुनिश्चित किया जाए, देर रात में खुले रहने वाले होटल, रेस्टोरेंट, ठेले वालों से गीला-सूखा कचरा पृथक-पृथक लिया जाए, शहर मे स्थित बैकलेनों का सौदर्यिकरण कर उन्हें कचरा मुक्त किया जाए, कचरा पड़ाव स्थल एवं बर्निंग प्वाइंट की नियमित मॉनिटरिंग की जाए, रहवासियों को गीला, सूखा एवं अन्य घरेलु हानिकारक कचरा के संबंध मे जागरूकता लाने हेतु कहा, शासकीय, अशासकीय स्कूलों में स्कुल संस्थापकों से समन्वय कर स्वच्छता के संबंध में जागरूकता गतिविधियां चलाऐं, व्यवसायिक क्षेत्रों में अमानक पॉलिथीन सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध हेतु जागरूकता अभियान चलाएं, सिंगल यूज प्लास्टिक व डिस्पोजल बेचने वालों को चिन्हित कर चालानी कार्रवाई करें, स्थानीय एनजीओ और सामाजिक संस्थाओं से स्वच्छता मिशन के संबंध मे जुड़कर जागरूकता अभियान चलायें, आरआरआर सेंटर पर फौकस रखते हुए रिड्यूस, रीयूज, रीसायकल सेंटर का निरंतर संचालन किया जाए, जन जागरूकता के तहत स्वच्छ वायु पर्यावरण को दृष्टिगत रखते हुए घरों की छत पर बागवानी को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाए, नागरिकों को माय देवास एप डाउनलोड करने के लिए प्रेरित किया जाए, बैठक में निगम के स्वच्छ भारत मिशन नोडल अधिकारी सौरभ त्रिपाठी, स्वच्छ भारत मिशन से विश्वजीत सिंह, विशाल जोशी, अरुण तोमर, दीपक अग्रवाल सहित नगर निगम सहयोगी संस्था ओम साई विजन एवं फीडबैक फाउंडेशन के टीम लीडर, सुपरवाइजर तथा बड़ी संख्या में वार्डो से स्वच्छता सहयोगी की टीम के सदस्य उपस्थित रहे।

बच्चों के सीखने के स्तर में सुधार के लिए शिक्षक सीखी गई बातों का कक्षा में जाकर प्रभावी क्रियान्वयन करें- कलेक्टर

शाजापुर/दैनिक मालवा हेराल्ड। कलेक्टर सुश्री ऋजु बाफना के मार्गदर्शन में जिले में प्रारंभिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के अधिगम स्तर में सुधार तथा निपुण भारत मिशन के लक्ष्यों की प्रभावी प्राप्ति के उद्देश्य से एक दिवसीय एफएलएन उन्मुखीकरण प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में विकासखंड शाजापुर एवं मोहन बड़ोदिया के उन विद्यालयों के कक्षा 1 एवं 2 के शिक्षक शामिल हुए, जिनका प्रदर्शन अपेक्षाकृत कमजोर रहा है।

कलेक्टर सुश्री बाफना ने प्रशिक्षण का निरीक्षण करते हुए शिक्षक संदर्शिका के नियमित उपयोग, मासिक ट्रैकर डेटा की शत-प्रतिशत एवं सटीक प्रविष्टि, कमजोर प्रदर्शन वाले विद्यालयों को विशेष अकादमिक सहयोग प्रदान करने तथा भाषा एवं गणित कॉर्नर को सक्रिय बनाने के निर्देश दिए।

कलेक्टर सुश्री बाफना ने शिक्षकों को निर्देश दिए कि प्रशिक्षण के दौरान उपयोगी बिंदुओं को नोट करें, अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त करें तथा कक्षा में जाकर सीखी गई बातों का प्रभावी क्रियान्वयन करें, जिससे बच्चों के सीखने के स्तर में सुधार हो सके। उन्होंने शिक्षकों को निर्देश दिए कि ट्रैकर में बच्चों का स्तर सही एवं वास्तविक रूप से दर्ज करें, किसी भी प्रकार की गलत जानकारी पाए जाने पर संबंधितों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने शाजापुर एवं मोहन बड़ोदिया विकासखंडों में शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारने तथा शिक्षक संदर्शिका एवं मासिक ट्रैकर के अनुसार गतिविधियों के संचालन को सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

कलेक्टर सुश्री बाफना ने जिला परियोजना समन्वयक को निर्देश दिए कि प्रत्येक दो माह में जिले के सभी अधिकारियों द्वारा विद्यालयों का अवलोकन कराएं। साथ ही ब्लॉक स्तरीय टीमों को निर्देशित किया गया कि वे अपने भ्रमण के दौरान सभी विद्यालयों में ट्रैकर की सही प्रविष्टि सुनिश्चित करें। उन्होंने जिले में आयोजित होने वाली प्रत्येक मासिक समीक्षा बैठक में पांच कमजोर प्रदर्शन वाले विद्यालयों के शिक्षक अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश भी दिए। इस दौरान कलेक्टर सुश्री बाफना ने प्रतिभागियों के साथ पूर्व प्रशिक्षणों के अनुभवों तथा विद्यालय स्तर पर आने वाली चुनौतियों पर भी चर्चा की।

उन्मुखीकरण प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को मिशन अंकुर के विभिन्न घटकों, कक्षा 1 से 3 के निपुण लक्ष्यों, शिक्षक संदर्शिका, वर्कबुक, जादुई पिटारा, गणित संदर्शिका तथा शिक्षण-अधिगम सामग्री (टीएलएम) के प्रभावी उपयोग पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया। साथ ही विद्यालयों में क्रियाशील रीडिंग कॉर्नर एवं समृद्ध शिक्षण वातावरण विकसित करने पर विशेष बल दिया गया, जिससे बच्चों में भाषा एवं गणितीय दक्षताओं का विकास सुनिश्चित किया जा सके। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों ने समूह गतिविधियों एवं प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुनिश्चित करने के लिए अपनी कार्ययोजनाएँ साझा कीं।

उल्लेखनीय हैं कि यह उन्मुखीकरण प्रशिक्षण विकासखंड शाजापुर एवं मोहन बड़ोदिया के प्रतिभागियों के लिए 9 जून को डाइट शाजापुर में तथा विकासखंड कालापीपल एवं शुजालपुर के प्रतिभागियों के लिए 10 जून को शुजालपुर केंद्र पर आयोजित किया गया।

801 अनानास, 51 किलों संतरों से हुआ श्री खेड़ापति दरबार का श्रृंगार

देवास/ राजेन्द्र सिंह पंवार/ दैनिक मालवा हेराल्ड। महात्मा गांधी मार्ग स्थित श्री खेड़ापति मारुति मंदिर में मंगलवार को बड़े मंगलवार के अवसर पर भगवान हनुमान का 801 अनानास, 51 किलों संतरों एवं विभिन्न प्राकृतिक सजावटी सामग्री से भव्य और आकर्षक श्रृंगार किया गया। जिसने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। भगवान के इस अनूठे स्वरूप के दर्शन करने के लिए सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचने लगे। मंदिर के पुजारी पंडित दर्शन उपाध्याय ने बताया कि ज्येष्ठ माह के बड़े मंगलवारों के उपलक्ष्य में मंदिर में विशेष धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में भगवान श्री खेड़ापति मारुति का 801 अजनास व संतरों से विशेष श्रृंगार किया गया। भगवान हनुमान का यह मनोहारी और अनूठा स्वरूप श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना रहा। दर्शन के लिए सुबह से लेकर देर शाम तक भक्तों का आना-जाना लगा रहा। भगवान के इस विशेष श्रृंगार को तैयार करने के लिए उज्जैन से सहायक कलाकारों की एक टीम देवास पहुंची थी। कलाकारों ने कई घंटों की मेहनत और रचनात्मकता के साथ इस श्रृंगार को आकार दिया। करीब 8 से 10 कलाकारों की टीम ने श्री खेडापति सरकार के दरबार का भव्य स्वरूप तैयार किया। देर शाम तक भक्तों की आवाजाही जारी रही और मंदिर परिसर जय श्री राम एवं जय बजरंगबली के जयघोषों से गूंजता रहा।

आंगनवाडी केन्द्रों पर मनाया मंगल दिवस

शाजापुर/दैनिक मालवा हेराल्ड। महिला एवं बाल विकास द्वारा जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री संजय त्रिपाठी व सहायक संचालक सुश्री नीलम चौहान के मार्गदर्शन में आज जिले के आंगनवाडी केन्द्रों पर मंगल दिवस के अवसर पर गोदभराई गतिविधि का आयोजन सेक्टर पनवाड़ी, सेक्टर सुन्दरसी, सेक्टर मोहमद खेडा, सेक्टर पोचानेर, सेक्टर दुपाडा, सेक्टर बोलाई में किया गया। उक्त गतिविधि के दौरान महिलाओं को परियोजना अधिकारी एवं पर्यवेक्षकों द्वारा बालिकाओ की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण संबंधी विषयों पर विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही बालिकाओ एवं महिलाओं को नियमिति स्वास्थ्य जाँच करवाने व आयरन केल्शियम के बारे में बताया एवं शिशु देखभाल की जानकारी दी गई। इस अवसर पर केन्द्र पर पंजीकृत हितग्राहियों को रेडी टू ईट का वितरण किया गया।

मानकुंड में आबकारी का बड़ा छापाः 56 बल्क लीटर अवैध शराब जब्त, आरोपी गिरफ्तार

देवास/ राजेन्द्र सिंह पंवार/ दैनिक मालवा हेराल्ड। कलेक्टर ऋषुराज सिंह के निर्देशन तथा सहायक आबकारी आयुक्त मनीष खरे के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा के निर्माण, संग्रहण, विक्रय एवं परिवहन के विरुद्ध लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में सोमवार को ग्राम मानकुंड में आबकारी टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक मकान से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया।

आबकारी विभाग को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम मानकुंड, तहसील हाटपिपल्या स्थित एक मकान में अवैध रूप से शराब का भंडारण किया गया है। सूचना मिलते ही आबकारी टीम मौके पर पहुंची और गवाहों की मौजूदगी में मकान की तलाशी ली। तलाशी के दौरान कमरे से 173 पाव देशी प्लेन मदिरा, 34 कैन बीयर तथा 11 बोतल व्हिस्की बरामद हुई।

जब्त देशी एवं विदेशी मदिरा की कुल मात्रा 56.3 बल्क लीटर पाई गई। अवैध रूप से संग्रहित शराब के संबंध में मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क) एवं 34(2) के तहत प्रकरण दर्ज कर मकान मालिक को गिरफ्तार किया गया। जब्त सामग्री का अनुमानित बाजार मूल्य करीब 29 हजार 711 रुपये बताया गया है।

कार्रवाई में आबकारी उपनिरीक्षक प्रेम यादव, मुख्य आरक्षक राजाराम रायकवार, आरक्षक अरविंद जिनवाल, निकिता परमार, निहाल खत्री तथा सैनिक किशोर सिसोदिया की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ अभियान आगे भी इसी सख्ती के साथ जारी रहेगा।

अमलतास इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प

देवास/ राजेन्द्र सिंह पंवार/ दैनिक मालवा हेराल्ड। अमलतास इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में आज विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन बेहद उत्साहपूर्ण, वैचारिक एवं गरिमामय वातावरण में किया गया। यह कार्यक्रम माननीय फाउंडर चेयरमैन (अमलतास ग्रुप) श्री सुरेश सिंह भदौरिया एवं माननीय चेयरमैन श्री मयंकराज सिंह भदौरिया के शुभाशीष और कुशल मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य भावी चिकित्सकों व युवाओं को प्रकृति के प्रति उनके कर्तव्यों, पर्यावरण संतुलन एवं सतत विकास के प्रति जागरूक करना था।

कार्यक्रम में संस्थान के डायरेक्टर डॉ. अभिजीत तायडे, जनरल मैनेजर श्री मनीष शर्मा एवं प्राचार्या डॉ. अनीता घोडके सहित सभी शिक्षकगण तथा छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने अपने प्रेरणादायक विचारों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण और आयुर्वेद व प्रकृति के अटूट संबंध पर प्रकाश डालते हुए सभी को पर्यावरण मित्र जीवनशैली अपनाने का संदेश दिया।

कार्यक्रम के दौरान संस्थान के विद्यार्थियों ने पर्यावरण की वर्तमान चुनौतियों और उनके समाधान पर अपने प्रभावशाली भाषण और विचार प्रस्तुत किए, जिन्हें उपस्थित श्रोताओं द्वारा खूब सराहा गया।

24 बैच के विद्यार्थियों ने ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण के खतरों और उनसे बचाव के व्यावहारिक उपायों पर अपने सारगर्भित विचार व्यक्त किए।

25 बैच के विद्यार्थियों ने आयुर्वेद में वर्णित लोक-पुरुष साम्य सिद्धांत, औषधीय पौधों के संरक्षण और हमारी सामाजिक भूमिका पर अपना प्रभावशाली वक्तव्य दिया।

इस संपूर्ण कार्यक्रम का सफल समन्वय डॉ. निवेदिता रावत द्वारा किया गया, जिनके कुशल मार्गदर्शन और प्रबंधन में पूरा कार्यक्रम सुव्यवस्थित व सुचारू रूप से संपन्न हुआ। कार्यक्रम के अंत में डॉ. निवेदिता रावत ने उपस्थित सभी अतिथियों, शिक्षकों और विद्यार्थियों का हृदय से आभार व्यक्त किया।

अतिवृष्टि एवं बाढ नियंत्रण कक्ष की स्थापना

शाजापुर/दैनिक मालवा हेराल्ड। कलेक्टर सुश्री ऋजु बाफना द्वारा शाजापुर जिले में अतिवृष्टि एवं बाढ नियंत्रण कक्ष की स्थापना 15 जून 2026 से 15 अक्टूबर 2026 तक कलेक्टर कार्यालय शाजापुर के जिला नियंत्रण कक्ष क्रमांक 40 में की गई है। कन्ट्रोल रूम के प्रभारी तहसीलदार भू-संसाधन प्रबंधन शाजापुर को बनाया गया हैं, जिनका मोबाईल नं. 9753424068 है। कन्ट्रोल रूम के कक्ष का दूरभाष क्रमांक 07364-227202 हैं। जो 24 घण्टे खुला रहेगा। कलेक्टर सुश्री बाफना ने अतिवृष्टि एवं बाढ नियंत्रण कक्ष के सुव्यवस्थित संचालन के लिए 15 जून से 15 अक्टूबर 2026 तक कर्मचारियों की ड्यूटी निर्धारित समय अनुसार लगाई हैं। जारी आदेश के तहत प्रातः 6.00 से दोपहर 2.00 बजे तक प्रथम शिफ्ट मं श्री अजय छजलाने मोनं. 7828306623, श्री अशोक राणावत मोनं. 7000949466 एवं श्री मुकेश राठौर मोनं. 9926576564 की ड्यूटी लगाई गयी हैं। इसी प्रकार दोपहर 2.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक द्वितीय शिफ्ट में श्री कैलाश शर्मा मोनं. 9424044103, श्री विजय पुष्पद मोनं. 6262403956 एवं श्री विकाश पारछे मोनं. 9165034484 की ड्यूटी लगाई गयी हैं। रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक तृतीय शिफ्ट में श्री एजजा अहमद कुरैशी मोनं. 9893491555, श्री विशाल पारछे मोनं. 6261520233 एवं श्री अजय सिमरैया मोनं. 7509084614 की ड्यूटी लगाई गयी हैं।

देवास जिले ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर लक्ष्य से अधिक धनराशि जुटाई !

देवास/ राजेन्द्र सिंह पंवार/ दैनिक मालवा हेराल्ड। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस (2024-25) में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए लक्ष्य से अधिक धनराशि एकत्रित की है। सशस्त्र सेना झण्डा दिवस वर्ष 2024-2025 में देवास जिले ने मध्यप्रदेश शासन द्वारा दी गई लक्ष्य राशि 9,05,100 रुपए से अधिक राशि 10,71,100 रुपए सैनिकों के कल्याण के लिए एकत्रित की है जो कि लक्ष्य राशि का 118 प्रतिशत है। यह राशि पूर्व सैनिकों, वीर नारियों, पूर्व सैनिकों की विधवाओं एवं उनके आश्रितों के कल्याण एवं पुनर्वास में संचालनालय सैनिक कल्याण म.प्र.भोपाल द्वारा चलाई जा रही कई कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उपयोग में ली जाती है।

इस महत्वपूर्ण उपलब्धि एवं योगदान के लिए राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 2026 को राजभवन में आयोजित विशेष सम्मान समारोह में कलेक्टर श्री ऋषुराज सिंह को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया। कलेक्टर देवास की ओर से जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कमांडर नगेश चन्द्र मालवीय (से.नि.) ने ग्रहण किया। उक्त प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कमांडर नगेश चन्द्र मालवीय (से.नि.) ने मंगलवार को समयसीमा बैठक के दौरान कलेक्टर श्री ऋषुराज सिंह को भेंट किया। इस दौरान जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ने जिले के समस्त दानदाताओं, अधिकारीगण एवं कलेक्टर का सशस्त्र सेना झण्डा दिवस में भरपूर सहयोग के लिए आभार एवं कृतज्ञता प्रगट की।

वर्षाकाल से पूर्व प्राप्त सभी सीमांकन के प्रकरणों का निराकरण करें - कलेक्टर

शाजापुर/दैनिक मालवा हेराल्ड। कलेक्टर सुश्री बाफना ने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिये कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत दी जा रही सेवाओं जैसे- सीमांकन, बटवारा, नामांतरण में प्राप्त लंबित प्रकरणों का निराकरण निर्धारित समयावधि में करें। कलेक्टर सुश्री बाफना ने राजस्व अधिकारियो को निर्देश दिये कि वर्षाकाल से पूर्व प्राप्त सभी सीमांकन के प्रकरणों का निराकरण करें। उन्होंने निर्देश दिये कि सीमांकन का कोई भी प्रकरण लंबित नहीं रखें। निर्धारित समयावधि में उक्त प्रकरण का निराकरण नहीं होने पर संबंधित राजस्व अधिकारी पर 250 रूपये के मान से अर्थदण्ड लगाने की कार्यवाही की जायेगी।

साथ ही कलेक्टर ने सभी राजस्व अधिकारियों को नियमित रूप से अपने-अपने क्षेत्र के उर्वरक केन्द्रों का निरीक्षण करने के भी निर्देश दिये।

कलेक्टर सुश्री बाफना ने जिला पंचायत सीईओ, जनपद पंचायतों के सीईओ एवं नगरीय निकायों के सीएमओ को जलकर, संपत्ति कर सहित अन्य करों की वसूली में तेजी लाने, जल गंगा संवर्धन अभियान के कार्यों में प्रगति लाने, रूफ हार्वेस्टिंग सिस्टम के लक्ष्यों की पूर्ति करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर सुश्री बाफना ने सभी नगरीय निकायों के सीएमओं एवं जनपद पंचायतों के सीईओ को निर्देश दिये हैं कि समग्र आईडी का सत्यापन कराएं तथा ऐसे व्यक्ति जो शाजापुर में निवासरत नहीं हैं, उनके नाम समग्र आईडी से विलोपित करें। उन्होंने सभी नगरीय निकायों के सीएमओ को निर्देश दिये कि विशेष अभियान चलाकर पात्र हितग्राहियों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ प्रदान करें। साथ ही उन्होंने पीएम आवास योजना 2.0 (शहरी) अंतर्गत प्राप्त लक्ष्यों की पूर्ति कराने तथा जीर्ण-शीर्ण भवनों को चिन्हांकन कर डिस्मेंटल कराने व सभी के निर्देश भी दिये।

कलेक्टर सुश्री बाफना ने सभी नगरीय निकायों के सीएमओं एवं जनपद पंचायतों के सीईओ को निर्देश दिये हैं कि समग्र आईडी का सत्यापन कराएं तथा ऐसे व्यक्ति जो शाजापुर में निवासरत नहीं हैं, उनके नाम समग्र आईडी से विलोपित करें।

कलेक्टर सुश्री बाफना ने जल निगम, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारी को निर्देश दिये कि जहां कहीं भी रेस्टोरेशन का कार्य शेष हैं, उसे वर्षाकाल को देखते हुए शीघ्र पूर्ण कराएं, जिससे अवागमन में नागरिकों को परेशानी न हो। साथ ही उन्होंने सभी जनपद पंचायत सीईओ, नगरीय निकाय के सीएमओ को रेस्टोरेशन किये जाने वाले कार्यों की सूची तैयार कर उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिये।

कलेक्टर सुश्री बाफना ने सहकारिता विभाग की समीक्षा कर धारा-85 के प्रकरणों में प्रगति लाने के निर्देश दिये।

हजारों श्रद्धालुओं के आगमन से पहले इटावा की सड़क व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग

सड़क चौड़ीकरण कार्य और भारी वाहनों से बढ़ी परेशानी पर शिवसेना युवासेना ने उठाई आवाज

देवास/ राजेन्द्र सिंह पंवार/ दैनिक मालवा हेराल्ड। नगर इटावा में 17 जून 2026 को आयोजित होने वाले विशाल गांव गैर माता पूजन एवं धार्मिक आयोजन को लेकर शिवसेना युवासेना मध्यप्रदेश के राज्य उप प्रमुख रोहित शर्मा एवं देवास जिला अध्यक्ष सुनील वर्मा के नेतृत्व में कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक देवास को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में आयोजन के दौरान सुरक्षा, यातायात, पार्किंग, चिकित्सा, पेयजल, साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था एवं आपदा प्रबंधन सहित विभिन्न आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने की मांग की गई। नगर अध्यक्ष शिवम चतुर्वेदी ने बताया कि गांव गैर माता पूजन इटावा क्षेत्र का प्रमुख धार्मिक एवं आस्था का आयोजन है, जो 12 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है। इस वर्ष आयोजित होने वाले इस विशेष धार्मिक आयोजन में लगभग 50 हजार से अधिक श्रद्धालुओं एवं अतिथियों के पहुंचने की संभावना है। मुख्य पूजन कार्यक्रम पीपल चौक स्थित शीतला माता मंदिर में संपन्न होगा, जबकि नगर इटावा के अन्य शीतला माता मंदिरों एवं पूजन स्थलों पर भी विधि-विधान के साथ पूजन-अर्चन एवं धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ऐसे में प्रशासन द्वारा सुरक्षा, यातायात एवं मूलभूत सुविधाओं की समुचित व्यवस्था किया जाना अत्यंत आवश्यक है। ज्ञापन में विशेष रूप से इटावा क्षेत्र में चल रहे सड़क चौड़ीकरण एवं निर्माण कार्य, संभावित वर्षा के कारण मार्गों पर कीचड़ एवं जलभराव की स्थिति तथा रेलवे ब्रिज क्षेत्र से भारी वाहनों के लगातार आवागमन से उत्पन्न हो रही समस्याओं का उल्लेख किया गया। संगठन ने कहा कि यदि समय रहते आवश्यक व्यवस्थाएं नहीं की गईं तो आयोजन में आने वाले हजारों श्रद्धालुओं को आवागमन में गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आयोजन स्थल पर पर्याप्त पुलिस बल, यातायात पुलिस, पार्किंग व्यवस्था, एम्बुलेंस, चिकित्सा दल, अग्निशमन वाहन, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था एवं साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है। संगठन ने प्रशासन से मांग की है कि आयोजन से पूर्व संबंधित विभागों द्वारा स्थल एवं मार्गों का निरीक्षण कर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूर्ण की जाएं, जिससे कार्यक्रम शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित रूप से संपन्न हो सके। ज्ञापन सौंपने के दौरान शिवसेना युवासेना के जिला प्रभारी विजय जायसवाल, श्रवण दादा, जिला उपाध्यक्ष शेर सिंह परमार, नगर अध्यक्ष शिवम चतुर्वेदी, शिवसेना नेता लखन टिपानिया, संजू भाटी, विनोद कुमावत, आशु पथरी, राकेश लाल, अमित त्रिवेदी एवं मोहित शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

जिला टास्क फोर्स समिति की बैठक संपन्न

शाजापुर/दैनिक मालवा हेराल्ड। विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए कलेक्टर सुश्री ऋजु बाफना की अध्यक्षता में आज जिला स्तरीय टास्क फोर्स (डीटीएफ) समि?ति की बैठक आयोजित की गई।

कलेक्टर सुश्री बाफना ने निर्देश दिये कि जिले की प्रत्येक शैक्षणिक व कोचिंग संस्थानों में मेटर की नियुक्ति करें। साथ ही हर शैक्षणिक व कोचिंग संस्थानों में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगे हो, यह सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिये कि आई गोट कर्मयोगी प्रशिक्षण में उपलब्ध विभिन्न मोटिवेशनल पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करें और इसके लिए समस्त शैक्षणिक संस्थानों में प्रचार-प्रसार भी कराएं।

कलेक्टर सुश्री बाफना ने बैठक के दौरान निर्देश दिये कि समस्त शैक्षणिक संस्थानों में महिला सेल, चाईल्ड लाईन (1098), उमंग किशोर टोल फ्री नंबर-14425, टेलिमानस नंबर-14416 व डायल-112 नंबर के संस्थानों से संबंधित प्राचार्यो एवं नोडल अधिकारियों के नाम व मोबाईल नंबर प्रदर्शित कराएं। साथ ही समस्त शिक्षण संस्थानों में समय-समय पर पालक शिक्षक बैठकें भी आयोजित करें। कलेक्टर सुश्री बाफना ने एनटीएफ द्वारा समय-समय पर भेजी गई निर्धारित लिंक के माध्यम से विद्यार्थियो अभिभावकों व समस्त स्टाफ सदस्यों की ऑनलाईन सर्वे में सहभागिता कराने के भी निर्देश दिये।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस बीकेएसएन शासकीय महाविद्यालय शाजापुर के प्राचार्य डॉ. एसके तिवारी, डॉ. वीपी मीणा, नगर पालिका सीएमओ श्री भूपेन्द्र दीक्षित, जनजातीय कार्य विभाग जिला संयोजक श्रीमती मीना मण्डलोई, महिला एवं बाल विकास जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री संजय त्रिपाठी, जिला शिक्षा अधिकारी, शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, श्रम अधिकारी सहित समिति सदस्य एवं अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

आदर्श रोड निर्माण में बड़ी लापरवाही

ठेकेदार आकाश रावत के रसूख के आगे बौने साबित हो रहे नियम, सुरक्षा किट के बिना 25 फीट से गिरा कर्मचारी, हालत गंभीर

बदनावर/ मनीष शर्मा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। बड़ी चौपाटी से बड़नगर-उज्जैन रोड को जोड़ने वाले आदर्श रोड के निर्माण कार्य और पोल शिफ्टिंग के दौरान सुरक्षा मानकों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सोमवार शाम को खुदाई के दौरान 11 केवी का बिजली खंभा अचानक गिरने के बाद भी सबक नहीं लिया गया। इसी कार्य के दौरान कल एक और बड़ा हादसा हो गया, जहां एक कर्मचारी लगभग 25 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर गया। सुरक्षा उपकरणों के अभाव में इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद तुरंत बड़नगर रेफर किया गया है, जहां उसकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है।

स्थानीय सूत्रों और प्रत्यक्षदर्शियों से मिली जानकारी के अनुसार, बिजली ठेकेदार आकाश रावत द्वारा साइट पर काम कर रहे कर्मचारियों को बुनियादी सुरक्षा किट तक उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। जान जोखिम में डालकर ऊंचाई पर काम कर रहे इन लाइनमैनों और मजदूरों को न तो हेलमेट दिए गए हैं, न ही सेफ्टी बेल्ट, दस्ताने या सेफ्टी जूते उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सुरक्षा मानकों की इस घोर अनदेखी के कारण लगातार हादसे हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि ठेकेदार आकाश रावत का रसूखदार होने के कारण विभाग के उच्च अधिकारियों से गहरी पैठ है। इसी प्रशासनिक और राजनैतिक संरक्षण के बल पर ठेकेदार अपनी मनमर्जी से काम कर रहा है। पोल शिफ्टिंग के इस महत्वपूर्ण कार्य में मानकों को ताक पर रखकर अत्यंत अमानक और हल्की गुणवत्ता वाली केबल डाली गई है। इस घटिया निर्माण और हल्की केबलिंग का विद्युत मंडल पहले भी लिखित और मौखिक रूप से कड़ा विरोध कर चुका है, परंतु ठेकेदार के रसूख के आगे बिजली कंपनी के अधिकारी भी बौने साबित हो रहे हैं।

इस पूरे मामले और लापरवाही को लेकर जब हमारे संवाददाता ने सच्चाई जानने और उनका पक्ष लेने के लिए ठेकेदार आकाश रावत से उनके मोबाइल फोन पर चर्चा करना चाहा, तो उन्होंने इस विषय पर बात करने से साफ मना कर दिया। पहली बार बात काटने के बाद उन्होंने दोबारा फोन उठाना भी मुनासिब नहीं समझा, जो उनके अड़ियल रवैये और जवाबदेही से भागने की प्रवृत्ति को साफ दर्शाता है।

कानूनी विशेषज्ञों और पुलिस विभाग के नियमों के अनुसार, कर्मचारियों की सुरक्षा में इस तरह की जानलेवा लापरवाही बरतने और अमानक सामग्री का उपयोग करने पर ठेकेदार आकाश रावत पर भारतीय न्याय संहिता के तहत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हो सकता है। जिसके तहत कारावास और भारी आर्थिक जुर्माने का प्रावधान है।

विद्युत मंडल के विरोध के बावजूद हल्की केबल डालना सरकारी धन के दुरुपयोग और जनता की जान से खिलवाड़ की श्रेणी में आता है। इसके तहत लोक निर्माण विभाग ठेकेदार को टेंडर निरस्त कर उसे ब्लैकलिस्ट करना चाहिए।

राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका, मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज

नीमच/ सतीश सैन/ दैनिक मालवा हेराल्ड। मध्यप्रदेश की तीसरी राज्यसभा सीट के चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा खारिज कर दिया गया है। भाजपा की ओर से नामांकन पर आपत्ति दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद जांच के उपरांत यह निर्णय लिया गया।

भाजपा का आरोप था कि मीनाक्षी नटराजन ने हैदराबाद की एक अदालत में लंबित मामले की जानकारी नामांकन पत्र में प्रस्तुत नहीं की। इस संबंध में रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था। जवाब और दस्तावेजों की समीक्षा के बाद नामांकन निरस्त कर दिया गया।

हालांकि कांग्रेस ने इस फैसले पर कड़ा विरोध जताया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भाजपा के आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए कहा कि मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। उन्होंने दावा किया कि उन्हें केवल एक न्यायालयीन नोटिस प्राप्त हुआ था, जिसे गलत तरीके से विवाद का विषय बनाया गया है।

नामांकन पत्रों की जांच के दौरान विधानसभा परिसर में राजनीतिक तनाव भी देखने को मिला। कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बीच तीखी बहस, नारेबाजी और हंगामे की स्थिति बनी रही। इस दौरान कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे और विक्रांत भूरिया ने रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में प्रवेश करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस एवं विधानसभा सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोक दिया।

इधर राज्यसभा चुनाव को लेकर बढ़ी राजनीतिक गतिविधियों के बीच कांग्रेस ने अपने विधायकों को बेंगलुरु भेजने का फैसला किया है। जानकारी के अनुसार कांग्रेस की चार्टर्ड फ्लाइट में 38 विधायक सहित लगभग 75 लोग बेंगलुरु रवाना हुए हैं, जबकि शेष विधायकों को दूसरी उड़ान से भेजने की तैयारी की गई है।

फ्लाइट को लेकर भी विवाद सामने आया। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि भोपाल एयरपोर्ट पर उनकी चार्टर्ड फ्लाइट को उड़ान की अनुमति देने में अनावश्यक देरी की गई। वरिष्ठ कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने आरोप लगाया कि सरकार के दबाव में विमान को रोका गया, जबकि एयरपोर्ट प्रशासन ने तकनीकी और अनुमति संबंधी कारणों का हवाला दिया।

मध्यप्रदेश की तीसरी राज्यसभा सीट को लेकर अब राजनीतिक संघर्ष और तेज हो गया है। एक ओर कांग्रेस नामांकन निरस्त किए जाने के फैसले को चुनौती देने की तैयारी में है, वहीं दूसरी ओर विधायकों की निगरानी और राजनीतिक जोड़-तोड़ की आशंकाओं के बीच सियासी माहौल बेहद गर्म हो गया है।

जिले में 12, 15 और 16 जून को आयोजित होंगे जनकल्याण शिविर

सीहोर/ दैनिक मालवा हेराल्ड। कलेक्टर श्री बालागुरू के. के निर्देशानुसार जिले की सभी तहसीलों एवं जनपदों में 12, 15 और 16 को जनकल्याण शिविरों का आयोजन किया जाएगा। जिले के सभी विकासखंडों एवं नगरीय निकाय क्षेत्रों में आयोजित होने वाले इन शिविरों का उद्देश्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से वंचित पात्र हितग्राहियों तक लाभ पहुंचाना तथा उनकी समस्याओं का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करना है। जनकल्याण शिविरों में विभिन्न विभागों की योजनाओं से संबंधित पात्र हितग्राहियों की पहचान कर उनका पंजीयन किया जाएगा तथा पात्रतानुसार योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा। शिविरों में शासन की प्रमुख हितग्राहीमूलक योजनाओं के साथ-साथ स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत व्यक्तिगत एवं पारिवारिक शौचालयों के लिए भी आवेदन प्राप्त कर उनका निराकरण किया जाएगा। शिविरों में सीएम हेल्पलाइन, लोक सेवा गारंटी अधिनियम, राजस्व प्रकरणों तथा अन्य जन शिकायतों के निराकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। विभिन्न विभागों द्वारा सूचना एवं सहायता केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जहां नागरिकों को योजनाओं की जानकारी, आवेदन, पंजीयन तथा सेवा वितरण की सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएंगी। कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शिविरों में प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाए तथा पात्र हितग्राहियों को अधिकतम संख्या में शासन की योजनाओं का लाभ दिलाया जाए। उन्होंने जनप्रतिनिधियों एवं आमजन की सहभागिता के साथ शिविरों के व्यापक प्रचार-प्रसार के भी निर्देश दिए हैं, ताकि जिले का कोई भी पात्र नागरिक शासन की योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे।

समान नागरिक संहिता से सामाजिक समरसता और समानता को मिलेगा बल - प्रो. गोपाल शर्मा

सीहोर/ दैनिक मालवा हेराल्ड। समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के अध्ययन एवं परीक्षण के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता समिति के सदस्य प्रो. गोपाल शर्मा ने की। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों, सामाजिक, धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों, शांति समिति के सदस्यों, पत्रकारों एवं प्रबुद्ध नागरिकों ने यूसीसी पर अपने सुझाव दिये।

बैठक में समिति के सदस्य प्रो. गोपाल शर्मा ने कहा कि समान नागरिक संहिता से समाज में सद्भाव एवं सौहार्द की स्थापना होगी तथा पारिवारिक और सामाजिक संबंधों में अनावश्यक तनाव की स्थिति नहीं बनेगी। उन्होंने कहा कि यह एक गंभीर एवं महत्वपूर्ण विषय है, जिस पर प्रदेश सरकार नागरिकों की राय लेकर व्यापक अध्ययन कर रही है। यूसीसी लागू होने से महिलाओं, बच्चों एवं सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित होगा तथा विवाह, विवाह विच्छेद, उत्तराधिकार एवं अन्य पारिवारिक विषयों में समानता स्थापित होगी।

प्रो. शर्मा ने कहा कि पुरुष और महिलाओं के अधिकारों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रहेगा तथा दत्तक पुत्र को भी जेनेटिक पुत्र के समान अधिकार प्राप्त होंगे। उन्होंने बताया कि वर्तमान में विभिन्न धर्म एवं समुदायों के लिए अलग-अलग पारिवारिक कानून प्रचलित हैं। विवाह, विवाह विच्छेद, भरण-पोषण, उत्तराधिकार तथा लिव-इन संबंध जैसे विषय समान नागरिक संहिता की परिधि में आते हैं। प्रो. शर्मा ने बताया कि प्रदेश सरकार यूसीसी के संबंध में नागरिकों के विचार एवं सुझाव प्राप्त करने के लिए ह्वष्ष्-द्वश्च-द्द्श1-द्वठ्ठ पोर्टल संचालित कर रही है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे पोर्टल पर अपने सुझाव दर्ज कर इस महत्वपूर्ण विषय पर चल रहे जन-विमर्श में सहभागी बनें।

बैठक के दौरान यूसीसी से जुड़े सामाजिक, विधिक एवं प्रशासनिक पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। उपस्थित नागरिकों ने विभिन्न राज्यों में लागू व्यवस्थाओं, सामाजिक समरसता, महिला अधिकारों तथा संवैधानिक प्रावधानों से जुड़े महत्वपूर्ण सुझाव समिति के समक्ष रखे।

सरकारी नियमों के चक्रव्यूह में घिरे व्यापारी

अधिकारियों की फाइल-धोंस के आगे आखिरकार डाले हथियार

बदनावर/ मनीष शर्मा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। नगर में पिछले दो दिनों से चल रहा सिंहासन बटल यानी व्यापारियों और सरकारी नुमाइंदों के बीच का महामुकाबला आखिरकार अपने तार्किक और पारंपरिक अंत तक पहुंच ही गया। जनता पॉपकॉर्न लेकर बैठी थी कि देखें इस बार भ्रष्टाचार की सरकारी तोप जीतती है या मेहनतकश व्यापारी ढाल। लेकिन अंततः वही हुआ जो आदि काल से होता आ रहा है– सरकारी दांवपेच की धोंस और फाइलों के मकड़जाल के आगे बेचारे व्यापारियों को अपने हथियार डालने ही पड़े। व्यापारियों ने समझदारी दिखाई और तय किया कि व्यापार करना है, तो मगरमच्छ से बैर कैसा।

बाज़ार में चर्चा गर्म है कि हमारे कुछ चुनिंदा ईमानदार अधिकारी व्यापारियों का शिकार करने में इतने माहिर हैं कि वे अच्छे-अच्छे वाइल्डलाइफ एक्सपर्ट्स को भी फेल कर दें। जब तक नीचे से चढ़ावा और सुविधा-शुल्क की पावन गंगा बिना किसी रुकावट के बहती रहती है, तब तक सब कुछ नियमानुसार और पवित्र लगता है। उस समय न तो कोई नियम टूटता है, न कोई फाइल अटकती है और न ही किसी को अतिक्रमण दिखाई देता है।

लेकिन, जैसे ही किसी सिरफिरे व्यापारी ने इस अघोषित टैक्स को देने से मना किया या आवाज़ उठाई, बस उसी शुभ दिन से अधिकारियों की तीसरी आँख खुल जाती है। रातों-रात सारे कागजात अवैध हो जाते हैं, दस्तावेजों में छिपे हुए कीड़े बाहर आ जाते हैं और सालों पुरानी दुकानें नियम विरुद्ध लगने लगती हैं।

सूत्रों की मानें तो कल इन चतुर अधिकारियों ने अपनी कुर्सी और कलेक्शन को बचाने के लिए एक नया दांव खेला। उन्होंने ऊपर बैठे वरिष्ठ अधिकारियों के कानों में ऐसी मंत्रदीक्षा फूंकी और कागजों का ऐसा मायाजाल बुना कि बड़े साहब भी हक्के-बक्के रह गए। व्यापारियों को सीधे-सीधे यह समझा दिया गया कि अगर रोज़-रोज़ दुकानों पर नए-नए नियमों के छापे, लाइसेंस रद्द होने की धमकियाँ और अदालती चक्करों से बचना है, तो चुपचाप सिस्टम के आगे नतमस्तक हो जाओ। व्यापारी भी ठहरे दूरदर्शी, उन्होंने सोचा कि रोज-रोज सरकारी बाबू के कोपभाजन का शिकार बनने से बेहतर है कि थोड़ा पीछे हट लिया जाए। आखिर पेट पालना है, कोर्ट-कचहरी के चक्कर नहीं काटने।

इस पूरे घटनाक्रम से एक बात तो साफ हो गई है कि इस देश में नियम जनता की सुविधा के लिए कम और अधिकारियों की अतिरिक्त कमाई के लिए ज्यादा बनाए जाते हैं। अब आने वाले दिनों में भी क्या होगा, यह सबको पता है। कागजों पर नियम जीतेंगे, फाइलों पर दस्तखत होंगे, और पर्दे के पीछे वही पुराना खेल फिर से शुरू हो जाएगा।

व्यापारियों ने हथियार डाल दिए हैं, ईमानदार अधिकारी अपनी कागजी जीत पर मूंछों पर ताव दे रहा है, और आम जनता इस अद्भुत सरकारी सर्कस को देखकर तालियां बजा रही है।

स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए मोहित पांचाल ने कलेक्टर को कराया अवगत, मिला आश्वासन

बदनावर/ मनीष शर्मा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। जनहित के मुद्दों को लगातार प्रशासन के समक्ष मजबूती से उठाने वाले भाजपा खेल प्रकोष्ठ जिला धार के सह-संयोजक एवं श्री राजमाता विजयाराजे सिंधिया फाउंडेशन (म.प्र.) के प्रदेश महामंत्री मोहित कुमार पांचाल ने आज बदनावर सिविल अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की मांग को लेकर धार कलेक्टर राजीव रंजन मीणा तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अनीता सिंघल से भेंट की।

भेंट के दौरान मोहित कुमार पांचाल ने बदनावर क्षेत्र की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से दोनों अधिकारियों को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि बदनावर तेजी से विकसित हो रहा औद्योगिक एवं व्यावसायिक केंद्र है, जहां हजारों श्रमिक, कर्मचारी एवं उनके परिवार निवास करते हैं, लेकिन क्षेत्र की स्वास्थ्य सुविधाएं वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हैं। इसके कारण आम नागरिकों को उपचार, दवाइयों एवं जांच सुविधाओं के लिए विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने अधिकारियों को अवगत कराया कि अस्पताल में कई आवश्यक दवाइयां, इंजेक्शन एवं जांच सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं। साथ ही कई स्वास्थ्य उपकरण एवं मशीनें लंबे समय से बंद पड़ी हैं, जिसके कारण मरीजों को निजी अस्पतालों एवं लैबों का सहारा लेना पड़ता है। इसका सीधा आर्थिक भार गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों पर पड़ रहा है। पांचाल ने मांग की कि बदनावर सिविल अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ एवं अन्य आवश्यक कर्मचारियों की पर्याप्त नियुक्ति की जाए तथा सभी जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं शीघ्र उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधा पर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए। पांचाल ने कहा कि जनप्रतिनिधि एवं सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते वे जनता के सुख-दुख को अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। अस्पतालों में उपचार के अभाव में जब कोई गरीब परिवार परेशान होता है, तो उसकी पीड़ा केवल उस परिवार की नहीं, बल्कि पूरे समाज की पीड़ा होती है। बदनावर की माताओं, बहनों, बुजुर्गों, मजदूरों एवं जरूरतमंद परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना उनका नैतिक दायित्व है।

उन्होंने कहा कि जनता के विश्वास और आशीर्वाद से वे निरंतर जनहित के मुद्दों को शासन-प्रशासन के समक्ष मजबूती से उठाते रहेंगे, ताकि क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक को सम्मानजनक एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हो सकें। उन्होंने कहा कि राजनीति उनके लिए केवल पद प्राप्ति का माध्यम नहीं, बल्कि जनसेवा का संकल्प है और बदनावर की जनता के हितों की रक्षा के लिए वे हर स्तर पर प्रयास एवं संघर्ष करते रहेंगे।

उन्होंने यह भी कहा कि जनता की समस्याओं को लेकर वे निरंतर प्रशासन एवं शासन स्तर पर आवाज उठाते रहेंगे तथा बदनावर क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। उनका मानना है कि क्षेत्र की जनता को अपने नगर में ही गुणवत्तापूर्ण उपचार प्राप्त होना चाहिए और इसके लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे।

इस दौरान कलेक्टर राजीव रंजन मीणा एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अनीता सिंघल ने विषय का परीक्षण कर आवश्यक एवं नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया।

लैब टेक्नीशियन रवींद्र सिंह पंवार का निधन

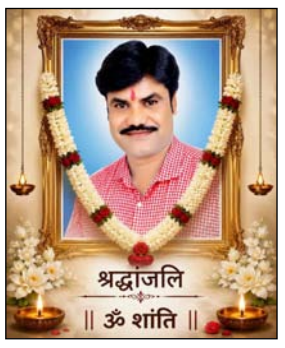

बदनावर/ मनीष शर्मा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। बदनावर रावतसेरी निवासी रवींद्रसिंह पंवार 47 वर्ष 8 जून सुबह 5 बजे निधन हो गया। रात में पैर फिसलने से बाथरूम में गिर गए थे। इससे उनकी पसली में गंभीर चोट लगी थी। कुछ ही देर में इसका असर फेफड़े तक पहुंच गया था। पता चलने पर उन्हें सिविल अस्पताल ले गए। वहां से बड़नगर ले जाया गया किंतु पहले ही उनका निधन हो चुका था।

सेवानिवृत शिक्षक मांगूसिंह पंवार के पुत्र व ज्ञानेंद्रसिंह के भाई तथा चेतन्यवीरसिंह के पिता थे। 2 बजे दोपहर में अंतिम यात्रा निककर नागेश्वर मुक्तिधाम अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कुशल लैब टेक्नीशियन माने जाते थे। स्थानीय दुर्गा चौक में उनकी लैब थी। असामयिक निधन से परिवार में शोक का माहोल।

घर-घर पहुंचा नल का जल, बदली श्रीमती मंजू वर्धन की जिंदगी

सीहोर/ दैनिक मालवा हेराल्ड। सीहोर जिले की रेहटी तहसील के ग्राम अमीरगंज में रहने वाली श्रीमती मंजू वर्धन के जीवन में जल जीवन मिशन के तहत संचालित नल-जल योजना ने एक बड़ा सकारात्मक बदलाव लाया है। कभी प्रतिदिन पानी की व्यवस्था करना उनके दिन का सबसे कठिन और समय लेने वाला काम हुआ करता था, लेकिन आज उनके घर के आंगन में लगे नल से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो रहा है। इससे न केवल उनकी दैनिक परेशानियां कम हुई हैं, बल्कि उनके जीवन की गुणवत्ता में भी उल्लेखनीय सुधार आया है। श्रीमती मंजू वर्धन बताती हैं कि पहले उन्हें पानी के लिए काफी दूर तक जाना पड़ता था। गर्मी के दिनों में स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण हो जाती थी। परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए कई बार दिन में अनेक चक्कर लगाने पड़ते थे, जिससे समय और श्रम दोनों की अधिक खपत होती थी। पानी लाने में लगने वाले समय के कारण घर के अन्य कार्यों पर भी प्रभाव पड़ता था।

उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत गांव में नल-जल योजना शुरू होने के बाद अब घर पर ही नियमित रूप से पानी उपलब्ध हो रहा है। इससे उन्हें बड़ी राहत मिली है। अब पानी के लिए अधिक दूरी तय नहीं करनी पड़ती और बचा हुआ समय परिवार की देखभाल तथा अन्य उपयोगी कार्यों में लगाया जा रहा है।

श्रीमती मंजू वर्धन का कहना है कि घर तक पानी पहुंचने से महिलाओं का जीवन काफी आसान हुआ है। पहले जहां पानी की चिंता दिनभर बनी रहती थी, वहीं अब स्वच्छ पेयजल सहज रूप से उपलब्ध होने लगा है। इससे परिवार के स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है तथा जीवन अधिक सुविधाजनक और सम्मानजनक बना है।

ग्राम अमीरगंज में जल जीवन मिशन के माध्यम से घर-घर नल कनेक्शन उपलब्ध कराकर ग्रामीणों को मूलभूत सुविधा से जोड़ा गया है। श्रीमती मंजू वर्धन की कहानी इस बात का प्रमाण है कि जल जीवन मिशन केवल पेयजल उपलब्ध कराने की योजना नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण महिलाओं के जीवन में बदलाव लाने, उनके श्रम को कम करने और उन्हें सशक्त बनाने का एक प्रभावी माध्यम भी बन रहा है।

भ्रष्ट कुर्सी पर तो मौन क्यों ? अब मुंह पर पट्टी बांधकर कलेक्टोरेट पहुंचे कांग्रेसी नेता पंकज तिवारी, जावद जनपद अध्यक्ष को हटाने की मांग

नीमच/ सतीश सैन/ दैनिक मालवा हेराल्ड। जावद जनपद पंचायत अध्यक्ष गोपाल चारण को भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के तहत पद से बर्खास्त करने की मांग को लेकर मंगलवार को जिला मुख्यालय पर एक अनोखा और तीखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। जावद विधानसभा क्षेत्र के नागरिक और कांग्रेस नेता पंकज तिवारी अपने मुंह पर ÷भ्रष्ट कुर्सी पर मौन क्यों?÷ लिखी पट्टी बांधकर नीमच कलेक्टोरेट पहुंचे। इस दौरान उनके हाथों में भारतीय संविधान और मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम-1993 की प्रतियां थीं, जिसके जरिए उन्होंने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए।

लोकायुक्त द्वारा रिश्वत लेते रेंज हाथों गिरफ्तारी बाद भी पद पर बने रहने का विरोध- कलेक्टर के नाम सौंपे गए ज्ञापन में पंकज तिवारी ने सीधे आरोप लगाया कि वर्ष 2023 में लोकायुक्त पुलिस ने जावद जनपद पंचायत अध्यक्ष गोपाल चारण को कथित रूप से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। उन्होंने कहा कि इस गंभीर मामले की जांच और न्यायालयीन प्रक्रिया वर्तमान में भी गतिशील है, लेकिन इसके बावजूद संबंधित जनप्रतिनिधि को अब तक पद से पृथक नहीं किया गया है। तिवारी ने इसे जनहित, नैतिक मूल्यों और लोकतांत्रिक व्यवस्था के बिल्कुल विपरीत बताते हुए कहा कि इससे समाज में बेहद गलत संदेश जा रहा है।

प्रशासन की निष्पक्षता पर खड़े किये प्रश्नचिह्न- ज्ञापन में स्पष्ट तौर पर मांग की गई है कि भ्रष्टाचार के इतने गंभीर मामले और न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने के चलते, मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम के तहत वैधानिक कार्रवाई करते हुए अध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से पदमुक्त किया जाए। पंकज तिवारी ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि लंबे समय के बाद भी प्रशासन द्वारा कोई ठोस कदम न उठाना, उसकी अपनी निष्पक्षता और नीयत पर भी बड़े प्रश्नचिह्न खड़े करता है।

संवैधानिक जवाबदेही सर्वोपरि- यश लोहार- प्रदर्शन के दौरान उपस्थित यश लोहार ने भारतीय संविधान और पंचायत राज अधिनियम के कानूनी प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी जनप्रतिनिधि की जवाबदेही सबसे ऊपर होती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि भ्रष्टाचार के मामलों में त्वरित, निष्पक्ष और पारदर्शी कार्रवाई नहीं की गई, तो जनता का प्रशासनिक और लोकतांत्रिक संस्थाओं से विश्वास पूरी तरह उठ जाएगा।

इस अनोखे प्रदर्शन ने कलेक्टोरेट परिसर में मौजूद अधिकारियों और आम जनता का ध्यान अपनी ओर जमकर आकर्षित किया। अब देखना यह है कि इस तीखे विरोध और सौंपे गए ज्ञापन के बाद जिला प्रशासन इस मामले में क्या वैधानिक रुख अख्तियार करता है।

जनसुनवाई में मिली दिव्यांग पूनमचंद को रेडक्रास से 10 हजार की आर्थिक सहायता

पूजा व भाईयों को फॉस्टर केयर योजना का लाभ

नीमच/ सतीश सैन/ दैनिक मालवा हेराल्ड। कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जनसुनवाई के दौरान 140 आवेदकों की समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को उनके त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला पंचायत सी.ई.ओ.श्री अमन वैष्णव, एडीएम श्री बी.एस. कलेश सहित अन्य जिला अधिकारी उपस्थित थे। प्रमुख प्रकरणों पर त्वरित कार्रवाई- अवैध कब्जे पर कार्रवाई- जनसुनवाई में ग्राम गिरदौड़ा की रामप्यारी बाई ने अपनी खाली जमीन पर ग्रामीणों द्वारा किए जा रहे अवैध कब्जे की शिकायत की। कलेक्टर ने तहसीलदार नीमच ग्रामीण को तत्काल मौके पर पटवारी भेजकर कब्जा हटवाने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

दिव्यांग को स्वरोजगार सहायता- कांकरिया तलाई के दिव्यांग बल्लुराम बंजारा द्वारा स्वरोजगार हेतु आर्थिक मदद के अनुरोध पर कलेक्टर ने सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग को दिव्यांग पूनमचंद को स्वरोजगार योजना का अविलंब लाभ दिलाने के निर्देश दिए।

तत्काल आर्थिक सहायता- जयप्रकाश नगर जीरन के दिव्यांग पूनमचंद द्वारा शारीरिक अक्षमता के चलते भरण-पोषण में कठिनाई संबंधी आवेदन पर कलेक्टर ने रेडक्रास प्रभारी को 10 हजार रुपये की तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए।

फॉस्टर केयर योजना का लाभ- ग्राम केरी निवासी बालिका पूजा के आवेदन पर कलेक्टर ने जिला कार्यक्रम अधिकारी को पूजा एवं उसके तीन भाईयों को फॉस्टर केयर योजना के तहत लाभान्वित करने के निर्देश दिए।

अन्य आवेदक- जनसुनवाई में दुधिखेड़ा के बालू बंजारा, पडदा की राजकुमारी, पिपल्याघोटा के जीवनलाल पाटीदार, वरथुन के मदनसिंह, माहुपुरा मोलकी के छीतरमल, श्रीपुरा के ईश्वरलाल, महागढ़ के कोमलसिंह, अननिया मानगिर के मदनलाल, निपानिया आबाद के सज्जनसिंह, ग्वालटोली के हरिश, निपानिया के भंवरसिंह, भाटखेड़ी की कारीबाई सहित अठाना के भंवरलाल, काजीवाड़ा रामपुरा की सुगनाबाई, गुठलाई के नारायण प्रजापत, बरूखेड़ा के भेरूलाल, जेतपुरा की प्रेमबाई, चम्पी के प्रदीप कुमावत, बोरखेड़ी की श्यामाबाई, पिपल्याहाड़ा की मांगीबाई, देवरान के देवीलाल, थडौद के मुरलीधर, ढाबा के हरलाल व उदयलाल गायरी, बालागंज के गोपाल एवं अडमालिया के जगदीशदास ने भी अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए।

मिलावट के विरुद्ध कार्रवाइयों में लगाए गए जुर्माने की वसूली समय पर सुनिश्चित की जाए - कलेक्टर

राशन हितग्राहियों को शत-प्रतिशत राशन वितरण और ईकेवाईसी करने के कलेक्टर ने दिए निर्देश

सीहोर/दैनिक मालवा हेराल्ड। कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कृषि, खाद्य, औषधि प्रशासन एवं खाद्य सुरक्षा विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित कर विभागीय गतिविधियों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आम नागरिकों और किसानों को आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए तथा सभी व्यवस्थाएं समय पर और सुचारू रूप से संचालित की जाएं।

खाद्य विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने निर्देश दिए कि पात्र हितग्राहियों को राशन का शत-प्रतिशत वितरण सुनिश्चित किया जाए तथा सभी हितग्राहियों की केवाईसी प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण की जाए। उन्होंने कहा कि राशन का उठाव और वितरण निर्धारित समय पर होना चाहिए, ताकि किसी भी पात्र परिवार को खाद्यान्न प्राप्त करने में कठिनाई न आए।

कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने जिले में डीजल, पेट्रोल एवं एलपीजी गैस की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के निर्देश देते हुए कहा कि अधिकारी पेट्रोल पंपों का नियमित निरीक्षण करें और आपूर्ति व्यवस्था पर सतत निगरानी रखें। उन्होंने विशेष रूप से निर्देश दिए कि किसानों को कृषि कार्यों के लिए आवश्यक डीजल की उपलब्धता में किसी प्रकार की बाधा न आए।

कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने डीएपी, एनपीके सहित उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खेती के सीजन में किसानों को खाद के लिए भटकना न पड़े। साथ ही उर्वरकों की कालाबाजारी पर सख्त नजर रखने और संबंधितों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों को ई-विकास पोर्टल से जनरेट टोकन के आधार पर पात्रतानुसार एवं नियमानुसार ही उर्वरकों का वितरण किया जाए। खाद्य सुरक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने निर्देश दिए कि मिलावट के विरुद्ध की गई कार्रवाइयों में लगाए गए जुर्माने की वसूली समय पर सुनिश्चित की जाए तथा लंबित प्रकरणों का त्वरित निराकरण किया जाए। उन्होंने खाद्य प्रतिष्ठानों और दुकानों का नियमित निरीक्षण कर मिलावटखोरों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई जारी रखने के निर्देश भी दिए। औषधि प्रशासन विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने निर्देश दिए कि जिले में दवाओं की गुणवत्ता एवं उपलब्धता पर सतत निगरानी रखी जाए। उन्होंने कहा कि मेडिकल स्टोर्स और औषधि प्रतिष्ठानों का नियमित निरीक्षण किया जाए तथा अमानक, नकली अथवा एक्सपायरी दवाओं के विक्रय पर सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही आवश्यक जीवनरक्षक दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए आमजन को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण औषधियां उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

बैठक में कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने कहा कि आमजन को गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना, किसानों को समय पर खाद एवं ईंधन उपलब्ध कराना तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावी बनाए रखना प्रशासन का दायित्व है। इसके लिए सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य करते हुए शासन की योजनाओं और व्यवस्थाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। बैठक में कृषि उप संचालक श्री अशोक कुमार उपाध्याय, जिला आपूर्ति अधिकारी श्रीमती रेशमा भामोर सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने पेटलावद एवं रायपुरिया स्वास्थ्य केंद्रों का किया निरीक्षण

झाबुआ/ दैनिक मालवा हेराल्ड। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के विशेष शिविर के अंतर्गत जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. देवेन्द्र भायल द्वारा सिविल अस्पताल पेटलावद एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रायपुरिया का निरीक्षण किया गया।

सिविल अस्पताल पेटलावद में निरीक्षण के दौरान बताया गया कि माह मई 2026 में संस्था पर 357 प्रसव एवं 28 IUCD सेवाएं प्रदान की गईं। PMSMA विशेष शिविर के दौरान 98 गर्भवती महिलाओं की एएनसी जांच की गई तथा निरीक्षण दिवस पर संस्था की ओपीडी 170 रही। डॉ. भायल द्वारा गर्भवती महिलाओं को प्रदान की जा रही एएनसी सेवाओं, उच्च जोखिम गर्भवती महिलाओं की पहचान एवं फॉलोअप व्यवस्था का अवलोकन किया गया तथा गुणवत्तापूर्ण मातृ स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इसके पश्चात प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रायपुरिया का निरीक्षण किया गया, जहां माह मई 2026 में 36 प्रसव एवं 1 PPIUCD सेवा प्रदान की गई। PMSMA शिविर में 28 गर्भवती महिलाओं की एएनसी जांच की गई तथा संस्था की ओपीडी 50 रही। संस्था के स्वास्थ्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सभी गर्भवती महिलाओं का समयबद्ध पंजीयन, नियमित जांच एवं आवश्यकतानुसार रेफरल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

निरीक्षण के दौरान दोनों संस्थाओं के लेबर रूम का विस्तृत निरीक्षण किया गया। दोनों संस्थाओं के लेबर रूम साफ-सुथरे एवं व्यवस्थित पाए गए। प्रसव सेवाओं हेतु उपलब्ध सभी आवश्यक उपकरण क्रियाशील स्थिति में पाए गए तथा संबंधित रजिस्टरों में प्रविष्टियां अद्यतन एवं सुव्यवस्थित रूप से दर्ज पाई गईं।

इसके अतिरिक्त दोनों स्वास्थ्य संस्थाओं में पेयजल की समुचित व्यवस्था, परिसर एवं वार्डों में संतोषजनक साफ-सफाई तथा मरीजों के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध पाई गईं। एएनसी क्लिनिक, प्रयोगशाला सेवाओं, औषधियों की उपलब्धता, MCP कार्ड वितरण तथा e-PMSMA एवं ANMOL पोर्टल पर रिपोर्टिंग व्यवस्था का भी अवलोकन किया गया।

डॉ. भायल द्वारा निर्देश दिए गए कि उच्च जोखिम गर्भवती महिलाओं की समय पर पहचान एवं नियमित फॉलोअप सुनिश्चित किया जाए, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा दिया जाए, परिवार नियोजन सेवाओं का विस्तार किया जाए तथा सभी पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाने की कार्यवाही निरंतर जारी रखी जाए। गर्भवती महिलाओं को संतुलित आहार, आयरन एवं कैल्शियम सेवन, प्रसव पूर्व एवं प्रसवोत्तर देखभाल तथा संस्थागत प्रसव के महत्व के संबंध में परामर्श भी प्रदान किया गया।

फार्मर रजिस्ट्री में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, एक सप्ताह में लक्ष्य पूर्ण करें : एसडीएम महेश मंडलोई

झाबुआ/ दैनिक मालवा हेराल्ड। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राणापुर श्री महेश मंडलोई ने मंगलवार को तहसील कार्यालय राणापुर में पटवारियों की समीक्षा बैठक आयोजित कर शासन की विभिन्न प्राथमिकता वाली योजनाओं एवं राजस्व कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में विशेष रूप से फार्मर रजिस्ट्री, राजस्व प्रकरणों के निराकरण, सीएम हेल्पलाइन शिकायतों तथा आगामी मानसून को देखते हुए आपदा प्रबंधन तैयारियों पर चर्चा की गई।

बैठक में फार्मर रजिस्ट्री कार्य की समीक्षा के दौरान पाया गया कि राणापुर तहसील में अब तक 35.20 प्रतिशत किसानों की ही फार्मर रजिस्ट्री पूर्ण हो सकी है। इस पर असंतोष व्यक्त करते हुए एसडीएम श्री मंडलोई ने सभी पटवारियों को निर्देशित किया कि वे आगामी एक सप्ताह के भीतर शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने हेतु विशेष अभियान चलाएं। उन्होंने कहा कि सभी पटवारी अपने-अपने हल्कों में पहुंचकर विशेष शिविर आयोजित करें तथा किसानों की फार्मर रजिस्ट्री का कार्य प्राथमिकता से पूर्ण करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि शासन की इस महत्वपूर्ण योजना के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

बैठक में नामांतरण, बंटवारा एवं सीमांकन सहित विभिन्न राजस्व प्रकरणों की भी समीक्षा की गई। एसडीएम ने लंबित प्रकरणों का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों की समीक्षा करते हुए उन्होंने 50 दिवस से अधिक अवधि से लंबित प्रकरणों का शत-प्रतिशत एवं संतुष्टिपूर्ण निराकरण शीघ्र करने के निर्देश दिए।

मेघनगर जनसुनवाई में 97 आवेदनों पर सुनवाई, कलेक्टर ने दिए त्वरित निराकरण के निर्देश

झाबुआ/दैनिक मालवा हेराल्ड। कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट ने मंगलवार को विकासखंड मेघनगर में आयोजित जनसुनवाई में नागरिकों की समस्याएं एवं मांगें सुनीं। उन्होंने प्राप्त आवेदनों के त्वरित एवं प्रभावी निराकरण हेतु संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

जनसुनवाई के दौरान ग्राम मोरीपाड़ा, ग्राम पंचायत बिसौली के ग्रामीणों ने तड़वी फलिया में पेयजल एवं सिंचाई जल की गंभीर समस्या से अवगत कराते हुए सार्वजनिक कुएं के निर्माण की स्वीकृति प्रदान किए जाने संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया।

आवेदक श्री राजा मानसिंह बसौड़, तहसील मेघनगर ने क्षेत्र में स्थित केमिकल उद्योगों से होने वाले प्रदूषण की समस्या उठाई। उन्होंने बताया कि उद्योगों से निकलने वाला रासायनिक युक्त अपशिष्ट जल खुले स्थानों एवं कुण्डों में छोड़ा जा रहा है, जिससे पर्यावरण एवं जनस्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। उन्होंने औद्योगिक प्रदूषण, नल-जल योजना के अंतर्गत दूषित पेयजल आपूर्ति तथा संबंधित कर्मचारियों के अभद्र व्यवहार के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया।

आवेदिका रीता, पति स्वर्गीय गलिया ने बताया कि उनके पति की खेत के समीप स्थित कुएं में पानी पीने के दौरान डूबने से मृत्यु हो गई थी, किन्तु राजस्व एवं श्रम विभाग से उन्हें आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने पात्रतानुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध कराए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया।

श्री गणपतसिंह नायक, निवासी रंभापुर रोड, टेम्पो चौराहा, मेघनगर ने शिकायत की कि उनके मकान के दक्षिण दिशा में स्थित वर्षा जल एवं नाली निकासी के प्राकृतिक मार्ग पर कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण किया जा रहा है। उन्होंने प्रकरण की जांच कर अतिक्रमण हटाने तथा आवश्यक कार्रवाई किए जाने की मांग की।

हितलाभ वितरण- जनसुनवाई के दौरान विभिन्न हितग्राहियों को शासन की योजनाओं के अंतर्गत लाभ भी वितरित किए गए। ई-विकास प्रणाली के माध्यम से कृषक श्री गोपाल, श्री मनिया खपेड एवं श्री देवचंद भूरा को उर्वरक हेतु ई-टोकन प्रदान किए गए।

लाड़ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत जीविका, यशवी, समृद्धि एवं प्रियांशी को प्रमाण-पत्र वितरित किए गए। वहीं अनाया एवं छवि को विद्यारंभ योजना के प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए।

मेघनगर में आयोजित जनसुनवाई में कुल 97 आवेदन प्राप्त हुए। वहीं जिला मुख्यालय झाबुआ में अपर कलेक्टर श्री सी.एस. सोलंकी एवं संयुक्त कलेक्टर श्री विजय कुमार मंडलोई द्वारा आयोजित जनसुनवाई में 101 आवेदन प्राप्त हुए। सभी आवेदनों के निराकरण हेतु संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए गए।

इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री जितेन्द्र सिंह चौहान, डिप्टी कलेक्टर श्री महेश बड़ोले, एसडीएम मेघनगर सुश्री अवनधती प्रधान, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बी.एस. बघेल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

बाल संप्रेषण गृह में निवासरत किशोरों के लिये आयोजित किया गया स्वास्थ्य परीक्षण शिविर

जबलपुर/दैनिक मालवा हेराल्ड। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री कृष्णमूर्ति मिश्र के मार्गदर्शन में आज बाल संप्रेषण गृह में निवासरत किशोरों के लिए निः शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य बालकों के समग्र स्वास्थ्य का आकलन करना तथा उन्हें आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श एवं उपचार उपलब्ध कराना था। शिविर के दौरान सभी किशोरों का सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिसमें स्वास्थ्य परामर्श एवं अन्य आवश्यक चिकित्सकीय जांचें शामिल थीं। साथ ही, जरूरतमंद बालकों को दवाइयों का वितरण भी किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव श्रीमती शक्ति वर्मा ने सभी बालकों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हुए प्रतिदिन योग एवं व्यायाम करने, संतुलित एवं पौष्टिक आहार लेने, पर्याप्त नींद लेने तथा व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने के महत्व को विस्तारपूर्वक समझाया। उन्होंने विशेष रूप से गर्मी के मौसम में होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं जैसे लू लगना, डिहाइड्रेशन एवं थकान लू से बचाव के उपायों पर भी प्रकाश डाला। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ने सकारात्मक सोच अनुशासित दिनचर्या एवं मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर भी जोर देते हुए बालकों को प्रेरित किया कि वे अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें और किसी भी समस्या होने पर तुरंत परामर्श लें। उन्होंने नशे से दूर रहने का आग्रह करते हुये कहा कि नशा केवल एक बुरी आदत ही नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी मानसिक और शारीरिक बीमारी है जो हंसते-खेलते परिवारों को तबाह कर देती है। आज का युवा, जो कल के देश का भविष्य है, अनजाने में या दोस्तों के दबाव में आकर नशे के जाल में फंसता जा रहा है।

स्व-निधि मिली तो मंजिल खुद चलकर आई

ग्वालियर/दैनिक मालवा हेराल्ड। ग्वालियर शहर के सिद्धेश्वर नगर, मुरार की रहने वाली इन्द्रा प्रजापति की कहानी उन लाखों महिलाओं के लिए एक मिसाल है, जो सीमित संसाधनों के बावजूद अपने सपनों को पंख देना चाहती हैं।

कुछ समय पहले तक इन्द्रा के पास न पर्याप्त पूंजी थी और न कोई बड़ा सहारा, पर उन्हें अपनी अदम्य जिजीविषा और मेहनत पर अटूट भरोसा था। प्रधानमंत्री स्व-निधि योजना ने उनकी उम्मीद को पंख लगा दिए। योजना के तहत इन्द्रा को पहले चरण में 10 हजार रूपये की आर्थिक सहायता प्राप्त हुई। इस छोटी-सी पूंजी को उन्होंने बड़े हौसले के साथ लगाया और हाथ ठेले पर फल बेचने का व्यवसाय शुरू किया। उनकी लगन और ईमानदार मेहनत रंग लाई। व्यवसाय चल निकला और घर में खुशहाली की एक नई सुबह हुई।

कुछ समय पहले तक इन्द्रा के पास न पर्याप्त पूंजी थी और न कोई बड़ा सहारा, पर उन्हें अपनी अदम्य जिजीविषा और मेहनत पर अटूट भरोसा था। प्रधानमंत्री स्व-निधि योजना ने उनकी उम्मीद को पंख लगा दिए। योजना के तहत इन्द्रा को पहले चरण में 10 हजार रूपये की आर्थिक सहायता प्राप्त हुई। इस छोटी-सी पूंजी को उन्होंने बड़े हौसले के साथ लगाया और हाथ ठेले पर फल बेचने का व्यवसाय शुरू किया। उनकी लगन और ईमानदार मेहनत रंग लाई। व्यवसाय चल निकला और घर में खुशहाली की एक नई सुबह हुई।

आज इन्द्रा प्रजापति के चेहरे पर जो संतोष और आत्मनिर्भरता की चमक है, वह इस योजना की सबसे बड़ी सफलता है। वे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रति हृदय से कृतज्ञ हैं और कहती हैं कि इस योजना ने उनके जीवन को एक नया अर्थ दिया है।

इन्द्रा की स्वावलंबन की ओर यह यात्रा सिद्ध करती है कि जब सरकार की सही नीति और एक आम नागरिक की कड़ी मेहनत साथ आती है, तो तस्वीर बदलते देर नहीं लगती।

महिन्द्रा पिकअप वाहन से 904.8 बल्क लीटर अवैध शराब जप्त

झाबुआ/ दैनिक मालवा हेराल्ड। जिले में अवैध मदिरा के धारण, परिवहन एवं विक्रय पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट तथा उपायुक्त, संभागीय उड़नदस्ता इंदौर श्री इंदरसिंह जामोद के निर्देशानुसार आबकारी विभाग द्वारा सतत कार्रवाई की जा रही है।

इसी क्रम में जिला आबकारी अधिकारी श्रीमती बसंती भूरिया के निर्देशन में दिनांक 09 जून 2026 को रात्रि गश्त के दौरान आबकारी टीम द्वारा वृत्त पेटलावद 'ब' क्षेत्र में बदनावर-सारंगी मार्ग पर एक संदिग्ध महिन्द्रा पिकअप वाहन को चिन्हित किया गया। टीम द्वारा वाहन का पीछा कर ग्राम कसारबर्डी में उसे रोका गया। वाहन चालक वाहन को सड़क पर छोड़कर फरार हो गया, जिसकी तलाश किए जाने के बावजूद उसे मौके पर पकड़ा नहीं जा सका।

वाहन क्रमांक MP41GA4039 की विधिवत तलाशी लेने पर उसमें से विदेशी मदिरा बैगपाइपर डीलक्स व्हिस्की की 70 पेटियां (604.8 बल्क लीटर) तथा माउंट 6000 सुपर स्ट्रांग बियर कैन की 25 पेटियां (300 बल्क लीटर) बरामद हुईं। इस प्रकार कुल 95 पेटियों में 904.8 बल्क लीटर अवैध मदिरा जप्त की गई।

मौके पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (संशोधित 2000) की धारा 34(1)(क), 34(2), 36 एवं 46 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया। कार्रवाई की नवीन विधिक प्रावधानों के अनुसार वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी भी कराई गई।

जप्त की गई मदिरा का अनुमानित बाजार मूल्य 6 लाख 56 हजार 760 रुपये तथा वाहन का अनुमानित मूल्य 8 लाख रुपये है। इस प्रकार जप्त मदिरा एवं वाहन का कुल अनुमानित मूल्य 14 लाख 56 हजार 760 रुपये है। यह कार्रवाई सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री महादेव सोलंकी के मार्गदर्शन में आबकारी उपनिरीक्षक श्री प्रेमसिंह परमार द्वारा की गई।

कार्रवाई में आबकारी उपनिरीक्षक श्री योगेश कुमार दामा, मुख्य आरक्षक श्री कांतु डामोर, आरक्षक श्री कुंवर सिंह डावर, श्री पंकज डोडियार, श्री लालचंद गेहलोत तथा वाहन चालक श्री लोकेंद्र बर्मन एवं श्री दयाल मड़ोडिया का उल्लेखनीय योगदान रहा। आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध मदिरा के परिवहन, संग्रहण एवं विक्रय के विरुद्ध अभियान निरंतर जारी रहेगा।

कलेक्टर ने मेघनगर की पेयजल व्यवस्था का किया निरीक्षण, वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट एवं झायड़ा बैराज का लिया जायजा

झाबुआ/ दैनिक मालवा हेराल्ड। कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट ने नगर परिषद मेघनगर के वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट, झायड़ा बैराज एवं इंटेक वेल का निरीक्षण कर नगर की पेयजल आपूर्ति व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जल शोधन, गुणवत्ता परीक्षण एवं जल स्त्रोतों से संबंधित व्यवस्थाओं का गहनता से अवलोकन करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने कच्चे पानी के संग्रहण से लेकर उसके शुद्धिकरण एवं वितरण तक की संपूर्ण प्रक्रिया का विस्तार से अवलोकन किया। उन्होंने जल शोधन की विभिन्न चरणबद्ध प्रक्रियाओं, फिल्ट्रेशन यूनिट, क्लोरीनेशन व्यवस्था तथा जल गुणवत्ता परीक्षण प्रणाली की जानकारी प्राप्त की। इस दौरान कलेक्टर ने शुद्ध किए गए पानी का क्लोरीन टेस्ट अपने समक्ष कराकर उसकी गुणवत्ता का परीक्षण भी किया।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पेयजल की गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का नियमित परीक्षण किया जाए तथा नागरिकों को सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए।

कलेक्टर ने कहा कि नगर की जल प्रदाय व्यवस्था से जुड़े सभी तंत्रों का नियमित रखरखाव एवं सतत निगरानी आवश्यक है। जल शोधन संयंत्र की कार्यक्षमता बनाए रखते हुए गुणवत्ता नियंत्रण के सभी मापदंडों का पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि आमजन को निरंतर स्वच्छ एवं गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध हो सके।

इसके पश्चात कलेक्टर ने झायड़ा बैराज एवं इंटेक वेल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बैराज में उपलब्ध जल की स्थिति, जल संग्रहण क्षमता तथा इंटेक वेल के माध्यम से जल उठाव की व्यवस्था का अवलोकन किया। इस दौरान कलेक्टर ने इंटेक वेल में दूषित पानी के विथड्रॉल की प्रक्रिया को भी देखा तथा संबंधित अधिकारियों से इसकी संपूर्ण कार्यप्रणाली की जानकारी प्राप्त की। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि जल गुणवत्ता बनाए रखने एवं स्वच्छ जल के संग्रहण को सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर दूषित अथवा अनुपयुक्त पानी की निकासी की जाती है।

कलेक्टर ने निर्देश दिए कि बैराज एवं इंटेक वेल क्षेत्र की नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित की जाए तथा जल स्त्रोतों को प्रदूषण से सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक सावधानियां बरती जाएं। उन्होंने इंटेक वेल की मशीनरी, पम्पों एवं विद्युत उपकरणों का नियमित निरीक्षण करने, आवश्यक मरम्मत समय पर कराने तथा आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं तैयार रखने के निर्देश दिए।

अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित बरेला का सांदीपनि विद्यालय तैयार, 16 जून से शुरू होंगी नियमित कक्षाएं

जबलपुर/दैनिक मालवा हेराल्ड। बरेला स्थित अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त सांदीपनि विद्यालय का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। लगभग 4.426 एकड़ क्षेत्र में 32.76 करोड़ रुपये की लागत से तैयार यह विद्यालय अब विद्यार्थियों को आकर्षित कर रहा है। आगामी 16 जून से केजी-1 से लेकर कक्षा 12वीं तक की नियमित कक्षाएं प्रारंभ होंगी। विद्यालय में 1830 विद्यार्थियों के प्रवेश का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, अब तक तक 1292 विद्यार्थियों का प्रवेश हो चुका है। विद्यालय प्राचार्य के अनुसार नई प्रवेश नीति लागू होने के बाद अब निजी विद्यालयों के विद्यार्थी भी मेरिट के आधार पर प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे, जिससे निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति में सहायता मिलेगी। -अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है विद्यालय- चार एकड़ से अधिक क्षेत्र में निर्मित तीन मंजिला विद्यालय भवन में केजी-1 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए अलग-अलग कक्षाओं की व्यवस्था की गई है। नन्हे बच्चों के लिए विशेष प्ले रूम, आकर्षक खिलौने और झूले तैयार किए गए हैं। विद्यालय में म्यूजिक रूम, डांस रूम, कंप्यूटर लैब, गणित, जीवविज्ञान, भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान की आधुनिक प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। सभी कक्षाओं में इंटरएक्टिव पैनल (डिजिटल बोर्ड) लगाए गए हैं, जिनकी मदद से विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक एवं इंटरनेट आधारित शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा विद्यार्थियों की स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सिक रूम की भी व्यवस्था की गई है। कुशल शिक्षक देंगे शिक्षा विद्यालय के प्राचार्य डी.के. गुप्ता ने बताया कि शासन द्वारा निर्धारित सभी विषयों एवं सह-शैक्षणिक गतिविधियों के लिए कुशल एवं प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। वर्तमान में विद्यालय में 41 शिक्षक कार्यरत हैं, जो विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण एवं बेहतर शिक्षा प्रदान करेंगे। उन्होंने बताया कि विद्यालय भवन का निर्माण ए-ग्रेड गुणवत्ता मानकों के अनुरूप किया गया है। प्रवेश प्रक्रिया निरंतर जारी है और आने वाले दिनों में विद्यार्थियों की संख्या 1500 तक पहुंचने की संभावना है।

मालिक, प्रकाशक, मुद्रक विजय शर्मा द्वारा 44, बहादुरगंज, उज्जैन (म.प्र.) से प्रकाशित एवं भगवती ऑफसेट 44, बहादुरगंज, उज्जैन (म.प्र.) से मुद्रित। सम्पादक - विजय शर्मा, मो.नं. 94250-22499, फोन 0734-2553435 प्रधान संपादक : शुभम ताम्रकार (सभी वाद विवाद का न्याय क्षेत्र उज्जैन रहेगा)

4 किमी लंबा एलिवेटेड ब्रिज बदलेगा उज्जैन का ट्रैफिक सिस्टम

मकोड़ियाआम कृषि मंडी से हरिफाटक तक बनेगा फोरलेन एलिवेटेड कॉरिडोर

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। आगामी सिंहस्थ को लेकर शहर में बुनियादी ढांचे के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में शामिल एलिवेटेड ब्रिज की तैयारी जल्द ही जमीन पर उतरती दिखाई देगी।सोमवार को संभाग आयुक्त और कलेक्टर ने अधिकारियों के साथ प्रस्तावित एलिवेटेड ब्रिज के निर्माण स्थल का निरीक्षण कर विस्तृत योजना तैयार करने के निर्देश दिए।

प्रशासन की योजना के अनुसार यह फोरलेन एलिवेटेड ब्रिज करीब 4 किलोमीटर लंबा होगा। इसका निर्माण आगर रोड स्थित मकोड़ियाआम कृषि उपज मंडी से शुरू होकर चामुंडा माता चौराहा, रेलवे स्टेशन क्षेत्र और हरिफाटक तक किया जाएगा। ब्रिज का एक सिरा सीधे हरिफाटक ब्रिज से जुड़ेगा, जिससे शहर के सबसे व्यस्त हिस्सों में ट्रैफिक दबाव कम करने में मदद मिलेगी।

सिंहस्थ के दौरान उज्जैन में करोड़ों श्रद्धालुओं के आने की संभावना को देखते हुए प्रशासन भीड़ और यातायात प्रबंधन को लेकर बड़े पैमाने पर तैयारी कर रहा है। अधिकारियों का मानना है कि यह एलिवेटेड कॉरिडोर शहर के भीतर से गुजरने वाले वाहनों और सिंहस्थ के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं के यातायात को आसन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

निरीक्षण के दौरान नगर निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा सहित अन्य विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे। संभाग आयुक्त ने अधिकारियों से कहा कि ब्रिज निर्माण का पूरा तकनीकी प्लान जल्द तैयार कर क्रियान्वयन की दिशा में तेजी लाई जाए। इधर, अधिकारियों ने ढाबा रोड से दानी गेट तक चल रहे मार्ग चौड़ीकरण कार्य का भी निरीक्षण किया। मौके पर निर्माण एजेंसियों को गुणवत्ता से समझौता किए बिना निर्धारित समयसीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए गए।

प्रशासन का दावा है कि आगामी सिंहस्थ को देखते हुए सड़क, पुल, यातायात और भीड़ प्रबंधन से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। प्रस्तावित 4 किलोमीटर लंबे फोरलेन एलिवेटेड ब्रिज को इसी का अहम हिस्सा माना जा रहा है, जो भविष्य में भी शहर के ट्रैफिक नेटवर्क को नई दिशा देगा।

एक नजर में पूरा प्रोजेक्ट-

-प्रस्तावित लंबाई- लगभग 4 किलोमीटर

-प्रकार- फोरलेन एलिवेटेड ब्रिज

-प्रारंभ बिंदु- मकोड़ियाआम कृषि उपज मंडी, आगर रोड

-मार्ग- चामुंडा माता चौराहा ङ्क रेलवे स्टेशन क्षेत्र

-अंतिम बिंदु- हरिफाटक ब्रिज

बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने कुचला, मौत

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। बीती रात अज्ञात वाहन से हुई दुर्घटना बाइक सवारी युवक की मौत हो गई उसके पास मिले आधार कार्ड से पहचान होने पर परिजनों को सूचना दी गई। पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश कर रही है। पंवासा थाना पुलिस ने बताया कि पंड्याखेड़ी चौराहा से उद्योगपुरी में जाने वाले मार्ग पर रात 11-30 12 बजे के लगभग अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी थी। गंभीर हालत में दुर्घटना स्थल से एंबुलेंस निजी अस्पताल लेकर पहुंची थी। जहां युवक की मौत होना सामने आया था। मामले की सूचना पुलिस को मिली तो अस्पताल पहुंची और मृतक के कपड़ों की तलाशी ली गई जिसमें उसका आधार कार्ड मिलना सामने आया। जिससे उसकी पहचान गजेंद्र पिता सोहन सिंह राजपूत 38 साल निवासी पंड्याखेड़ी के रूप में हुई। परिजन सूचना मिलते ही रात में अस्पताल पहुंच गए थे। पुलिस ने निजी अस्पताल से शव पोस्टमार्टम के लिए चरक अस्पताल पहुंचाया। मंगलवार सुबह पोस्टमार्टम के दौरान सामने आया कि गजेंद्र मजदूरी करता था और रात में घर लौट रहा था। पुलिस ने मर्ग कायम कर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू की।

गले में रस्सी का फंदा डाल 2 लोगो ने लगाई फांसी

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। पिछले कुछ घंटो में दो लोगों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। एक कुल्फी बेचने का काम करता था दूसरा रेलवे में गैंगमेन था। दो थानों की पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम कराए गए हैं। एक के पास से सुसाइड नोट भी मिला है। उन्हेल थाना क्षेत्र के ग्राम पिपलिया डाबी में मंगलवार सुबह घर में मुकेश पिता रूपनाथ बागरी 55 वर्ष की लाश फंदे पर लटकी मिली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची इस दौरान सामने आया कि मृतक मुकेश कुल्फी बेचने का काम करता था। पुलिस ने शव को फंदे से उतारा इस दौरान उसके पास से एक सुसाइड नोट मिला जिसमें लिखा था कि मैं अपनी मर्जी से आत्महत्या कर रहा हूं किसी को परेशान ना किया जाए। परिजनों ने घटना के संबंध में बताया कि रात तक सब कुछ ठीक था। उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया इसकी जानकारी नहीं है लेकिन माना जा रहा है कि संभवत आर्थिक परेशानी के चलते मुकेश ने आत्महत्या की है। दूसरा मामला सोमवार शाम को नागझिरी थाना क्षेत्र के विक्रम नगर रेलवे स्टेशन परिसर में बनी रेलवे कॉलोनी से सामने आया। रेलवे में गैंगमेन का काम करने वाले कमल सिंह पिता रतनलाल भाटी ने घर में ही फांसी लगा ली थी। घटना से पहले सांवेर गए पुत्र शुभम को जल्दी आने के लिए मोबाइल पर कॉल किया था। पुत्र ने अपने छोटे भाई को पिता के फोन आने की जानकारी दी और कमरे में जाकर देखने को कहा क्योंकि पिता बीमार चल रहे थे। छोटा पुत्र राजवीर कुछ देर बाद कमरे में पहुंचा तो उसने पिता को फंदे पर लटका देखा। मंगलवार सुबह पोस्टमार्टम के दौरान सामने आया कि कमल सिंह पिछले कुछ महीनो से बीमार चल रहा था उसका ऑपरेशन भी हुआ था और वह नौकरी पर नहीं जा पा रहा था। पुत्र शुभम ने आरोप लगाया कि पिता पर कम पर लौट के लिए दबाव बनाया जा रहा था पिता ने भारी काम करने से मना कर दिया था लेकिन उनसे ट्रैक पर ही काम करने के लिए कहा जा रहा था संभव था इसी के चलते पिता ने आत्महत्या की है। फिलहाल दोनों मामलों में पुलिस द्वारा जांच की जा रही है।

बारिश के लिए अभी एक सप्ताह का इंतजार, 8 दिन और सताएगी गर्मी

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। जून का पहला सप्ताह बीतने को है, लेकिन शहरवासियों को अभी बारिश के लिए कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार मालवांचल क्षेत्र में फिलहाल ऐसा कोई प्रभावी मौसम तंत्र सक्रिय नहीं है, जो अच्छी बारिश करा सके। ऐसे में अगले एक सप्ताह तक मानसून जैसी स्थिति बनने की संभावना कम है। वेधशाला अधीक्षक डॉ. आरपी गुप्त ने बताया कि क्षेत्र में प्री-मानसून गतिविधियां जरूर शुरू हो गई हैं, लेकिन बारिश के लिए अनुकूल सिस्टम अभी विकसित नहीं हुआ है। इसके कारण उज्जैन सहित आसपास के क्षेत्रों में लोगों को करीब आठ दिन और गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। सोमवार को शहर का अधिकतम तापमान 39.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि मंगलवार सुबह न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। दिनभर तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं रात में भी तापमान अपेक्षाकृत अधिक रहने से उमस और बेचैनी बनी रही। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि प्री-मानसून गतिविधियों के चलते कहीं-कहीं बादल छाने या हल्की बूंदाबांदी की स्थिति बन सकती है, लेकिन व्यापक और राहत देने वाली बारिश के लिए अभी इंतजार करना होगा। लगातार बढ़ती गर्मी के बीच शहरवासी अब मानसून की पहली अच्छी बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

गश्त में 2 युवकों के पास मिली 1 किलो एमडी ड्रग्स

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। रात्रि गश्त के दौरान मादक पदार्थ तस्करी में शामिल कार सवार दो युवकों को पकड़ा गया। जिनके पास से 1 किलो 15 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद की गई है। दोनों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। मादक पदार्थ से जुड़े कुछ और आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकती है। एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि चिमनगंज थाना पुलिस रात्रि गश्त पर थी। गरोठ रोड ब्रिज के नीचे टाइम हेडक्वार्टर के पीछे सर्विस रोड क्षेत्र में एक संदिग्ध वाहन क्रमांक एम एच 31एफ आर 2515 स्विफ्ट डिजायर कार खड़ी दिखाई दी। वाहन के पास पहुंचकर पुलिस टीम ने देखा तो उसमें दो युवक सवार थे जिनसे पूछताछ करने पर उनके नाम पंकज पिता श्यामराव चरडे 34 वर्ष निवासी प्रभा सिटी, पवनगांव, थाना पार्डी जिला नागपुर (महाराष्ट्र) और अमित तिवारी पिता महेन्द्र तिवारी 20 वर्ष निवासी बिहार सामने आये। रात के अंधेरे में बाहरी युवकों के मिलने पर उनकी कार की तलाशी ली गई। जिसमें एक बॉक्स रखा मिला। पूछताछ करने पर बॉक्स में रखे सामान की जानकारी देने में दोनों बरगलाने। पुलिस द्वारा बॉक्स खोला गया तो उसमें एक थैली के अंदर रखा मादक पदार्थ एमडी ड्रग्स बरामद हो गया। जोक 1 किलो 15 ग्राम था। दोनों लोगों को थाने लाया गया और उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट का प्रकरण दर्ज किया गया। मादक पदार्थ की कीमत 15 लाख और कार की 5.50 लाख रुपए होना सामने जिसे जप्त कर दोनों आरोपियों को मंगलवार दोपहर न्यायालय में पेश किया गया जहां से पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया गया है। थाना प्रभारी विवेक कनोडिया ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मादक पदार्थ मंदसौर से लाया गया था और नागपुर ले जाया जा रहा था। दोनों युवक अपने एक साथी का इंतजार करने के लिए गरोठ ब्रिज के नीचे रुके थे। उनसे साथी के संबंध में भी जानकारी जुटा जा रही है जिसकी मादक पदार्थ तस्करी में भूमिका सामने आने पर गिरफ्तारी की जाएगी। दोनों को गिरफ्तार करने में उपनिरीक्षक लिबेन खेस, सहायक उपनिरीक्षक दिनेश सरौठिया, आरक्षक तेजकरण हिरवे, जगदीश गेहलोत, संदीप चौधरी, अर्जुन जाटव, वीरसिंह, सोहन वर्मा, अभिषेक राठौर की मुख्य भूमिका रही

शिप्रा नदी से मिली युवक की लाश

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। मंगलवार सुबह शिप्रा नदी से एक युवक की लाश बरामद की गई। युवक के पास से पहचान का कोई दस्तावेज नहीं मिला। पुलिस उसके परिजनों की जानकारी जुटाने का प्रयास कर रही है। महाकाल थाना पुलिस ने बताया कि शिप्रा नदी स्थित रामघाट पर मंगलवार सुबह कुछ लोगों ने एक युवक की लाश देख पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचे तैराक दल के सदस्यों की मदद लाश को बाहर निकाल। मृतक सिर्फ अंडरवियर में था आशंका जताई गई कि नहाने के दौरान डूबने से उसकी मौत हुई है। पुलिस ने आसपास घाट पर कपड़ों की तलाश की लेकिन कुछ नहीं मिला जिसके चलते मृतक की पहचान नहीं हो पाई। पुलिस के अनुसार मृतक 25 से 30 साल का है। जिसका शव पोस्टमार्टम कक्ष में रखा गया है। उसके परिजनों की जानकारी जुटाना का प्रयास किया जा रहा है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मृतक अन्य जिले से आया हुआ था। पुलिस द्वारा सभी जिले के पुलिस को मृतक का फोटो भेजा गया है, वही गुमशुदा लोगों की जानकारी भी मांगी गई है। 24 घंटे बाद मृतक की पहचान नहीं होने पर पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम कराकर शव दफनाया जाएगा।

प्रशासक पहुंचे श्रद्धालुओं के बीच... पूछा, कैसी हैं व्यवस्थाएं..?

महाकाल दर्शन की दर्शन कतारों को और आसान बनाने के निर्देश- विश्राम धाम के बेहतर उपयोग पर जोर

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। महाकाल मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर और सुगम दर्शन सुविधा देने के लिए मंदिर प्रशासन अब सीधे उनसे संवाद कर रहा है। बीते दिन मंदिर प्रशासक एवं ने मंदिर की दर्शन व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने स्वयं श्रद्धालुओं से बातचीत कर व्यवस्थाओं को लेकर फीडबैक लिया।

निरीक्षण के दौरान प्रशासक प्रथम कौशिक ने गणेश मंडप से शुरू होने वाली कतार व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं की लाइन को अधिक सरल, व्यवस्थित और सुचारु बनाया जाए ताकि दर्शन के दौरान अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। साथ ही शीघ्र दर्शन व्यवस्था को भी और अधिक सुगम बनाने के निर्देश दिए गए।

प्रशासक ने श्रद्धालुओं से बातचीत कर यह जानने का प्रयास किया कि उन्हें किन सुविधाओं में सुधार की आवश्यकता महसूस हो रही है। प्राप्त सुझावों और फीडबैक के आधार पर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश भी दिए गए। मंदिर प्रशासन का उद्देश्य श्रद्धालुओं को कम समय में सहज और सुविधाजनक दर्शन उपलब्ध कराना है।

निरीक्षण के दौरान विश्राम धाम के बेहतर उपयोग पर भी जोर दिया गया, ताकि कतार में प्रतीक्षा कर रहे श्रद्धालुओं को राहत मिल सके। प्रशासन का मानना है कि उपलब्ध सुविधाओं का प्रभावी उपयोग होने से दर्शन व्यवस्था और अधिक व्यवस्थित हो सकेगी।

भ्रमण के दौरान प्रशासक ने नंदी हॉल, गणेश मंडपम, अभिषेक स्थल, पालकी हॉल, एंबुलेंस एग्जिट गेट, मंदिर परिसर तथा बड़ा गणेश क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कतार व्यवस्था हर समय नियंत्रित और सुव्यवस्थित रहे तथा दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को अधिकतम सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

डीजल के लिए ट्रैक्टर लेकर पेट्रोल पंप तक जाना पड़ रहा किसानों को, जुताई हो रही प्रभावित

केन में डीजल नहीं मिलने से बढ़ी परेशानी - किसानों ने प्रशासन से व्यवस्था बनाने की मांग की

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। ईरान अमेरिका और इजरायल के बीच जारी युद्ध के चलते जिले में खरीफ सीजन की तैयारियों के बीच किसानों को डीजल की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि पेट्रोल पंपों पर केन में डीजल नहीं दिया जा रहा है और ट्रैक्टर लेकर आने पर ही डीजल मिल रहा है। इससे खेतों की जुताई का काम प्रभावित हो रहा है।

चिंतामण जवासिया के किसान अजय पटेल ने बताया कि मानसून शुरू होने वाला है और किसान खेतों में जुताई का काम तेजी से कर रहे हैं। ऐसे समय में ट्रैक्टर लेकर शहर स्थित पेट्रोल पंप तक आने-जाने में काफी समय और डीजल खर्च हो रहा है। गांवों से पेट्रोल पंप की दूरी 10 से 15 किलोमीटर तक है, जिससे आने-जाने में ही करीब 25 प्रतिशत डीजल खर्च हो जाता है। किसानों का कहना है कि 20 लीटर टैंक वाले ट्रैक्टर का डीजल दिनभर की जुताई के दौरान खत्म हो जाता है। इसके बाद दोबारा डीजल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप जाना पड़ता है, जिससे खेती का काम बाधित होता है। उनका आरोप है कि पेट्रोल पंप संचालक केन में डीजल देने से मना कर रहे हैं और वाहन लाने की शर्त रख रहे हैं। किसानों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देशित किया जाए कि किसानों के खसरा, बी-1 और आधार कार्ड जैसे दस्तावेज देखकर केन में भी डीजल उपलब्ध कराया जाए। उनका कहना है कि इससे समय और ईंधन दोनों की बचत होगी तथा खेती के कार्य सुचारू रूप से हो सकेंगे।

नौरंगा-मोगरा की फूल मंडी में आवक बढ़ी, लेकिन मांग सुस्त

अधिकमास में मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। दूधतलाई स्थित फूल मंडी इन दिनों नौरंगा और मोगरा की खुशबू से महक रही है। आसपास के गांवों और खेतों से इन फूलों की बंपर आवक हो रही है, जिससे मंडी में रौनक तो बढ़ी है, लेकिन व्यापारियों के चेहरे पर संतोष नहीं दिख रहा। वजह यह है कि आवक के मुकाबले मांग अपेक्षाकृत कम बनी हुई है।

फूल व्यवसायी अभिषेक दयाल के अनुसार वर्तमान में मंडी में नौरंगा और मोगरा की भरपूर आवक हो रही है। दूसरी ओर तेज गर्मी के कारण गेंदे और गुलाब के फूलों की आवक काफी घट गई है। मौसम का असर उत्पादन पर भी पड़ा है, जिससे इन फूलों की उपलब्धता सीमित बनी हुई है। व्यापारियों का कहना है कि अधिकमास के चलते शहर के मंदिरों में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है और धार्मिक गतिविधियां भी चल रही हैं, लेकिन इसके बावजूद फूलों की खपत में अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं हुई है। इससे कारोबारियों को बेहतर व्यापार की उम्मीद के अनुरूप लाभ नहीं मिल पा रहा है।

मंडी में फिलहाल आसपास के किसानों द्वारा ही अधिकांश फूलों की आपूर्ति की जा रही है। नौरंगा थोक बाजार में 30 से 40 रुपए प्रति किलो के भाव से बिक रहा है। कारोबारियों का मानना है कि यदि आगामी दिनों में मांग बढ़ती है तो फूल उत्पादकों और व्यापारियों दोनों को राहत मिल सकती है। फिलहाल आवक अधिक और मांग अपेक्षाकृत कम रहने से बाजार संतुलित स्थिति में बना हुआ है।

9 महीने बाद खुला बस रजिस्ट्रेशन घोटाले का पिटारा

नई बसों के रजिस्ट्रेशन निरस्त करने के आदेश, नियमों को दरकिनार कर हुए पंजीयन पर परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। प्रदेश के परिवहन विभाग ने बस पंजीयन में हुई बड़ी अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई करते हुए उज्जैन जिले की 192 बसों समेत मध्यप्रदेश की 2440 नई बसों के रजिस्ट्रेशन निरस्त करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस फैसले से बस संचालकों में हड़कंप मच गया है, वहीं परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में आ गई है।

परिवहन आयुक्त उमेश जोगा द्वारा जारी आदेश में प्रदेश के सभी संबंधित आरटीओ कार्यालयों को निर्देश दिए गए हैं कि नियमों का उल्लंघन कर पंजीकृत हुई बसों के रजिस्ट्रेशन 15 दिनों के भीतर निरस्त कर कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

जानकारी के अनुसार परिवहन आयुक्त कार्यालय को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कई जिलों के आरटीओ कार्यालयों में यात्री बसों के पंजीयन में निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया गया। जांच के दौरान वाहन पोर्टल के रिकॉर्ड खंगाले गए तो सामने आया कि बस बॉडी निर्माण और प्रमाणन से जुड़े नियमों की अनदेखी कर बड़ी संख्या में बसों का पंजीयन कर दिया गया।नियमों के अनुसार 1 सितंबर 2025 तक बस चैसिस पर तैयार की गई बॉडी के लिए बस बॉडी बिल्डर द्वारा फॉर्म-22बी के माध्यम से सेल्फ सर्टिफिकेशन की व्यवस्था थी। इसके बाद अप्रूवल सर्टिफिकेट को अनिवार्य कर दिया गया था। लेकिन जांच में पाया गया कि कई बसों का पंजीयन आवश्यक अनुमोदन के बिना ही कर दिया गया।सबसे ज्यादा गड़बड़ी इंदौर, नीमच, देवास, उज्जैन, आगर मालवा, भोपाल, झाबुआ और खरगोन जैसे जिलों के आरटीओ कार्यालयों में सामने आई है। उज्जैन में अकेले 192 बसें इस कार्रवाई की जद में आ गई हैं। उधर परिवहन विभाग के आदेश के बाद बस मालिकों ने भी मोर्चा खोल दिया है। मध्यप्रदेश बस ऑनर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने परिवहन मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर आदेश पर पुनर्विचार की मांग की है। बस संचालकों का कहना है कि यदि बसें नियमों के अनुरूप नहीं थीं तो पंजीयन के समय ही उन्हें रोका जाना चाहिए था। उन्होंने शासन द्वारा निर्धारित सभी शुल्क जमा किए और आरटीओ की अनुमति मिलने के बाद ही वाहन सड़कों पर उतारे। ऐसे में यदि कहीं कोई अनियमितता हुई है तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों या बस बॉडी बिल्डरों की है, न कि बस मालिकों की। एसोसिएशन का दावा है कि अचानक रजिस्ट्रेशन निरस्त होने से बस संचालकों को करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। इसके साथ ही प्रदेश के कई रूटों पर यात्री परिवहन व्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है। अब सभी की नजर सरकार के अगले फैसले पर टिकी है कि वह इस आदेश को बरकरार रखती है या बस संचालकों की मांग पर कोई राहत देती है।

पूरी कार्रवाई एक नजर में-

-उज्जैन में 192 बसें प्रभावित

-प्रदेशभर में 2440 बसों के रजिस्ट्रेशन निरस्त करने के आदेश

-उज्जैन जिले की 192 बसें सूची में शामिल

-15 दिन के भीतर कार्रवाई कर रिपोर्ट देने के निर्देश

-बस मालिकों ने आर्थिक नुकसान का हवाला देकर आदेश वापस लेने की मांग उठाई

-परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली पर भी उठ रहे सवाल

शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, खाचरौद में एक दिवसीय युवा संगम रोजगार मेला, स्वरोजगार एवं अप्रेंटिसशिप मेला का आयोजन आज किया जाएगा

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। मध्यप्रदेश शासन के युवा संगम कार्यक्रम के अंतर्गत जिला रोजगार कार्यालय, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र व शासकीय आई.टी.आई. संस्थान के तत्वावधान में 10 जून, बुधवार को प्रातः 11-00 बजे से दोपहर 03-00 बजे तक स्थान - शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ढ्ढञ्जढ्ढ), खाचरौद जिला उज्जैन में एक दिवसीय युवा संगम रोजगार मेला, स्वरोजगार एवं अप्रेंटिसशिप मेला का आयोजन किया जाएगा।

उक्त रोजगार मेले में कई प्रतिष्ठित कम्पनियां जैसे कटारिया ग्रुप उज्जैन, न्यूजील फैशन बेयर प्राइवेट लिमिटेड बदनावर, प्रतिभा स्वराज प्राइवेट लिमिटेड उज्जैन, बेस्ट लाइफस्टाइल अपैरल प्राइवेट लिमिटेड उज्जैन, वीजेए एग्रो बायोकेयर प्राइवेट लिमिटेड भोपाल, वीईसीबी पॉवरट्रेन पीथमपुर, कृषि दर्पण एग्रो प्राइवेट लिमिटेड उज्जैन, नॉक्स विंड लिमिटेड बडवानी, सीआईआई एमसीसी इंदौर (भारतीय उद्योग का विन्यास) इंदौर, स्वातंत्र माइक्रोफिन लिमिटेड, भारतीय जीवन बीमा निगम, खाचरौद आदि के लगभग 300 से अधिक विभिन्न पदों जैसे- सेल्स एग्जीक्यूटिव, टेक्नीशियन, ट्रेनर, सेल्स, टीम लिडर, बैंक ऑफिस, सुरक्षा गार्ड, ऑपरेटर, हेल्पर, ऑफिस बॉय आदि पदों के लिए आकर्षक वेतन पर रोजगार प्रदान करने के लिए कम्पनियों के प्रतिनिधि आवेदकों के साक्षात्कार लेकर प्रारम्भिक रूप से चयन करेंगे। महिला हेल्पर, ऑपरेटर के लिए विशेष भर्ती के अवसर हैं। उक्त मेले में 18 से 40 वर्ष के आवेदक जो कि 5वीं से स्नातकोत्तर किसी भी विषय में पास आवेदक एवं तकनीकी योग्यता के आवेदक भी उक्त पदों के लिए रोजगार मेले में भाग लेकर योग्यता अनुसार रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। रोजगार मेले में सम्मिलित होने वाले आवेदक अपनी समस्त शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण-पत्रों के साथ बायोडेटा की प्रतियां एवं अन्य प्रमाण-पत्र जैसे आधार कार्ड आदि के प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रतियां भी आवश्यक रूप से साथ लाएं।

केनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड निवेशकों को शिक्षित करने के लिए मध्य प्रदेश में 'निवेश बस यात्रा' लेकर आई

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। भारत के दूसरे सबसे पुराने म्यूचुअल फंड, केनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (केनरा रोबेको म्यूचुअल फंड के निवेश प्रबंधक), मध्य प्रदेश में म्यूचुअल फंड निवेश के बारे में जागरूकता पैदा करने और राज्य भर के निवेशकों को शिक्षित करने के लिए निवेश बस यात्रा शुरू करने के लिए तैयार है।

इस पहल का उद्देश्य राज्य के लोगों के बीच वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना और म्यूचुअल फंड निवेश के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह बस यात्रा इंदौर से शुरू होगी और इसके बाद उज?जैन, देवास, भोपाल, जबलपुर और ग?वालियर पहुंचेगी। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर लोगों को निवेश से जुड़ी जानकारी दी जाएगी।

केनरा रोबेको एएमसी के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी रजनीश नरूला ने कहा, आज के बदलते वित्तीय परिदृश्य में, ज्ञान उतना ही शक्तिशाली है जितना कि समझ। एक जानकार निवेशक न केवल अपने लिए बेहतर निर्णय लेता है बल्कि एक मजबूत वित्तीय इकोसिस्टम में भी योगदान देता है। हम निवेश के ज्ञान को सरल, सुलभ और व्यावहारिक बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। निवेश बस यात्रा का उद्देश्य वित्तीय शिक्षा को सीधे समुदायों तक पहुँचाना है। केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, असम, महाराष्ट्र, गोवा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू जैसे राज्यों में पहले ही पहुँचने के बाद, अब हम इसे मध्य प्रदेश ले जा रहे हैं ताकि कई शहरों में निवासियों के साथ जुड़ सकें, निवेश की अवधारणाओं को सरल बना सकें, आम मिथकों को दूर कर सकें और दीर्घकालिक वित्तीय योजना को बढ़ावा दे सकें।

निवेश बस यात्रा राज्य भर के प्रमुख स्थानों पर निवासियों के साथ जुड़ेगी, उन्हें निवेश के बारे में आसानी से समझ में आने वाली जानकारी प्रदान करेगी। इंटरैक्टिव सत्रों और डिजिटल संसाधनों के माध्यम से, इस पहल का उद्देश्य निवेश की अवधारणाओं को सरल बनाना और वित्तीय निर्णय लेने के लाभों को समझाना है।

केनरा रोबेको एएमसी के हेड- सेल्स एंड मार्केटिंग गौरव गोयल ने कहा, हम वित्तीय ज्ञान को व्यावहारिक और सुलभ बनाकर निवेशकों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह निवेश बस यात्रा ज़मीन पर हमारी प्रतिबद्धता का ही एक विस्तार है, जो सीधे समुदायों को जोड़ती है और निवेशकों से उनके अपने माहौल में मिलती है। सीधे जुड़कर, हमारा उद्देश्य व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करना, आम गलतफहमियों को दूर करना और निवेशकों के बीच दीर्घकालिक निवेश की सोच को बढ़ावा देना है।